भारत नेपाल संबंध
भविष्य की दशा–दिशा

राम सागर शुक्ल

भारत–नेपाल संबंध
भविष्य की दशा–दिशा

प्रकाशक
सनातन प्रकाशन
4/137 विकास खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ

प्रथम संस्करण
मूल्य ....
मुद्रक.............

त्यैणैनासं

'आवायो मण्डल निविष्ट'

चाणक्य

जो राष्ट्र पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों
पर दृष्टि नहीं रखता, उसे
हानि उठानी पड़ती है

विषय सूची

अध्याय — पृष्ठ संख्या

1. प्रस्तावना
2. साक्षात्कार
3. भारत–चीन के बीच
4. माओवादी एजेंडा
5. विवाद के बिन्दु
   अ. नदियां–वरदान या अभिशाप
   ब. भारत–नेपाल संधि
   स. मधेशी आंदोलन
   द. खुली सीमा
6. दो देश एक लोग
7. पशुपतिनाथ

प्रस्तावना

दिसम्बर 1999 में नेपाल के काठमाण्डू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट से भारतीय विमान का अपहरण कर लिया गया। इस घटना ने भारत–नेपाल संबंधों की जड़ को हिला दिया। अपहरण के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ था। विमान अपहरण की घटना के बाद समूचा नेपाल भारत की सुरक्षा के लिये अत्यन्त संवेदनशील हो गया।

नेपाल और भारत के बीच सीमा खुली होने से कोई भी आ जा सकता है। इस स्थिति का लाभ उठाकर पास्तिान समर्थित आतंकवादी और जाली नोटों के सौदागर भारत की नाक में दम किये हुये हैं। विमान अपहरण की घटना के बाद नेपाल नरेश वीरेन्द्र तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या से भो भारत–नेपाल संबंधों में एक नया आयाम जुड़ गया। यह नरसंहार किसने करवाया, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। परन्तु नरेश वीरेन्द्र की हत्या से तात्कालिक लाभ तो ज्ञानेन्द्र को ही हुआ। वे नेपाल नरेश बन गये। बाद में इस स्थिति का पूरा लाभ माओवादियों को मिला। माओवादी राजशाही की समाप्ति के लिये संघर्ष कर रहे थे। नरेश वीरेन्द्र की हत्या से नेपाल में राजशाही कमजोर हो गयी। इस स्थिति का लाभ लेते हुये माओवादियों ने राजतंत्र को समाप्त करने के लिये अपना आंदोलन और तेज कर दिया।

नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने सत्ता संभालने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये हरसंभव उपाय किया। उन्होंने अपनी पसन्द के व्यक्तियों, पहले लोकेन्द्र बहादुर चन्द तथा बाद में सूर्य बहादुर थापा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये दोनों ही व्यक्ति राजा समर्थक माने जाते हैं। ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। नरेश ज्ञानेन्द्र उम्मीद कर रहे थे कि वे माओवादियों को नियंत्रित कर लेगें। परन्तु स्थिति और खराब होने लगी। नेपाल में माओवादी हिंसा बढ़ती गयी। स्थिति ऐसी बनी कि माओवादी ही नहीं अपितु अन्य सात प्रमुख राजनीतिक दल भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिय खुलकर सामने आ गये। अब माओवादियों समेत सभी राजनीतिक दलों का एक ही लक्ष्य थ राजशाही का खात्मा और प्रजातंत्र की स्थापना।

नेपाल के हालात के लिये नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र स्वयं जिम्मेदार थे। एक फरवरी, 2005 को उन्होंने विधिवत चुनी हुई प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार को अचानक बर्खास्त करके संसद को भंग करके जो गलती की थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। नेपाल के संविधान में नरेश को ऐसा करने को अधिकार प्राप्त था, परन्तु इसके लिये समुचित कारण होना चाहिए। देउबा सरकार को बर्खास्त करते समय नेपाल नरेश ने कहा था कि वे यह कदम माओवादी समस्या को सुलझाने के लिये उठा रहे हैं क्योंकि देउबा सरकार इस दिशा में असफल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे जल्दो चुनाव भी करायेंगे। परन्तु तेरह महीने बीत जाने के बाद का समाधान तो दूर माओवादी और शक्तिशालो हो गये, हिंसक घटनायें बढ़ गयी। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दलों ने बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक था।

माओवादी प्रारम्भ से ही राजशाही के खिलाफ थे। वे प्रारम्भ से देश में संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त करने और संविधान सभा के गठन की मांग करते

रहे हैं। वे देश में चीन के पैटर्न वाला एक दलीय लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। अन्य राजनीतिक दल संवैधनिक राजतंत्र के खिलाफ कभी नहीं रहे, वे बहुदलीय प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। संविधान सभा के गठन के बारे में भी वे इतने गंभीर नहीं थे परन्तु नरेश ज्ञानेन्द्र द्वारा सत्ता हथियाने के बाद वे भी माओवादियों के सुर में सुर मिलाने लगे।

मार्च, 2006 में सात राजनीतिक दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच विधिवत एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि वे मिलकर राजशाही को समाप्त करने के लिये आर–पार की लड़ाई छेड़ंगे। इसी समझौते के अंतर्गत पांच अप्रैल 2006 से पूरे नेपाल में जोरदार प्रदर्शन और धरनों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। इसे दबाने के लिये सरकार ने कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। आंदोलनकारियों को तितर–बितर करने के लिये सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर गोलियां चलायीं और लाठियां भांजी, जिससे कम से कम पन्द्रह लोगों की मौतहो गयी और सैकड़ों लोगों घायल हो गये।

नेपाल की भयानक स्थिति को देखते हुये भारत ने कश्मीर के भूतपूर्व सदर–ए–रियासत डॉ.कर्ण सिंह को प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में काठमांडु भेजा। कर्ण सिंह ने नेपाल नरेश को इस बात के लिये राजी कर लिया कि वे देश में प्रजातंत्र फिर से बहाल कर देंगे। इसके लिये नेपाल नरेश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी काफी था। डॉ. कर्ण सिंह के भारत वापस आने के तुरन्त बाद 21 अप्रैल को नेपाल नरेश ने राज्य के समस्त कार्यकारी अधिकार जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को सौंपने की घोषणा कर दी।

नेपाल नरेश ने यह घोषणा करके एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ तो उन्होंने भारत तथा अंतरराष्ट्रीय जगत को यह संदेश दिया कि वे नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध हैं, साथ ही अपनी इस घोषणा से उन्होंने सात राजनीतिक दलों के बीच आपस में तथा उनके गठबंधन और माओवादियों के बीच फूट डालने की कोशिश की।

नरेश ज्ञानेन्द्र ने जब देउबा सरकार को बर्खास्त किया था तो वे समझ रहे थे कि चूंकि राजनीतिक दलों ने अपना जनाधार खो दिया है इसलिये उनका विरोध नहीं होगा। हुआ भी ऐसा ही। परन्तु उन्हें यह पता नहीं था कि अगर सत्ता अधिक दिनों तक उनके हाथ में रही तोराजनीतिक दल और माओवादी एक साथ हो सकते हैं। नेपाल नरेश को शायद यह भी भ्रम था कि एशिया कई देशों में तानाशाही बड़े शान से चल चल रही है। नेपाल नरेश शायद यह भी सोचते होंगे कि वे सेना की मदद से आंदोलनकारियों को दबा सकते हैं, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

नेपाल के सबंध में भारत की विदेश नीति स्पष्ट नहीं रही है। उसके कई कारण है। मुख्य रूप से भारत यह लांछन नहीं लेना चाहता कि वह नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। परन्तु भौगोलिक कारणों से भारत की यह मजबूरी है कि वह नेपाल में हो रही घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकता। नेपाल नरेश की घोषणा से नेपाल में यह सुनाई देना लगा है कि भारत की दखलंदाजी के कारण ही नेपाल नरेश ने ऐसी घोषणा की है। नेपाल में ऐसा कहने वाले लोगों की कमी नहीं कि भारत नही चाहता कि नेपाल में पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित हो।

राजनीतिक दलों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक बार पुनः वयोवृद्ध नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला सभी राजनीतिक दलों की सहमति से प्रधानमंत्री बनाये गये। माओवादियों ने भी सरकार में शामिल होने के लिये रजामंदी जताई।

प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद 10 जून 2006 में कोइराला ने भारत की सरकारी यात्रा की। स्वदेश लौटने पर नरेश ज्ञानेन्द्र के शेष बचे अधिकार भी छीन लिये गये। वे नाममात्र के राजा रह गये। कोइराला की भारत यात्रा से माओवादियों के मन में संदेह पैदा था कि वे भारत के दबाव में ज्ञानेन्द्र के प्रति नरम रूख अपनायेंगे। शायद इसीलिये भारत से वापस आते ही कोइराला ने नेपाल नरेश की रही सही ताकत भी छीन ली।

भारत यात्रा के बाद नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के स्वदेश लौटते ही नेपाली संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की पुष्टि करने का अधिकार नेपाल नरेश से छीनकार प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को दे दिया गया। नेपाल नरेश को अब किसी विधेयक को नामंजूर करने का अधिकार नहीं रह गया। नेपाल नरेश अब मंत्रियों, सांसदों एवं विशिष्ट अधिकारियों को शपथ दिलाने के अधिकार से भी वंचित कर दिये गये। यह कार्य अब संसद द्वारा नामित 15 सदस्यों की विशेष समिति करेगी। नये कानून के मुताबिक सरकार को सभी कार्यकारी शक्तियां मंत्रि परिषद के पास होगीं जबकि विधायी शक्तियां प्रतिनिधि सभा के अधीन होगी।

नेपाली संसद द्वारा पारित इस प्रस्ताव का बड़ा महत्व है। भारत यात्रा से लौटने के तुरंत बाद नेपाली संसद द्वारा पारित इस प्रस्ताव का एक निहितार्थ यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोइराला माओवादियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत चाहे जितना ही राजशाही बनाये रखने के पक्ष में मत व्यक्त करता रहे कोइराला सरकार माओवादियों के साथ हुये समझौते का उल्लंघन नहीं करेगी। नेपाली प्रधानमंत्री कोइराला की भारत यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इस बात का तो कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ऐसा समझा जाता है कि भारत यह चाहता था कि नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र मजबूत हो साथ ही नेपाल नरेश भी संवैधानिक प्रमुख के रूप में बने रहे। नेपाल में वैसे तो सात दलों के गठबंधन का शासन था, परन्तु परोक्ष रूप से माओवादियों का एजेण्डा ही लागू हो रहा था। नेपाली संसद ने अधिवेशन प्रारम्भ होते ही सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इस प्रस्ताव के अनुसार नेपाल अब हिन्दू राष्ट्र नहीं रहा। उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नेपाली जनता में नब्बे प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। नाममात्र के लोग बौद्ध मतावलम्बी हैं। मुसलमानों की भी संख्या बहुत अधिक नहीं हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि पिछली जनगणना के उपरांत नेपाल में मुसलमानों की जनसंख्या दो प्रतिशत बढ़कर बारह प्रतिशत हो गयी है। दुनिया के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देने से बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ।

नेपाल में नरेश को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक अब सेना के सवांच्च कमाण्डर की भी उपाधि उनसे छीन ली गयी। प्रस्ताव के मुताबिक नरेश की प्रधान सलाहकार संस्था राज परिषद को भंग कर दिया गया। शाही नेपाली सेना का नाम बदलकर नेपाली सेना कर दिया गया। सेनाध्यक्ष की नियुक्ति नेपाल नरेश द्वारा नहीं बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा

की जायेगी। संसद ही अब नेपाल नरेश के खर्चे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। नेपाल नरेश के पास वास्तव में अब कोई अधिकार नहीं रह गया। यह सब माओवादियों के दबाव के कारण हुआ।

इस बीच माओवादी नेता जो अभी तक भारत में छिपकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अब प्रकट हो गये। वे भारत तथा अन्य देशों के नेताओं से खुलकर मिलने लगे।

इस बीच नेपाल में सात दलों की संयुक्त सरकार ने जिसके नेता कोइराला थे नये संविधान के निर्माण के लिये अंतरिम सरकार के गठन और संविधान सभा के चुनाव के लिये पहल शुरू कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल होने और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हथियार डालने के लिये सहमत हो गये। इस बीच प्रचण्ड ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के बाद भारत ने भी माओवादियों के प्रति नरमी अख्तियार की। उन्हें आतंकी संगठनों की सूची से अलग कर दिया।

माओवादी सरकार में शामिल हो गये। इससे पहले कि संविधान सभा का चुनाव हो, वे सरकार से अलग भी हो गये। उनका कहना था कि चुनाव के पहले राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की जानी चाहिये। हालांकि पहले माओवादी सहमत हो गये थे कि राजतंत्र के बारे में फैसला चुनी हुई संविधान सभा करेगी, परन्तु उन्होंने पैतरा बदलकर जन मानस पर अपना प्रभाव बनाये रखने के लिये चुनाव के पहले ही नेपाल नरेश को पदच्युत कर गणतंत्र की घोषणा पर अड़ गये। अंततः उनकी यह मांग भी स्वीकार कर ली गयी। इस बीच मधेशी समुदाय के लोगों का लगा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है अतः विभिन्न मधेशी संगठनों ने एक मोर्चा बनाकर 12 फरवरी से 28 फरवरी 2008 तक आंदोलन चलाया, जिसमें कई लोगों की जानें गयीं। अंततः सरकार ने मधेशियों की मांग स्वीकार कर ली और वे भी संविधान सभा के चुनाव में भाग लने के लिये सहमत हो गये।

नेपाल में 10 अप्रैल 2008 को संविधान सभा के चुनाव कराये गये। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। माओवादी इस गलतफहमी में थे कि उन्हें बहुमत अवश्य मिलेगा।

601 सीटों वाली संविधान सभा के 575 सीटों के लिये चुनाव हुये। शेष 26 सदस्यों को नामित किया जा सकेगा। संविधान सभा के चुनाव दो तरह से हुये। 240 सीटों के लिये सीधे चुनाव हुये, जिनमें माओवादियों को 120, नेपाली कांग्रेस को 37, ए–माले को 35, मधेशी जनाधिकार फोरम मो 30 सीटें मिली। अन्य सीटों पर छोटे–मोटे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार विजयी हुये। इसके अलावा 335 सीटों के लिये अप्रत्यक्ष समानुपात पद्धति से मतदान कराया गया। इनमें कुल एक करोड़ 74 हजार मतों में से माओवादियों को 29.14 प्रतिशत और एमाले को 20. 33 प्रतिशत मत मिले। इस प्रकार दोनों पद्धतियां से हुये चुनावों को मिलाकर माओवादियों को 218, नेपाली कांग्रेस को 108, एमाले को 101 और मधेशी जनाधिकारी फोरम को 51 सीटें मिली। शेष 97 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार विजयी हुये। चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि माओवादी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आये हैं परन्तु उन्हें बहुमत अब भी नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि लगभग दो तिहाई मतदाताओं ने माओवादियों को अस्वीकार कर

दिया। फिर भी माओवादी चुनाव परिणामों से इतने उत्साहित थे कि उनके सर्वोच्च नेता पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचण्ड ने यहां तक घोषणा कर दी कि वे नेपाल के अगले राष्ट्रपति होंगे, जबकि अंतरिम संविधान में राष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है।

अंततः प्रचण्ड प्रधानमंत्री बन गये। वे 14–18 सितम्बर 2008 तक भारत की सरकारी यात्रा पर थे। उनके साथ विदेश मंत्री उपेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री राजेन्द्र महतो तथा अन्य अधिकारी भी थे। प्रचण्ड ने अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, विपक्ष के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अन्य लोगों से भी मुलाकात की। भारत–नेपाल मैत्री मंच की ओर से शरद यादव द्वारा उनके निवास स्थान पर दिये गये भोज में प्रचंड ने देश के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की।

नेपाली प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद भारत ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिये 20 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत न चीनी, मक्का, गेहूं और चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लेने का आश्वासन दिया। इससे नेपाल की आम जनता को लाभ मिलेगा। भारत ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगले तीन महीने तक नेपाल को 150 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया करायी जायेगी। भारत द्वारा दिये गये इन आश्वासनों को ही प्रचण्ड की भारत यात्रा की उपलब्धि माना जा सकता है। प्रचण्ड के साथ भारतीय नेताओं की बातचीत, लिये गये अन्य निर्णय केवल खानापूर्ति के लिये थे।

नेपाल की नवनिर्वाचित संविधान सभा ने अंततः 28 मई 2008 को देर रात काठमांडू के वीरेन्द्र इंटरनेशनल कन्वेशन सेंटर में हुई अपनी पहली बैठक में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही दुनिया के एकमात्र हिन्दूराज का भी अवसान हो गया। राजशाही को समाप्त करने के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 560 मत पड़े जबकि विपक्ष में केवल चार मत पड़े। संविधान सभा ने नारायण हिती राजमहल को एक संग्रहालय में बदल दिया। नेपाल में श्री पांच को सरकार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह, जो विष्णु के अवतार माने जाते थे, अब एक सामान्य नागरिक हो गये। नेपाल अब एक संघीय, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो गया है। इसका राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका के सभी अधिकार होंगे।

240 साल पहले वर्तमान नेपाल कई–कई छोटे–छोटे राज्यों में बंटा था। सन 1768 में राजस्थान के किसी राजघराने के पृथ्वी नारायण शाह ने घाटी में स्थित काठमांडू भक्तपुर और पाटन राज्यों को जीतकर तथा पूर्वी और पश्चिमी नेपाल को जोड़कर वर्तमान नेपाल की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी नारायण शाह को स्वयं भगवती दुर्गा ने एक तलवार भेंट की थी, जिसके सहारे उन्होंने अपना विजय अभियान शुरू किया और लगातार जीतते गये। यहां तक की उन्होंने 600 वर्ष पुराने मल्ल शासकों को भी हरा दिया।

पृथ्वी नारायण शाह के बाद 1775 से 1777 तक प्रताप सिंह शाह, 1777 से 1799 तक राणा बहादुर शाह, 1799 से 1816 तक गिरवाना विक्रम शाह, 1816 से 1847 तक राजेन्द्र विक्रम शाह, 1847 से 1881 तक सुरेन्द्र विक्रम शाह, 1881 से

1911 तक पृथ्वी विक्रम शाह, 1911 से 1955 तक त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, 1955 से 1972 तक महेन्द्र विक्रम शाह, 1972 से 2001 वीरेन्द्र विक्रम शाह, एक जून 2001 से चार जून 2001 तक दीपेन्द्र वीर विक्रम शाह, और चार जून 2001 से 28.05.2008 तक ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपाल की गद्दी पर रहे।

नरेश ज्ञानेन्द्र शाह वंश की 11वीं पीढ़ी और इस वंश के 13वें और अंतिम शासक बन गये थे। नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिये शुरू संघर्ष के दौरान अक्सर यह लोककथा सुनाई जाती थी कि गुरू गोरखनाथ ने शाह वंश को आशीर्वाद दिया था कि शाह वंश 11वीं पीढ़ी के बाद समाप्त हो जायेगा। नरेश ज्ञानेन्द्र 11वीं पीढ़ी के ही हैं, परन्तु वास्तव में उनके बड़े भाई वीरेन्द्र को जो 11वीं पीढ़ी के थे, अंतिम शासक माना जाना चाहिये। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र दीपेन्द्र को केवल चार दिनों के लिये राजा बनाया गया था और उस समय वे अगर मृत नहीं थे तो कोमा में थे। उस समय नरेश ज्ञानेन्द्र को प्रोटेम राजा घोषित किया गया था और दीपेन्द्र की मृत्यु की औपचारिक घोषणा के बाद ज्ञानेन्द्र ने सत्ता संभाली। ज्ञानेन्द्र इससे पहले भी 1950 में लगभग तीन महीने के लिये राजा घोषित किये गये थे जब उनकी उम्र मात्र ढाई वर्ष थी।

शाह वंश के 240 वर्षो के इतिहास में कई उतार–चढ़ाव आये। 1846 में राणा जंग बहादुर प्रधानमंत्री बने और इसके साथ ही अगले 104 वर्षो तक वास्तव में नेपाल में राणाओं का शासन रहा। राणा जंग बहादुर ने नेपाल के लिये कानून–मुल्की ऐन की घोषणा की जो पूरी तरह जाति व्यवस्था पर आधारित था। इसमें ब्राहम्ण को विशेष दर्जा प्राप्त था और छोटी जातियों को गुलाम के रूप में व्यवहार किया जाता था। नेपाल में अभी लगभग 14 वर्षो पहले ही कमाईया पथा समाप्त की गयी जो राणा शासन के जमाने की दास प्रथा थी।

राणा शासन के दौरान राजवंश के लोगों को पढ़ने–लिखने की आजादी नहीं थी। वे नाम के राजा थे। 1950 में अचानक नेपाल नरेश त्रिभुवन ने सपरिवार राणाओं से बचकर भारत में शरण ले ली। इसके बाद राणा प्रधानमंत्री ने बालक ज्ञानेन्द्र को जो राज परिवार के एकमात्र सदस्य नेपाल में बच गये थे को राजा घोषित कर दिया। भारत तथा अन्य देशों ने इसको मान्यता नहीं दी। भारत के प्रयास से लगभग तीन महीने बाद जनवरी 1951 में नरेश त्रिभुवन को पूरे अधिकार के साथ नपाल के राजपद पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया और इसके साथ ही राणाओं का शासन समाप्त हो गया।

नेपाल में सरकार द्वारा नारायणहिति राजमहल के साथ सात और महलों के राष्ट्रीयकरण के बाद ज्ञानेन्द्र महल छोड़कर चले गये। वे अपने परिवार के साथ काठमाण्डू के उपनगरीय इलाक में एक अन्य स्थान पर रहते हैं। नारायणहिति राजमहल एक ऐतिहासिक महल है। इसी महल में लगभग छः वर्ष पहले तत्कालीन नेपाल नरेश वीरेन्द्र और उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी। नारायणहिति ह ीवह महल है जिसमें नेपाल के राणा प्रधानमंत्रियों न लगभग 100 वर्ष तक राजा को एक कैदी की तरह रखा। राणाओं के प्रधानमंत्री रहने के दौरान राजा तो होते थे परन्तु उनकी कुछ चलती नहीं थी। यहां तक उन्हें पढ़ने–लिखने तक की आजादी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ने के इच्छुक राज परिवार के सदस्य बाथरूम में चोरी से पढ़ते थे।

नारायणहिति राजमहल के साथ और कई किंवदन्तियां जुड़ी हुई है। यह हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। राजशाही के दौरान इसकी सुरक्षाके लिये लगभग 5000 सेना के जवान वहां बराबर तैनात रहते थे। नेपाल क राष्ट्रगान को बदल दिया गया है। पहले वाले राष्ट्रगान में नेपाल नरेश की स्तुति होती थी। अब नेपाल नरेश के किसी स्थान पर पहुंचने पर उन्हें सलामी नहीं दी जाती है।

संविधान सभा की पहली बैठक के पहले ही काठमांडू घाटी में कई विस्फोट हुये। इसकी जिम्मेदारी रणवीर सेना के लोगों ने ली। भारत में रणवीर सेना और माओदियों की शत्रुता जगजाहिर है। नेपाल और भारत के हिन्दू संगठन राजशाही को समाप्त करने से खुश नहीं हैं। संविधान सभा के चुनाव के बाद माओवादी नेता प्रचंड का रूख भी बदल गया। अभी तक वे घोर भारत विरोधी थे, परन्तु अब वे भारत के माओवादियों को हथियार छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। भारत के नेताओं से भी उनका मेलजोल बढ़ रहा है। वे इस बात को समझने लगे हैं कि भारत के सहयोग के बिना नेपाल की आर्थिक उन्नति का रास्ता सहज नहीं होगा।

नेपाल में हिन्दी भाषी को लेकर शुरू हुआ विाद गहराता जा रहा है। अन्तरिम सरकार में निर्वाचित उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ने हिन्दी में शपथ क्या लिया, माओवादियों ने नेपाल सिर पर उठा लिया। यहां तक कि यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि हिन्दी में ली गयी शपथ गैर संवैधानिक है।

मधेशी नेता और नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ने आखिर वही किया, जिसकी उम्मीद थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और फिर से नेपाली में शपथ लेने से इंकार कर दिया। वे स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके है। फिलहाल उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यालय छोड़ दिया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री माधव कुमार ने गत दो दिसम्बर 2009 को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल सद्भावना पार्टी के मंत्री लक्ष्मण लाल करना ने हिन्दी में शपथ लेकर इस विवाद को फिर से उजागर कर दिया। उधर, प्रचण्ड की माओवादी पार्टी के कार्यकर्ता हिन्दी में शपथ लेने के कारण उपराष्ट्रपति परमानन्द झा के खिलाफ अब भी लामबंद है।

नेपाल की आबादी लगभग ढाई करोड़ है। इसमें लगभग एक करोड़ भारत में रहकर नौकरी चाकरी करते है। अतः इनके हिन्दी ज्ञान के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले लगभग एक करोड़ लोग पूरी तरह हिन्दी जानते हैं। शेष बचे 40–50 लाख लोग ही ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं बोल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति मे हिन्दी का अपमान करना नेपाल के लिये बहुत मंहगा पड़ सकता है।

नेपाल को यह भूलना नहीं चाहिये कि भाषा का विवाद बहुत संवेदनशली मामला है। भाषा के कारण ही पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया। बांगलादेश और पाकिस्तान के रहने वाले दोनों ही मुसलमान है। परन्तु बांगलादेशा की भाषा का पाकिस्तान में आदर नहीं होने के कारण धार्मिक समानता के बावजूद बांगलादेश के मुसलमान अलग हो गये और उन्होंने एक नये देश का निर्माण कर लिया।

श्रीलंका में भी यही हो रहा है। वहां भी मूल मुददा शिंघली और तमिल भाषियों का है।

फिलहाल श्रीलंका सरकार ने तमिल भाषियों को सेना के बल पर कुचल दिया है। परन्तु यह समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। इसी तरह दुनिया के और कई हिस्सों में उदाहरण है जहां भाषाई समूह को उपेक्षित रखने के कारण बड़ी समस्या पैदा हो गयी।

यह मजेदार बात है कि नेपाल में भोजपुरी, मैथिली और पहाड़ पर बोली जाने वाली बोलिया नेपाल की राष्ट्रीय भाषा की सूची में है। परन्तु न जाने हिन्दी से उन्हें क्या चिढ़ है कि वे इसका बराबर विरोध करते रहे है।

तराई क्षेत्र के दबे–कुचले लोग हिन्दी भाषी अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं। इसलिये भविष्य में उन्हें दबाया नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति परमानन्द झा तराई क्षेत्र के रहने वाले हैं, वे भी मधेशी हैं, वे उपराष्ट्रपति का पद छोड़ सकते हैं, परन्तु मधेशियों का समर्थन पाने के लिये वे हिन्दी को कभी नहीं छोड़ सकते। राजशाही जाने के बाद हिन्दी बोलने वाले एकजुट होंगे। हालांकि स्थिति अभी वसी नहीं है। मधशियों की लगभग 14 पार्टियां हैं वे आपस में बंटे हुये हैं। परन्तु भविष्य में अगर भाषा और संस्कृति के नाम पर वे एक होजाय तो नेपाल की राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। अतः माओवादी नेता प्रचण्ड और अन्य वर्गो को जो हिन्दी को हिकरात की नजर से देखते हैं इतिहास से सबक लेना चाहिये और उन्हें हिन्दी का विरोध छोड़ देना चाहिए। हिन्दी का विरोध नेपाल के हित में नहीं है।

नेपाल में माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचण्ड ने मई 2009 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने त्यागपत्र इसलिय दिया, क्योंकि सेना प्रमुख रूकमांगद कटवाल को बर्खास्त करने की उनकी सिफारिश को राष्ट्रपति ने नहीं माना था। कटवाल जुलाई, 2009 में सेवानिवृत्त हो गये। वास्तव में प्रचण्ड अपने त्यागपत्र से एक तीरसे दो निशाने साधना चाहते थे। परन्तु प्रचण्ड को यह नहीं भूलना चाहिये कि वे गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे। सेना प्रमख को बर्खास्त करने का निर्णय केवल उनकी पार्टी के मंत्रियों की बैठक में लिया गया। इससे पहले गठबंधन के अन्य दलों जैसे एमाले और मधेशी फ्रंट ने पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ऐसी परिस्थिति में अल्पमत वाली सरकार के निर्णय को यदि राष्ट्रपति ने मानने से इंकार कर दिया तो इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नेपाल में माओवादी समर्थक राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन तक कर रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी प्रजातांत्रिक देश में होता हो। राष्ट्रपति एक संवैधानिक सत्ता है और उसके निर्णय के खिलाफ उंगली नहों उठायी जानी चाहिये। परन्तु वामपंथियों की आचार संहिता में ऐसी कोई बात नहीं होती है। तुर्रा तो यह है कि सेना प्रमुख के मामले में प्रचण्ड भारत पर दोष मढ रहे हैं कि उनका यह कहना कितना बचकाना है कि भारत में लोकसभा चुनाव के चलते नेपाल के मामले में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। सच्चाई यह है कि कटवाल को पद से नहीं हटाने की सिफारिश न केवल भारत ने की बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी की थी। इतना ही नहीं नेपाल की विपक्षी पार्टियां भी कटवाल

को इस समय बर्खास्त करने के खिलाफ थी। ऐसी परिस्थिति में केवल भारत पर दोष मढ़ना प्रचण्ड की अपरिपक्वता दर्शाता है।

दरअसल प्रचण्ड का एक सूत्री उद्देश्य है यह है नेपाल में माओवादी एजेण्डा लागू करना। प्रचण्ड चाहते हैं कि राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान सभा का अध्यक्ष और सेना प्रमुख माओवादी विचारधारा का हो। प्रचण्ड को स्वतंत्र न्यायपालिका भी पसन्द नहीं है। प्रचण्ड को न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं की गरिमा को ध्यान में रखकर काम करना चाहिये। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि पिछले दिनों उकनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री कृष्ण बहादुर महरा ने खुलेआम न्यायपालिका को भला बुरा कहा और उसे चुनौती दी। यह शुभ लक्षण नहीं है। राष्ट्रपति से उनकी पटरी नहीं खाती है यह सर्वविदित है। राष्ट्रपति डॉ. रामबरन यादव दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रस के हैं। परन्तु सेना प्रमुख कटवाल के मामले को छोड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री प्रचण्ड के किसी फैसल को अस्वीकार नहीं किया। इसलिये राष्ट्रपति को दोष नहीं दिया जा सकता।

प्रचण्ड चीन के हिमायती हैं यह किसी से छुपा नहीं हैं। पिछले दिनों अफवाह थी कि वे अपनी चीन यात्रा के दौरान चीन से मैत्री की कोई संधि करना चाहते हैं। प्रचण्ड यह भी कहते हैं कि वे भारत और चीन क साथ बराबर का सम्बन्ध रखना चाहते हैं। परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत नेपाल के सम्बन्धों की तुलना नेपाल चीन सम्बन्धों से नहीं की जा सकती है। भारत और नेपाल के सम्बन्ध अद्वितीय हैं। दोनों देशों के बीच सैकड़ों मील खुली सीमा है। दोनों देश के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। एक आंकलन के अनुसार लगभग 20 लाख लोग प्रतिदिन भारत नेपाल सीमा से इधर उधर जाते हैं। लगभग एक करोड़ नेपाली भारत में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। प्रचण्ड की सरकार चाहे जो भी समझे भारत और नेपाल की जनता एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आखिर प्रचण्ड यह क्यों भूल जाते हैं कि लगभग 10 वर्षो तक भारत में ही छिपकर उन्होंने नेपाल में हथियारबंद आंदोलन चलाया। इसलिये भारत नेपाल के सम्बन्धों की तुलना नेपाल चीन से कभी नहीं की जा सकती है।

माओवादियों की जन सेना जो इन दिनों राष्ट्र संघ की देख–रेख में शिविरों मे आराम कर रही है, उसे प्रचण्ड सेना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। माओवादी लड़ाकों का अगर सेना में शामिल नही किया जा सकता है तो उन्हें पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में संगठित किया जा सकता है। इससे इस समस्या का समाधान निकल सकता है। परन्तु ये सारी बातें प्रचण्ड पर निर्भर करती हैं। प्रचण्ड को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उन्हें भारत को दोष देने के बजाये नेपाल को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिये काम करना चाहिये। उनकी प्राथमिकता साम्यवादी एजेण्डा लागू करना नहीं अपितु नेपाल का विकास होना चाहिये। नेपाल के विकास में भारत जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद कोई और नहीं कर सकता हैं।

चीन को नेपाल के विकास से कोई मतलब नहीं। वह तो भारत को परेशान करने के लिये नेपाल में अपनी उपस्थिति बनाये रखना चाहता है। परन्तु यह तथ्य नेपाली नेताओं को समझना चाहिये। दक्षिण एशिया में चीन का यह प्रयास है कि

भारत को चारों ओर से घेरा जाये। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दे रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी चीन की गतिविधियां संदेहजनक है। परन्तु नेपाली नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिये कि नेपाल का हित भारत के साथ रहने में है या चीन के साथ।

नेपाली संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की जो स्थिति है उसके हिसाब से कोई दल अकेले सरकार नहीं चला सकता है। नयी सरकार के गठन में मधेशी फ्रंट की भूमिका महत्वपूर्ण है। 112 सीट लेकर दूसरे नम्बर पर रहने वाली नेपाली कांग्रेस का, 108 सीट वाली ऐमाले के साथ सहयोग नेपाल के हित में है। परन्तु नयी माधव कुमार नेपाल सरकार तभी सफल होगी जब 83 सदस्यों वाली मधेशी पाटियां भी उन्हें समर्थन दें। इसलिये प्रयास होना चाहिये कि माओवादियों को भी सरकार में शामिल किया जाय। जो भी हो भारत और नेपाल दोनों के हित में है कि आपसी विश्वास और सद्भावना को बनाये रखा जाय। प्रचण्ड का त्यागपत्र एक सोची समझी रणनीति के तहत है। दो वर्षो तक प्रधानमंत्री रहने के बाद प्रचण्ड की अपनी पार्टी में ही लोकप्रियत घट रही है। उन्होंने त्यागपत्र देकर अपना लड़ाकू चेहरा बनाये रखने का कोशिश की है। परन्तु समय की मांग है कि प्रचण्ड को साथ लेकर नेपाल में शांति प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाय।

नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री माधव कुमार पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आये थे। उन्होंने यहां के नेताओं से बातचीत की। इस बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वही पुरानी बातें कि 1950 की भारत नेपाल की संधि समाप्त होनी चाहिये। इसके लिये फिर से कार्यदल संगठित करने की सहमति व्यक्त की गयी है। नेपाल के पास जल विद्युत का अपार भंडार है परन्तु इसके उपयोग के लिये दोनों देशों के बीच हुई महाकाली संधि कब लागू होगी, निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। हर वर्ष बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हजारों हेक्टेअर जमीन नेपाल से पानी आने के कारण डूब जाती हैं। इसे रोकने के लिये दोनों देशों के बीच भाषण के अलावा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आते है। इसके लिये भी कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। यह जरूर है कि इस बार माधव नेपाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि करने पर सहमति बन गयी है। इस संधि के बाद दोनों देश एक–दूसरे के यहां गिरफ्तार अपराधियों को विधिवत सौंप सकेंगे।

नेपाल और भारत का इतिहास नही नहीं, दोनों का भविष्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माओवादी नेता प्रचण्ड नेपाल को चीन का पिछलग्गू बनाने की जितनी भी कोशिश करें फिलहाल दोनों देशों को एक–दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किया जा सकता।

नेपाल और भारत के सम्बन्धों के बारे में दर्जनों पुस्तकें लिखीं जा चुकी हैं। ये पुस्तकें लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों और विशेषज्ञों ने लिखीं है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का कोई महत्व नहीं। भविष्य में भी पुस्तकें लिखीं जाती रहेंगी। जैसा कि नेपाल के एक सेवानिवृत्त राजनयिक ने मुझसे कहा ''भारत–नेपाल संबंधों के बारे में पुस्तकें लिखने का क्या फायदाघ असल बात यह है कि संबंधों

को प्रगाढ़ बनाने के लिये प्रयास होना चाहिये जो नहीं हो रहा है। '' उनकी बात का महत्व है। परन्तु इससे पुस्तकें लिखने का महत्व कम नहीं होता। अस्तु, इस बात पुस्तक का कोई महत्व है या नहीं यह तो पाठक ही तय करेंगे।

इस पुस्तक का उद्देश्य उन मुद्दों पर विचार करना है जिनसे भारत–नेपाल संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस उद्देश्य से मैंने नेपाली समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों से खुलकर बात की। विशेषकर उन लोगों से जो इस समय सत्ता में नही है। उन लोगों से जिन्होंने कभी महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुये दोनों देशों के बीच संबंधों के लिये मार्ग प्रशस्त किया है। उन लोगों से जो अपने जीवन के उस पड़ाव पर है। जहां आदमी निरपेक्ष भाव से चिन्तन करता है। मैं समझता हूँ िकइस पुस्तक का यह अंश सबसे महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त मीडिया में समय–समय पर प्रकाशित भारत–नेपाल संबंधों के बारे में लेखों आदि के आधार पर भी विचार इस पुस्तक में किया गया है। केवल उन्हीं लेखों की चर्चा की गयी है जिनका स्वर सकारात्मक और रचनात्मक है और केवल थोथी आलोचना नहीं।

नेपाल ही भारत का एक मात्र ऐसा पड़ोसी है जिससे हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ और निर्विवाद है।। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इन संबंधों को मानकर ;जंमद वित हतंदजमकद्ध चलना चाहिये। भारत–नेपाल सम्बन्धों पर भी सतत ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर जो कुछ घटनाएं हुई हैं वे इस बात का संकेत हैं कि दुनिया के बदलते हुये परिदृश्य में दोनों देशों को अपने संबंधों पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी। जरा भी असावधानी या अनदेखी करने से विकट समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नेपाल की माओवादी समस्या और पास्तिानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की बढ़ती हुई गतिविधियां दोनों देशों के लिये चिन्ता का विषय है।

लखनऊ 14 नवम्बर 2009

अध्याय–1
साक्षात्कार

नेपाल, भारत का सबसे नजदीक का पड़ोसी, मित्र देश। भारत और नेपाल न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक–दूसरे के अत्यन्त निकट हैं अपितु भावनात्मक दृष्टि से भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। फिर भी दोनों देशों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे दोनों अनभिज्ञ हैं। नेपाल में भारतीय पत्रकारों से बातचीत करने से आम तौर पर लोग कतराते हैं। औपचारिक इन्टरव्यू देने से तो और भी अधिक परहेज करते हैं। फिर भी मैने प्रयास किया कि कम से कम उन लोगों से बात की जाय जो मुझे जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और भारत–नेपाल सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील रहत हैं। नेपाल के राजनेता, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी और अन्य लोग भारत–नेपाल संबंध को किस प्रकार देखते हैं यह जानना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि जिनके विचार यहां दिये जा रहे हैं कि वे समग्र नेपाली समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों परन्तु, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा प्रयास था कि उनसे खुलकर बात की जाय और वैसा ही

हुआ। मेरा प्रयास उनसे यह जानने का था कि भारत–नेपाल सम्बन्धों में वे कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से सम्बन्धों पर असर पड़ता है। इस दृष्टि से उनके विचार काफी महत्वपर्ण हैं। इनसे भारत के आम लोगों को नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

श्री सूर्य बहादुर थापा

अस्सी वर्षीय श्री सूर्य बहादुर थापा नेपाल के एक प्रमुख राजनेता हैं। वे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। पूर्वी नेपाल के धनकुटा जिले के जागिरगांव के निवासी श्री थापा कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल के एक संभ्रांत और सम्पन्न परिवार में जन्में थापा की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी स्मरण शक्ति गजब की है। सार्वजनिक अवसरों पर उनसे मेरी जब भी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे पहचान लिया तथा स्नेह और सम्मान दिया।

भारत–नेपाल सम्बन्धों के बारे में जब मैने उनका विचार जानना चाहा तो पहले तो उन्होंने भी टाल–मटोल किया, परन्तु अंततः काफी का दूसरा प्याला पिलाने के बाद वे मेरा आग्रह टाल नहीं सके। फलस्वरूप उनके काठमांडू निवास से मुझे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। प्रस्तुत है उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अंश।

यह पूछे जाने पर कि भारत–नेपाल सम्बन्धों को वे किस तरह देखते हैं: उन्होंने तापाक से कहा "माफिया ग्रुप, आई.एस.आई., दाऊद ये लोग इंडिया–नेपाल संबंध को नुकसान पहुंचा रहे हैं।" दाऊद के बारे में कहूँ तो–नेपाल के कई टॉप लीडर्स या उनकी फेमिली के लोग उससे जुड़े हैं। भारत की एक पत्रिका में यह रिपोर्ट आयी थी। इस समस्या के समाधान के लिये अगर हम भारत के साथ मिलकर कुछ करेंगे तो नेपाल के सूडो राष्ट्रवादी हाय–हल्ला शुरू करेगें, कहेगें – भारत नेपाल में दखल दे रहा है। इसलिये यहां के पालिसी मेकर्स कुछ करने से हिचकिचाते हैं। इससे माफिया ग्रुप को लाभ मिल रहा था। अब यह हो गया है कि आतंकवाद का क्षेत्र बढ़ गया है। अब तो अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश भी इससे प्रभावित हो गये हैं। अतः अब नेपाल को डरना नहीं चाहिये कि वह भारत से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर कुछ अनुचित कर रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाकर हमें नेपाल में आई.एस.आई. और दाऊद आदि के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये। अब तक राष्ट्रवाद की बात करके कुछ लोग अड़चनें डालते थे, वह बात अब नहीं चलनी चाहिये। भारत एवं नेपाल इस मौके का लाभ लेकर कार्रवाई करें तो भारत की यह शिकायत दूर हो सकती है कि नेपाल भारत की सुरक्षा चिन्ता की अनदेखी कर रहा है। परन्तु अफसोस ! कि ऐसा नहीं हो रहा है।

"नेपाल के जल संसाधनों के बारे में काफी अर्से से दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहा है। हम लोग चुप बैठे रहे। महाकाली संधि हुई– इसी को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिये–परन्तु मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में भी दोनों देशें के बीच गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है। बैठकें होती जरूर है, पर शायद मात्र औपचारिकता के निर्वाह के लिये, और बिना कुद ठोस निर्णय लिये ही खत्म हो जाती हैं, गंभीरता से कोई बात नहीं हो रही है।"

" भारत–नेपाल संबंध जिस तरह से विकसित होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है, हम लोग अब भी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं, धर्म, संस्कृति, इतिहास को आधार बनाकर चलते थे। परन्तु वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है, जिस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। "

'' पूरी दुनिया में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तित माहौल में हम दोनों देशों के बीच सम्बन्ध कैसा हो– हम नहीं सोच रहे हैं। तेजी से बदलते हुये विश्व–परिदृश्य में वर्तमान समस्याओं के समाधान पर हम उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक तरीके से कहा जाय तो टाल रहे हैं। वर्ष 1950 की भारत–नेपाल संधि को ही देखिये। नेपाल में एक साइक्लॉजी बन गयी है कि इसको चेंज करना है– पर हम लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। हम क्या बदलना चाहते हैं? क्या कुछ करना है? क्या नहीं करना है? इस पर बात नहीं करते हैं, इस पर खुलकर बात होनी चाहिये। ''

'' कभी–कभी नेपाल में भारत विरोधी भावना भड़कने के तीन–चार कारण हैं , जिनमें सबसे बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद का होना। भारत एक प्रजातांत्रिक देश हैं, जबकि हमारे यहाँ दूसरी व्यवस्था है। हम लोगों ने पंचायत व्यवस्था शुरू किया। भारत के बुद्धिजीवियों ने इसका स्वागत नहीं किया– तो एक तो सैद्धान्तिक मतभेद दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो ही गया। दूसरा कारण नेपाल में कई राजनीतिक दल हैं जो प्रजातंत्र में कत्तई विश्वास नहीं रखते, फलतः उनका झुकाव भारत विरोधी हो जाता है। तीसरी बात उद्योग और व्यवसाय आदि में यहां जो भारतीय मूल के मारवाड़ी स्थापित हैं उनसे नेपाली व्यपारी कम्पीट नहीं कर पाते हैं और उन्हें भारतीय कहकर स्वयं ही भारत विरोधी बन जाते हैं। चौथी बात कुछ देश भारत के साथ कम्पटीशन के उद्देश्य से या स्वभावतः भारत विरोधी होने के कारण नेपाल की जनता, नेपाली समाज के विभिन्न वर्गो और कभी–कभी सरकार को भी बरगलाते रहते हैं। जैसे माफिया, आई.एस.आई., आतंकवाद आदि तीसरे देशों की ही देन है।''

'' दोनों देशों के बुद्धिजीवियों के बीच सम्पर्क काफी कम हो पाता है– यह भी एक कारण है। पहले भारत–नेपाल में आगे बढ़ने के लिये जो समझदारी बन रही थी, वह टूट गयी है। पहले उच्च शिक्षा के लिये नेपाल के विद्यार्थी भारत जाते थे, अब वे यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं। ये लोग उन देशों में व्याप्त भारत विरोधी विपरीत भावनाओं को नेपाल में इम्पोर्ट करते हैं और यह सतत प्रक्रिया काफी दृढ़ हो गयी है। भारत सरकार की नीति के कारण नेपाली लोगों को वहां के विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में मौका नहीं मिलता है। इससे दोनों देशों के बुद्धिजीवियों के बीच सम्पर्क कम हो रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि भारत में नेपालियों के लिये शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह खुला होना चाहिये। हालांकि आर्थिक कारणों से भी अब अधिकांश लोग नेपाल में ही पढ़ते हैं। मगर भारत में खुला रहता है ता लोग वहां जाते हैं और आधुनिक भारत से परिचित होते हैं। नेपाली मीडिया के क्षेत्र में भी जो भारत विरोधी बात होती हैं वह इसी वजह से है। भारत में शिक्षा में सुविधा होगी तो भारत में पढ़े–लिखे नेपाली लोग यहां भी मीडिया में आयेंगे और भारत के साथ सम्बन्ध मजबूत होगा।''

'' नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को जाग्रत करने के लिय एक नया माध्यम भी बन रहा है – हिन्दू धर्म पर आक्रमण हो रहा है, इसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसेपहले बड़े–बड़े स्वामी, महात्मा और आचार्य भारत से आते थे। यहां उनके प्रवचनों का सुप्रबन्ध होता था। कुछ स्वार्थपरायण लोग इसे भी रोकने

की सफल–असफल कोशिश कर रहे हैं। वह भी इसे भारत विरोधी अभियान का हिस्सा बनाकर। '

'' इन सब बातों के बावजूद भारत और नेपाल के सम्बन्धों का भविष्य उज्ज्वल है। उसके भी कई कारण है। सबसे बड़ा आर्थिक कारण है। जब हिन्दुस्तान का नेपाल को पूरा आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा आर जब तक दोनों देशों के बीच में पॉलीटिकल अण्डरस्टैन्डिग ठीक से नहीं होगी, नेपाल का आर्थिक विकास तेजी से नहीं होगा। अतः भारत से नेपाल का घनिष्ठ सहयोग होना चाहिये। और यह तभी सम्भव है जब यहां नेपाल मे प्रजातंत्र मजबूत हो। भारत को भी देखना चाहिये कि नेपाल में प्रजातंत्र मजबूत हो। नेपाल में प्रजातंत्रिक संस्थाएं जितनी मजबूत बनेगी उतना ही दोनों देशों का सम्बन्ध मजबूत होगा। ''

''देखिये, आम नेपाली भारत विरोधी नहीं। आम नेपाली तो भारत को बहुत सम्मान और स्नेह की भावना के साथ देखता है।। हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। और इतने निकट के संबंध हैं कि कोई नेपाली भारत के विरोध में सोच भी नहीं सकता है। हां काठमाडूं में जरूर कभी–कभी भारत विरोधी भावना देखने को मिल जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां एक वर्ग (उन्होंने एक जाति का नाम लिया जो लिखना उचित नहीं है) जो हमेशा से दरबार के नजदीक रहा है, प्रयास करता है कि यहां लोग भारत के खिलाफ सोचते रहे। शायद, वे ऐसा इसलिये करते हैं कि इसके जरिये वे अपने विरोधियों को काबू में रख सकें। किन्तु इन लोगों को इस बात का अहसास नहीं कि आम नेपाली उनके बहकावे में नहीं आने वाला है क्योंकि वह भारत को अपना सच्चा दोस्त समझता है।

***

श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई

'किशुन जी' अर्थात 84 वर्षीय श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइ हमेशा नेपाली कांग्रेस की राजनीति के केन्द्र में रहे हैं। वे कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका फक्कड़ और हॅसमुख स्वभाव, जो शायद उन्हें उनके बनारस में रहने के कारण मिला, उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व की गरिमा प्रदान करता है। वे अविवाहित हैं। उनसे पत्रकार वार्ताओं के अलावा अलग से मिलने का मौका तो नहीं मिला, परन्तु भारत–नेपाल सम्बन्धों की व्याख्या उनके विचारों के बिना अधूरी ही रहेगी। इसलिये दिनांक 11 जनवरी, 2002 को नयी दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में उनके द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंश यहां देने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। आशा है किशुन जी मुझे माफ करेंगे।

21वीं सदी में भारत–नेपाल सम्बन्धों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये उन्होंने कहा–मेरा जन्म बनारस में हुआ था और यहीं मैने अपने जीवन के रचनात्मक वर्ष व्यतीत किये। उन दिनों मेरे माता–पिता अपने राजनीतिक सिद्धांतों क कारण भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। मेरी शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई और यहीं मैने राजनीति का ककहरा भी सीखा। मुझे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय तक गिरफ्तार कर जेल में रखा था। मैं महात्मा गांधी जी से तीन बार मिला था। उन्होंने नपाल की समस्याओं के बारे में मेरे जैसे नौजवान की बातें बड़े धैर्य से सुनीं। जवाहर लाल नेहरू और जय प्रकाश नारायण से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था।

'' भारत और नेपाल ने इतिहास के दौर में बहुत उतार–चढ़ाव देखे हैं। नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना में भारत के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन तथा दुनिया के अन्य देशों के साथ विकसित हो रहे अपने सम्बन्धों के बावजूद नेपाल के सम्बन्ध भारत के साथ अत्यन्त ही मैत्रीपूर्ण रहे। 1990 में नेपाल में प्रजातंत्र की फिर से स्थापना के समय दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत खराब थे। उस समय मैं प्रधानमंत्री के रूप में भारत आया और दोनों देशों के बीच फिर से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में मदद मिली। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय सम्बन्ध दुनिया में बेमिसाल हैं। दोनों देशों के सम्बन्ध बहुआयामी हैं और भूगोल, इतिहास, राजनोति और अर्थशास्त्र के सूत्रों से जुड़े हुये हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत और भाषाई उत्पत्ति समान है। समान पारस्परिक सुरक्षा हितों, सीमाओं से सम्बन्धित मुद्दे तथा ट्रेड और ट्रांजिट तथा औद्योगीकरण से संबंधित बातें दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का निर्धारण करती रही है।

पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। अमेरिका और चीन के साथ नेपाल के सम्बन्धों को प्रभावित करते रहे हैं। अब अमेरिका ने भी भारत को विकसित होते हुये विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में मान्यता दी है। भारत और चीन भी अपने सम्बन्धों को सुधार रहे हैं। भारत और नेपाल दोनों ने उदार व्यापारिक और आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जिसके अंतर्गत और अधिक खुलेपन और आजादी की आवश्यकता है।

दुनिया से शीत युद्ध का माहौल समाप्त हो गया है। परन्तु आज एक नये तरह का खतरा पैदा हो गया है और वह है आतंकवाद का। 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र और उसी वर्ष 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर हुआ आतंकवादी हमला इस बात का सबूत है कि आतंकवाद बड़े से बड़े शक्तिशाली देश के लिये भी एक खतरा बन गया है। नेपाल भी माओवादी हिंसा के आतंक से ग्रस्त है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा जो एक वरदान रही है अब वह हथियारों, नशीले पदार्थो और जाली नोटों की तस्करी का माध्यम बन गयी है। दोनों देशों के सहयोग से ही दोनों देशों पर सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधिययों को रोका जा सकता है। मेरा विश्वास है कि दोनों देशों के नागरिकों की सुविधाओं को नुकसान पहुंचाये बिना खुली सीमा के प्रबंधन के लिये प्रभावशाली तरीका निकालना होगा। इसके साथ ही दोनों देशों को विश्व के बदलते हुये परिवेश मं अपनी आर्थिक नीतियों को और सुगम तथा प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।

जल संसाधनों के विकास के मामले में हो रही देरी से दोनों देशों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब समय आ गया है कि अतीत में लागू की गयी परियोजनाओं की प्रगति और उनसे उत्पन्न समस्याओं की समीक्षा की जाय तथा भविष्य के लिये नयी योजनाएं तैयार की जाएं। सूचना तकनीक के बारे में भारत की प्रगति सराहनीय है। नेपाल इससे लाभ उठा सकता है। पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच प्रचुर सहयोग की संभावनाये ंहै।

नपाल और भारत दोनों ही देशों में एड्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के सहयोग से इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसी तरह की एक और समस्या है–महिलाओं और बच्चों की अवैध खरीद– फरोख्त तथा उन्हें वेश्यावृत्ति में लगाना। दोनों देशों का मिलकर इस शर्मनाक गतिविधि को निर्मूल करना होगा।

21वीं सदी में दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को परस्पर सहयोग, एक दूसरे की सहमति, आपसी विश्वास तथा सुरक्षा और विकास के लिये हमारे सक्रिय प्रयास से और मजबूत बनाया जा सकता है। भारत का एक छोटा पड़ासी और निकट का एक मित्र होने के नाते नेपाल भारत से उदारता की उपेक्षा रखता है। मैं यह समझता हूँ कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार दोनों देशों के संबंधों में भी सुधार होते रहने चाहिये। नेपाल और भारत चाहे तो वे अपने सम्बन्धों को दुनिया में बेमिसाल बना सकते हैं।

***

श्री कीर्ति निधि बिष्ट

नेपाल के वयोवृद्ध और पुरानी पीढ़ी के एक सम्मानित नेता कीर्ति निधि बिष्ट की छवि दरबार समर्थक नेता की है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि वे नेपाल में राजतंत्र के समर्थक है। संसद भंग होने तथा नेपाल में आपातकाल की घोषणा के पश्चात उनके निवास पर आने–जाने वाले की भीड़ बढ़ गयी। मीडिया में उनकी छवि चीन समर्थक राजनेता की है। इसलिये कुछ लोग उन्हें भारत विरोधी भी समझते हैं। आज वे सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। वे नेपाल मेंउन दिनों प्रधानमंत्री थे जब भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उनके ड्राइंगरूम में चीनी नेताओं की तस्वीरों के साथ–साथ भारतीय नेताओं जैसे लाल बहादुर शास्त्री, मोरार जी देसाई और इंदिरा गांधी की तस्वीरें अधिक शोभा बढ़ा रही हैं। कीर्ति निधि बिष्ट मुझे एक स्पष्टवादी और नेपाल के हितों के लिये किसी से भी टक्कर लेने वाले नेता लगे। शायद यही वजह है कि उन्हें कई बार गलत समझ लिया गया।

श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि –नेपाल में भारत के मिलिट्री मिशन को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। अंततः भारत ने उसे वापस बुला लिया। जब इंदिरा जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो कहा उसका तात्पर्य यह था कि अगर भारत की कोई बात नेपाल को पसन्द नहीं है तो उसके लिये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम बातचीत करके हल कर सकते हैं, इंदिरा जी बहुत भली महिला थी। वे वास्तव में भारत–नेपाल सम्बन्धों को सही दिशा में विकसित करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम लोग भारत–नेपाल संबंधों को मित्रता के एक नये युग में ले चलेंगे। भारत के अन्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शाास्त्री से मरे सम्बन्ध बहुत अच्छे थे। मैं जब कभी दिल्ली जाता तो उनसे मुलाकात अवश्य करता। वे नेपाल के बड़े हितेषी थे। शास्त्री जी की सादगी से आज के राजनेताओं को सीख लेनी चाहिये। वे संत पुरूष थे। उनके लिये मेरे मन में बड़ा सम्मान का भाव है। इसी प्रकार मोरार जी देसाई नेपाल के बहुत बड़े मित्र थे। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्वकाल में भारत ने नेपाल का प्रस्ताव मानकर ट्रेड और ट्रांजिट की अलग–अलग संधियां की। उनका कहना था कि नेपाल जैसे जमीन से घिरे लैंड लाकड देश को समुद्र तक पहुंचने की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिये। मैं समझता ह् कि मोरार जी भाई के समय ही भारत ने नेपाल को व्यापार संबंधी बहुत सारी सुविधाएं दी। आज हमें पता चल रहा है कि जो सुविधाएं उस समय मिल गयीं उन्हें आज हासिल करना कितना कठिन है।

नेपाल के राजवंश के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में श्री बिष्ट ने कहा कि नेपाल नरेश विश्व क एकमात्र हिन्दू राजा हैं, उन्हें पता है कि भारत में उनका बड़ा सम्मान है। परन्तु, जैसा कि मैने कहा अगर वे कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। वे एक संवैधनिक राज प्रमुख है। जैसा कि नरेश ज्ञानेन्द्र ने कहा कि वे नेपाल में प्रजातंत्र के प्रतिबद्ध हैं। परन्तु इसके साथ ही नेपाल की जनता की भलाई के लिये उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वे चुप बैठने वाले राजा नहीं हैं। जनता की भलाई के लिये समय आने पर वे सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं। पर जनता की भावना के

बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मुझे याद है कि एक बार नेपाल के कुछ हिस्सों में अचानक भयंकर बाढ़ आ गयी। हजारों लोग तबाह हो गये। उस समय महाराज वीरेन्द्र ने युवराज दीपेन्द्र को कहा कि वे बाढ़ राहत कार्यो में सरकार की सहायता करें। इस बात पर कुछ लोगों ने नेपाल नरेश की आलोचना की आर यहां तक कहा कि प्रजातंत्र में युवराज को इतना सक्रिय होना उचित नहीं। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूॅ। आप जानते हैं कि मै तो प्रबल राजतंत्र समर्थक हूॅ। मै समझता हूॅ कि वर्तमान नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र भारत–नेपाल के परम्परागत संबंधों को और मजबूत बनाने के लिये अपने प्रभाव का इस्तेमाल अवश्य करेंगे।

नेपाल को भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखना है। भारत के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा सम्बन्ध होना चाहिये, क्योंकि नेपाल को अपनी जरूरतों के लिये भारत पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता हैं। कभी–कभी कुछ लोग चीन के साथ नेपाल के बढ़ते सम्बन्धों को लेकर शंका करते हैं जो उचित नहीं है, क्योंकि नेपाल–चीन के संबंधों से भारत को भी लाभ हो सकता है। नेपाल के लोग न केवल आर्थिक दृष्टि से भारत से जुड़े हुये हैं। बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत करीब है। नेपाली नागरिक भारत के बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम् आदि तीर्थो में जाने की इच्छा रखते हैं। मैं स्वयं राजा महेन्द्र के साथ इन तीनों तीर्थो की यात्रा कर चुका हूॅ।

मेरी समझ से ऐसा सोचना गलत होगा कि अगर नेपाल नरेश सक्रिय होगे तो प्रजातंत्र को खतरा होगा। आज तो प्रजातंत्र की एक लहर चल पड़ी हैं सऊदी अरब जैसे देश में भी प्रजातंत्र की स्थापना की बात चल रही है। मैं समझता हूॅ कि जब तक नेपाल नरेश अपने व्यक्तिगत हितों के लिये सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं करते यहां प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं है अपितु नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के सक्रिय होने से नेपाल का भला ही होगा। परन्तु यह बात यहां के नेताओं कीी समझनी है।

माओवाद यहां एक नयी समस्या के रूप में पनपा है। इसके पीछे चीन का कोई हाथ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की यह शंका भी निराधार है कि नेपाल के माओवादियों को भारत से मदद मिल रही है। ऐसा सोचना भी बकवास है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण संभव है कि कुछ माओवादी नेता भारत में छिप जाते हों, परन्तु माओवादी समस्या से निपटने के लिये भारत जो मदद नेपाल की कर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिये।

नेपाल के नागरिकता विहीन लोगों को अगर हम लम्बे समय तक टालते रहे तो इसका भारत–नेपाल संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं समझता हूॅ कि इस मुद्दे को बहुत सतर्कता और रेस्ट्रेन्ट के साथ हल करना चाहिये। इसलिये गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकार ने इसके समाधान के लिये जो कदम उठाया मैंने खुलकर उसकी आलोचना की। नागरिकता कानून को इस हल्के ढंग से नहीं बदला जा सकता हैं परिणाम जानते ही हैं। उस विधेयक को न्यायालय ने अनुचित ठहरा दिया। वह अब भी नेपाली नरेश के पास लम्बित है। इस सम्बन्ध में नेपाल नरेश कुछ नही कर सकते। सरकार को पहल करनी चाहिये।

आप जानते हैं कि लाखों नेपाली वर्षो से भारत में रह रहे हैं वहां काम करते हैं, उन्हें वहां नागरिकता नहीं मिल रही है। तो फिर नेपाल में रहने वाले विदेशियों को नागरिकता कैसे दी जा सकती है? लेकिन जो वास्तव में नेपाली

नागरिक हैं उन्हें तो प्रमाण पत्र मिलना ही चाहिये। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस समस्या का समाधान तुरन्त होना चाहिये। अगर यह ज्यादा दिनों तक टलता रहा तो और पेचीदा हो जायेगा तथा भारत और नेपाल दोनों के लिये सिरदर्द हो सकता है।

भारत–नेपाल सम्बन्धों का भविष्य उज्ज्वल है। इसे बेहतर बनाने के लिये काफी कुछ हो रहा है। परन्तु और अधिक करने की आवश्यकता है। लेकिन कभी–कभी भारत सरकार ऐसे निर्णय लेती है जिससे नेपाल की परेशानी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत के उद्योग मंत्री राम कष्ण हेगड़े के समय नेपाल के साथ व्यापारिक संधि हुई, उसके अंतर्गत भारत ने नेपाल को कुछ सुविधायें दी। आज अचानक नयी संधि में उन सुविधाओं पर रोक लगा दी गयी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत अपने यहां के व्यापारियों को नुकसान पहुंचा कर कोई सहूलियत नेपाल को दे। दोनों देशों के व्यापारियों के बीच स्वस्थ स्पर्धा तो होनी चाहिये। परन्तु नेपाल के साथ सहानुभूति और उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। अगर वाकई पुरानी संधि के अंतर्गत भारतीय व्यापारियों को कोई परेशानी थी तो उस पर सलाह मशविरा किया जा सकता था, किन्तु संधि के नवीनीकरण में इतनी हीला–हवाली और देरी उचित नहीं। इससे माहौल बिगड़ता है। शायद भारत 'गुजराल डाक्ट्रीन' को भूल जाना चाहता हैं। यह कहते रहना कि भारत और नेपाल के विशेष सम्बन्ध हैं, पर्याप्त नहीं। भारत को नेपाल की सहायता अवश्य करनी चाहिये। अमेरिका और इंग्लैण्ड एक दूसरे से कितने दूर हैं परन्तु दोनों एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। भारत नेपाल के कितना करीब है, परन्तु सहायता करने के बारे में कितना सोचता है।

नेपाल में मीडिया में भारत विरोधी खबरों को बढ़ाचढ़ाकर छापन से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में श्री बिष्ट ने कहा कि यह सर्वथा उचित है। नेपाल को अपने हितों के बारे में चिन्ता प्रकट करने का अधिकार है, हो सकता है कि कभी यह ज्यादा हो जाता होगा। परन्तु अगर भारत–नेपाल सीमा पर भारत द्वारा बनाये जा रहे बांधों जैसे–लक्ष्मणपुर बांध, रसियावल, खुर्दलोटन बांध से नेपाली जनता को नुकसान हो रहा है तो नेपाल को विरोध करने का पूरा अधिकार है। मैं नहीं समझता इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता हैं। दो एक लोग इस प्रकार क हो सकते हैं, परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी समस्या को हम परस्पर बातचीत से सुलझा सकते हैं।

कीर्ति निधि बिष्ट का सम्बन्ध लखनऊ से भी रहा है उन्होनें लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। आज भी उनके अनेकों मित्र लखनऊ में हैं जिनसे समय–समय पर उनका सम्पर्क होता हैं हालांकि उन सम्पर्को का सिलसिला अब कमजोर पड़ता जा रहा है। परन्तु उन्होने मेरे साथ जिस सहृद्यता, स्नेह, सम्मान और आत्मीयता से बात की वह इस बात का प्रतीक है कि उनके मन में भारत के लोगों के लिये अपार स्नेह और सम्मान है।

यह साक्षात्कार उस समय लिया गया था जब नरेश ज्ञानेन्द्र नेपाल के राजा थे।

***

बनवारी लाल मित्तल

राजनीति शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रन्थ है–अर्थशास्त्र जिसे चाणाक्य ने लिखा था। इस पुस्तक के नाम से ही सिद्ध है कि आर्थिक मुद्दे ही राजनीति की दिशा निर्धारित करते हैं जबकि सांस्कृतिक सम्बन्ध समय आने पर गौड़ हो सकते हं क्योंकि राष्ट्र और व्यक्ति उनक बगैर भी बन रह सकते हैं पर आर्थिक सम्बन्धों की अनदेखी चाह कर भी नहीं की जा सकती है। इस दृष्टि से हमने नेपाल के एक प्रमुख उद्योगपति बनवारी लाल मिततल से बात की।

बनवारी लाल मित्तल नेपाल के चोटी के गिने–चुने व्यापारियों में स एक हैं। इनके पूर्वज वर्षो पूर्व दरबार के निमंत्रण पर नेपाल में व्यापार करने के लिये राजस्थान से आये थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नेपाली समाज में अपना एक स्थान बनाया। इसलिये उन्हें लोगों का भरपूर सम्मान प्राप्त है। वे यहां की सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बनवारी लाल जी तो जन्म से नेपाली हैं परन्तु भारत के लोगों से उनका सम्बन्ध उतना ही गहरा है जितना कुछ अन्य नेपालियों का है। इसके बावजूद ह्रातिक रोशन कांड के दौरान उनके निवास को भी निशाना बना गया। परन्तु वे विचलित नहीं हैं। वे इसे दुर्भाग्य बताते हैं। वे भारत–नेपाल संबंधों के बारे में काफी गहनता से सोचते है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा के उपरांत आर्थिक मुद्दे ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य साबित होगे जो दोनों देशों को प्रभावित कर उनके आगे के सम्बन्धों की दिशा का निर्धारण करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मित्तल साहब के विचार काफी माने रखते हैं। प्रस्तुत हैं उनसे हमारी बातचीत के कुछ अंश।

भारत और नेपाल के आर्थिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ रहे। नेपाल के आर्थिक विकास में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है और भविष्य में भी रहेगा। नेपाल की वस्तुओं का सबसे नजदीक का बाजार भारत ही है। भारतीय वस्तुओं का भी नेपाल में प्रचुर मात्रा में आयात होता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के लोगों का खानपान एवं उनके विचारों में भी समानता होने के कारण भारतीय वस्तुओं से नेपाली जन सामान्य जुड़ा हुआ है। यह सम्बन्ध इतना गहरा है कि नेपाल में भारतीय वस्तुएं विदेश से आने वाली वस्तुएं जैसे नहीं लगती। यह पूछे जाने पर कि भारत और नेपाल की आर्थिक प्रगति जितनी द्रुत गति से हो रही है उनती द्रुत गति से नेपाल में आर्थिक प्रगति क्यों नहीं हो रही? श्री मित्तल ने कहा कि ''ठीक है –चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, हमसे सटा हुआ है, परन्तु वहां की आर्थिक प्रगति हमें भौगोलिक कारणों से उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी भारत की आर्थिक प्रगति। भारत की आर्थिक प्रगति का सीधा प्रभाव नेपाल पर पड़ता है परन्तु यह वास्तव में विचारणीय प्रश्न है कि भारत की तुलना में नेपाल की आर्थिक प्रगति मंद क्यों है? नेपाल की अर्थ–व्यवस्था भारत से इतनी जुड़ी हुई है कि मैं इसे सेटेलाइट अर्थ–व्यवस्था मानता हूँ। भारत के आर्थिक विकास का सीधा प्रभाव नेपाल पर पड़ना चाहिये। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसके दो–तीन प्रमुख कारण हैं–पहला आंतरिक कारण है–नेपाल में शांति और सुरक्षा की समस्या। आर्थिक विषयों को भी जितना महत्व

हमें देना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं। इसकी अपेक्षा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को हम अधिक महत्व देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि नेपाल से जुड़ा हुआ जो भारतीय क्षेत्र है, उसकी आर्थिक प्रगति भी बहुत धीमी है, जिसका सीधा नेपाल पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपेक्षाकृत भारत के पिछड़े राज्य हैं और इनके क्षेत्र नपाल से जुड़े हुये अथवा नजदीक होने के कारण भी नेपाल की प्रगति विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। इसका एक असर नेपाल में यह होता है कि नेपाल के अधिकांश भू–भाग में रहने वाले लोगों को भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति का सच्चा अहसास ही नहीं होता एवं इन्हों राज्यों के लोगों के व्यवहार के आधार पर ही नेपाल में भारतीयों की छवि बनती है जो सही चित्र प्रदर्शित नही करती। अगर नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की आर्थिक प्रगति अच्छी होती तो नेपाल की आर्थिक प्रगति को भी तीव्र बढ़ावा मिलता। भारत–नेपाल के बीच हाल ही में हुई नई व्यापार संधि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी संधि या करार के दो पहलू होते हैं एक तो जो कागज में लिखा होता है और दूसरा जिस तरह उसे लागू किया जाता है। मैं समझता हूं कि नेपाल के आर्थिक विकास के लिये यह जरूरी है कि दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों तरफ कुछ गलतफहमियां हैं। भारत की दृष्टि में नेपाल हमेशा यह प्रयास करता है कि संधि में कोइ लूपहोल (छिद्र) मिल जाय जिसका वह लाभ उठा सके। हो सकता है कि मैं गलत हूं परन्तु मुझ ऐसा लगता है। इसी तरह नेपाल भी यही सोचता है कि भारत अनावश्यक रूप से नेपाल जैसी छोटी अर्थव्यवस्था की प्रगति में व्यवधान खड़ा कर देता है। वास्तविकता यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के विकास में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा पहले यह है कि नेपाल के आर्थिक विकास में भारत के अलावा किसी अन्य देश की सहभागिता बढ़ती है तो वह भारत के लिये लाभप्रद नहीं होगा। नेपाल और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के अनेक क्षेत्र हैं। नेपाल और भारत एक दूसरे को जल स्रोतों के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन इत्यादि में काफो सहयोग कर सकते हैं और इस तरह भारत आने वाले अधिकांश पर्यटक नेपाल तथा नेपाल आने वाले अधिकांश पर्यटक भारत आ सकते हैं। नेपाल की जलवायु ऐसी है कि यहां दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पैदा होती है। जो मंहगी से मंही बिकती हैं, इनकी मांग भारत में पुरातन काल से रही है और अब बढ़ रही है। इन जड़ी बूटियों की पैदावार नेपाल में आसानी से बढ़ रही है। नेपाल भारत के अपने पड़ोसी राज्यों को तथा दुनिया के अन्य देशों को जड़ी बूटियों की मांग के अनुसार उनकी आपूर्ति अपने यहां उद्योग और कुटीर धंधें स्थापित करके कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, कृषि उत्पादों इत्यादि के क्षेत्रों में भी दोनों देश एक दूसरे को काफी सहयोग कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिये मेरा यह सुझाव है कि जब कभी भी और जहां कही भी दोनों देशों के बीच किसी वस्तु के आयात–निर्यात को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका त्वरित समाधान एक संयुक्त समिति/संयुक्त संगठन द्वारा किया जाना चाहिये। अतः इस प्रकार की संस्था का गठन जरूरी है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने नेपाली चाय के आयात पर कुछ टैक्स लगा दिये। नेपाल के व्यापारियों का ऐसी स्थिति

में चिन्तित होना स्वाभाविक है। ऐसी समस्यायें लम्बी न खिंचे और ये और अधिक गहन न हों अतः इन समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिये।

नेपाल के जल संसाधन के बारे में अगर मैं सत्य बोलू तो कहना पड़ेगा कि नेपाल को नुकसान हुआ है। कर्नाली परियोजना की बात होते–होते 40 साल हो गये हैं। अगर समयसे कार्य प्रारम्भ हो गया होता तो अब तक कितना लाभ हुआ होता। भारत को भी नुकसान हुआ क्योंकि अगर यह परियोजना पूरी हो गयी होती तो भारत को भी बिजली मिलती और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलता। इस प्रकार की परियोजनाओ ंमें देरी का कारण यह है कि जब कभी कोई गलतफहमी होती है तो उसे दूर करने की तत्काल कोई कोशिश नहीं की जाती है। होना यह चाहिये कि भारत के निवशकों को नेपाल के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र में इन परियोजनाओं को स्थापित किया जाना चाहिये। यह पूछे जाने पर क्या महाकाली संधि लागू होगी उन्होंने कहा कि होनी चाहिये, मै तो शुरूआत से मानता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिये। इससे न केवल दोनों देशों के आर्थिक विकास को बल मिलेगा बल्कि दोनों दशों के बीच मैत्री और सद्भावना भी बढ़ेगी।

कुछ दिनों पहले ह्रतिक रोशन कांड के दौरान भारतीय मूल के नेपाली उद्योगपतियों और व्यपारियों को भी हिंसक घटनाओं का निशाना बनाया गया। इसके कारणों की व्याख्या करते हुये श्री मित्तल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी परन्तु इसका एक अच्छा पहलू भी है कि आम नेपाली ने उपद्रवियों का साथ नहीं दिया। सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा नियोजित षड्यंत्र था क्योंकि नेपाल की कुछ पत्र–पत्रिकाएं भारतीय मूल क लोगों और जाति विशेष के खिलाफ भड़काने वाले लेख छाप रही थीं, जिसका कुप्रभाव जन मानस पर पड़ा होगा। परन्त अच्छी बात यह है अब यह सिलसिला भी कमजोर पड़ रहा है। वह आंदोलन बहुत सुगठित ढंग से किया गया। चुन–चुन कर विशेष जाति के कुछ लोगों पर तथा उनके घरों पर हमले किये गये। परन्तु आम नेपालियों ने उनका साथ नहीं दिया। इसमें लेशमात्र भी कोई संदेह नहीं कि इसके पीछे कोइे षड्यंत्र था। इसका भारत–नेपाल के संबंधों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। पर इसके लिये यह भी जरूरी है कि दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ना चाहिये। केवल शासकीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच ही नहीं अपितु दोनों राष्ट्रों के लोगों के बीच में भी सम्पर्क बढ़ाकर उसे प्रगाढ़ करने तथा एक दूसरे की भावनाओ ंको समझने की जरूरत है।

यह पूछने पर कि नेपाल अगर विश्व व्यापार संगठन ;ॅवतसक ज्तंकम व्तहंदपेंजपवदद्ध का सदस्य बन गया तो उसका भारत–नेपाल संबंधों पर क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के व्यपारिक सम्बन्धों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल और भारत के आर्थिक सम्बन्ध विशेष हैं और हमेश रहेगें। उनका सुझाव था कि भारत और नेपाल का एक साझा बाजार विकसित किया जाना चाहिये। आगे उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुये कहा कि भारत–नेपाल सम्बन्ध बहुत ही करीबी हैं जिसका भविष्य भी उज्ज्वल है पर करीबी संबंध होने के कारण भारत की कभी–कभी छोटी से अनदेखी से भी नेपाल की भावना आहत हो जाती हैं। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिये धार्मिक

तथा सामाजिक स्तर पर भी प्रयास होने चाहिये तथा भारत के बारे में नेपाल की आम जनता को और अधिक जानकारी दी जानी चाहिये।

***

श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा

रवीन्द्र नाथ शर्मा नेपाल की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। वे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सक्रिय नेता हैं। वर्षो तक मंत्री रहे हैं। भारत की सीमा से लगा नेपाल का नवलपरासी जिला उनका निर्वाचन क्षेत्र है। इस दृष्टि से वे दोनों देशों के सम्बन्धों के सभी पहलुओं को गहराई से जानते हैं। भारत के राजनेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य संभ्रांत लोगों से उनका लगातार संपर्क रहता है। इस दृष्टि से उनके विचार काफी महत्वपूर्ण है। काठमांडू के सानेपा स्थित अपने निवास स्थान में उन्होंने मुझसे भारत–नेपाल संबंधों पर खुलकर बात की। उनके व्यवहार में जो आत्मीयता और अनौपचारिकता देखने को मिली उसने दोनों देशों के गहरे एवं घनिष्ठ सम्बन्धों की ओर संकेत दिया। उन्होंने बताया कि भारत के साथ नेपाल का गहरा तथ पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। भाषा के मामले में भी नेपाली लोग संस्कृत और हिन्दी समझ लेते हैं। नेपाल का पशुपति नाथ मंदिर तो भारत के हिन्दुओं की अगाध श्रद्धा का केन्द्र है। नेपाल और भारत का सम्बन्ध विशेष ढंग का, अनोखा एवं दो भाईयों जैसा है। जिस तरह दो भाईयों का सम्बन्ध अत्यंत मधुर होता है साथ ही अत्यन्त भवानात्मक (सेन्टीमेंटल) और संवेदनशली भी, ठीक उसी तरह भारत और नेपाल का सम्बन्ध भी अत्यन्त भावानात्मक और संवेदनशील है। संवेदनशीलता महसूस न करने पर जिस तरह दो भाईयों के बीच आशंकाओं और विश्वास की भावनाएं उठ खड़ो होती हैं ठीक उसी तरह जब दोनों देश इस संवेदनशीलता को भुला देते हैं अथवा ताक पर रख देते हैं। तो उनके बीच भी आशंकाओं और अविश्वास की भावनाओं का उठ खड़ा होना स्वाभविक है। कुछ भी हो जाये पर दोनों देशों को यह कदापि नही भूलना चाहिये कि उनको भूगोल ने एक साथ रख दिया है। दोनों देश अपनी–अपनी व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं पर भूगोल में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब दोनों देशों को साथ ही रहना है तो क्यों न एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखें और विश्वास को कायम रखें। भारत का नेपाल में इंटरेस्ट बहुत सीमित है। ब्रिटिश इंडिया का नेपाल में अगर इंटरेस्ट होता तो नेपाल अछूता नहीं रहता। हम इस बात को नहीं मानते कि नेपाल के मजबूत होने के कारण ब्रिटेन ने नेपाल पर हाथ नहीं डाला। यह भी सच नहीं कि हमारी बहादुरी के कारण हम ब्रिटेन के अंतर्गत नहीं आये। सच यह है वास्तव में उस समय नेपाल का भू–भाग ब्रिटेन के लिये एक एसेट के बजाय लाइबिलिटी ज्यादा था। इसलिये उन्होंने इसे नहीं छुआ। किन्तु आज स्थिति बदल गयी हैं आज नेपाल लाइबिलिटी नहीं रह गया है। नेपाल अब जल–स्रोत का धनी देश है। भारत के नक्शे में भी परिवर्तन आया है। कभी ब्रिटिश इंडिया के भाग रे म्यांमार (बर्मा), बांगलादेश तथा पाकिस्तान अब अलग देश हो गये हैं। वर्तमान में नेपाल में भारत का इंटरेस्ट सीमित होने के बावजूद काफी महत्वपूर्ण है। भारत का जो स्वार्थ अब नेपाल में हैं वह सर्वप्रथम सुरक्षा की दृष्टि से है और कदाचित यह भारत की मजबूरी है। अतः नेपाल को यह समझना चाहिये कि उसकी वजह से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिये। नेपाल को एक भाई की तरह इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निभाना चाहिये। हिन्दुस्तान को भी यह समझना चाहिये कि नेपाल

एक छोटा देश है, पिछड़ा है, वहां गरीबी है, अतः हिन्दुस्तान को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि नेपाल में किसी प्रकार की कोई आशंका पैदा हो। यदि दोनों देश इस तत्य को सामने रखकर काम करें ता दोनों देशों का सम्बन्ध दुनिया में बमिसाल संबंध हो सकता है। भारत के ऊपर नेपाल की निर्भरता लगभग 95 प्रतिशत है जबकि भारत की निर्भरता नेपाल के ऊपर मात्र लगभग 5 प्रतिशत होगी। भारत अपनी इस निर्भरता को समझप्त कर सकता है। सेना में भर्ती का विषय लें तो यह विदित होगा कि भारतीय सेना में नेपालियों की भर्ती के बिना भी काम हो सकता है और भारत का काम चल सकता है क्योंकि भारत में भी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है।,परन्तु नेपाल की निर्धरता कम नहीं की जा सकती है।

दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं से भी बहुत समस्यायें हैं। सोमाओ को रेगुलेट करना भी अत्यत जरूरी है। इसके माने है कि भारत से नेपाल कितने लोग आते हैं तथा नेपाल से कितने लोग भारत आते हैं, इसका भी रिकार्ड होना चाहिए। भारत–नेपाल संधि के कारण भारत के लोग नेपाल में आ सकते हैं, रह सकते हैं व काम कर सकते है परन्तु हमें यह डर है कि भारतीय के लगातार आने से और नेपल में बसने से कहीं नेपाली ही अल्पसंख्यक न हो जाय। अतः सीमा पर जांच होना और उसका रिकार्ड रखना जरूरी हैं पर अब भारत के लिये भी आवश्यक हो गा है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जाय। बाग्लोदेश के निर्माण के बाद जो बिहारी मुसलमान थे वे लौटकर हिन्दुस्तान आये, उसमें से कुछपाकिस्तान चले गये और कुछ नेपाल की तराई में आकर बैठ गये जिनकी संख्या हजारों में हैं । इस वजह से तराई क्षेत्र में जो अब तक हिन्दुस्तान का मित्र क्षेत्र था, अब भारत के लिये परेशनी वाला क्षेत्र बन गया है। मैं कोईग साम्प्रदायिक बात नहीं कर रहा हूॅ। यह जो हिन्दुस्तान बार–बार आई.ए.एस. की रट लगा रह है तो कौन होवो, किसके जरिये से है। इसलिये सीमाओं को रेगुलेट करना चाहिये। सीमा पर जो आते–जाते हैं उनका रिकार्ड सरकार के पास होना चाहिये। देखिये पासपोर्ट और आई.कार्ड लागू करना जरूरी नहीं है। परन्तु आने–जाने वालों का रिकार्ड होना चाहिये। इधर एक परिवर्तन हुआ है िकइस देश के लोग भी अब समझ रहे है कि नेपाल की आर्थिक उन्नति के लिये भारत का सहयोग जरूरी है क्योंकि निर्भरता बढ़ी है। भारत ने भी जान लिया है कि नेपाल का चीन से संबंध बढ़ना उसके खिलाफ नहीं हैवरना नेपाल ने जब तातोपानी के मार्ग से चीन के साथ सम्पर्क स्थापित किया तो भारत को लगा कि साम्यवाद अब इसी रास्ते से आ जायेगा। परन्तु अब उसे भी ऐसा नहीं लगता है। अब नेपाल चीन सीमा पर और कई राजमार्गो से जुड़ रहा है क्योंकि युद्ध की परम्परागत अवधारणा अब समाप्त हो गयी है।

नेपाल में भारत विरोधी भावना भड़कने का कारण क्या है? यह पूछे जाने पर श्री शर्मा ने कहा कि –''...देखिये, कभी–कभी मुख्य समस्या की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिये नेता नेपाल में ऐसा मुद्दा उछाल देते हैं। हमने राष्ट्रवाद का नारा दिया 1960 में। यह अच्छी बात है परन्तु क्या यह जरूरी है कि नेपाली राष्ट्रवाद का पर्याय समझते हैं। वे राष्टवाद के नाम पर उक्त जो समस्यायें हैं उनको छिपाना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। कुछ विदेशी ताकतें है जो चाहतीं होगी कि

ऐसा हों। परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल नेपाल में भारत विरोधी भवना के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। ह्रतिक रोशन कांड नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के लिये खुशी की बात हा सकती है, परन्तु इस कांड के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ हो, मैं नहीं मानता। ह्रतिक रोशन कांड के पहले नेपाल से भारतीय जहाज का अपहरण किया गया उसको भारतीय मीडिया ने जिस ढंग से उछाला वह नेपाल के लिये आपत्तिजनक है। इससे दोनों देशों का संबंध बहुत खराब हुआ। हाइजैक तो कहीं से भी हो सकता है परन्तु जिस ढंग से भारतीय मीडिया ने प्रस्तुत किया, नेपाल की भावनाओं को बहुत ठेस लगी और बहुत संभव है वही भावना ह्रतिक रोशन कांड के समय फूट पड़ी, वैसे ह्रतिक रोशन कांड के पीछे भी एक साजिश थी उसके बारे मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ लोग कहते ह कि इसे पीछे आई.एस.आई. का हाथ है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान ही यह कराना चाहता था। लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस कांड का भारत–नेपाल सम्बन्धों पर क्या असर पड़ा, यह एक अलग मुद्दा है। परन्तु इस कांड से नेपाली और गैर नेपाली के बीच जो दरार पैदा हुई वह चिन्ता की बात है। जिस ढंग से अविश्वास पैदा किया गया उससे हमारी शंका बढ़ गयी है।

नेपाल की नागरिकता समस्या के बारे में पूछे जाने पर श्री शर्मा ने कहा कि नागरिकता सेन्टीमेटल बात है। कोई भी देश किसी द्सरे देश से आने वाले सभी लोगों को नागरिकता नहीं दे सकता। भारत स्वयं 1950 के बाद नेपाल से गये लोगों को नागरिकता नहीं दे रहा है। एक करोड़ बांग्लादेशी वर्षो से भारत मं हैं, भारत उन्हे भी नागरिकता नहीं दे रहा है। इसलिये खुली सीमा होने के कारण जितने लोग भारत से आयेंगे उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती है। यह समस्या इतनी जटिल हो गयी है कि इसक बारे में एक कठोर राजनीतिक फैसला लेने की जरूरत है। इसके बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वास्तविकता यह है कि एक ही परिवार का एक भाई नेपाल में है तो दूसरा नेपाल में। दोनों अपने–अपने यहां नागरिक हैं। चुनाव के समय यहां के लोग वहां वोट देते हैं है आर वहां के लोग यहां आकर मतदान करते हैं।

.....तो नेपाल की नागरिकता की समस्या भारत के लिये भी सिरदर्द हो सकती है। जिस तरह से नेपाल की तराइ में आबादी बढ़ी है दूसरा एक कारण है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान नेपाल आ रहे हैं पहाड़ से भी लोग तराई में बस रहे हैं

वर्ष 1950 की संधि केवल कागज में हैं व्यवहार में नहीं है। दोनों देश कहते हैं इसमें संशोधन होना चहिय। परन्तु क्या संशोधन होना चहिय? ऐसा कोई बताता। हमारे विचार से अब स्थिति बदल गयी है। दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधियों को इस पर खुलकर बात करनी चाहिये। वैसे यह संधि अब बेमानी हो गयी है। हां समय समय पर भात के खिलफ बोलने के लिये नेपाल में इसका सहारा अवश्य लिया जाता है।

(शर्मा जी का एकवर्ष पहले निधन हो गया। यह साक्षात्कार उनके निधन के ठीक पहले का है।)

पं0 वेदनन्द झा

'जीवेम् शरदः शतम्' की दहलीज पार कर चुके पं. वेदानन्द झा नेपाल की तराई के एकमात्र ऐये व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल अपनी योग्यता के आधार पर वह सब कुछ हासिल किया, जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले किसी भो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है। पटना के प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय श्रीकांत ठाकुर पं. वेदानन्द झा के फुफेर भई थे। उन्हीं क सहयोग से पंडित वेदानन्द झा ने कलकत्ता से पत्रकार के रूप में अपना कैरियर प्रारम्भ किया। बादे में उनक साथ ही बनारस चले गये। उस समय बनारस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं और देशभर के पत्रकारों का केन्द्र था। राजा कशव प्रसाद गुप्त और कमलापति त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों की याद करते हय पं. वेदानन्द झा की बूढ़ी आंखों में जो चमक मैं देखो वह किसी को भी भावविह्वल कर देने के लिये काफी है।

नेपाल में पं. वेदानन्द झा को राजशाही व्यक्ति माना जाता है। वे राजा द्वारा नियुक्त राजसभा के सभापति थे। नेपाल के मंत्री भी थे। नेपाल के बहुत से नेताओं द्वारा विरोध जताने के बावजूद नेपाल नरेश ने उन्हें भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया। वह बड़ा कठिन समय था—नेपाल और भरत दोनों के लिये। इस दृष्टि से भारत—नेपाल से सम्बन्धों मे बारे म पं. वेदानन्द झा के विचार कम महत्वपूर्ण नहीं। काठमांड् में उनके निवास पर जाने तथा पं. वेदानन्द झा से मिलने के बादे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अत्यंत निकट व्यक्ति के घर आये हैं। प्रस्तुत है उनसे हुई मेरी बातचीत के कुछ सारगर्भित अंश—

उनका कहना था कि '' मैंने तीन भारतीय प्रधानमंत्रियों को देखा—मोरार जी देसाई,, चरण सिह और इंदिरा गांधी। कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी नेपाल के सख्त खिलाफ थी। असल में वह जनता पार्टी के खिलाफ थीं। वे जगह—जगह जनसभाओं में कहती थीं कि भारत का यह हाल हो गया है कि नेपाल और भूटान जैसे देश भी इसके खिलाफ अंगुली उठाने लगे हैं। मेरी समझ में उनका वह भाषण भारत में जनता पार्टो की सरकार के खिलाफ था। वास्तव में नेपाल और भूटान के खिलाफ वे नहीं। मुझे जब भारत में नेपाल का राजद्त बनाकर भेजा गया तो उस समय दोनों देशों के सम्बन्ध खराब थे। उसके बहुत से कारण थे। नेपाल भारत से बहुत सी उम्मीदें रखता था। उतना उसे मिलता नहीं था और जो मिलता है उसे नेपाल लना नहीं चाहता है। अब मैं समझता हूँ कि भारत नेपाल के साथ अपने संबंध सुधार रहा है। वर्ष 1986 में पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक पार्टी दी थी, उसमें नेपाल नरेश वीरेन्द्र शामिल नहीं हुये थे। काठमांडू लौटने पर मैने राजा से कहा कि आपने बड़ी भूल की है, जिस किसी ने आपको यह सलाह दी उसे कठोर दंड देना चाहिये। इसके बाद ही नेपाल के साथ भारत की सोमा पर स्थित नार्को को बंद कर दिया गया और पूरे नेपाल में खलबली मच गयी। उस समय मैने भारतीय नेताआ से कहा कि भारत ने यह

अच्छा नहीं किया। इससे पूरी नेपाली जनता को दंड भुगतना पड़ रहा है। इधर राजा वीरेन्द्र ने मुझसे सफाई देते हुये कहा कि प्रोटोकाल मिल न वेदानन्द। हमने कहा कि सरकार, प्रोटोकाल भगवान ने नही हमने बनाया है। राजीव गांधी भारत जैसे महान और एक विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं। आप राजाध्यक्ष और नेता भी बनेंगे और प्रोटोकाल देखेंगे तो काम कैसे चलेगा, राज चुप हो गये।

'' मोरार जी भाई से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। उनका नेपाल के प्रति थोड़ साफ्ट कार्नर था। जब मैं दिल्ली से नेपाल का राजदूत था– 1977 में मोरार जी भाई ने स्वयं फोन करके मुझको बुलाया और बहुत देर तक चर्चा की, उनसे अनौपचारिक सम्बन्ध था। उन्हीं की सद्भावना से हमारे समय में नेपाल और भारत के बीच व्यापार तथा ट्रांजिट के बारे में अलग–अलग संधियां की गयी जो नेपाल चाहता था। संधि करने के लिये दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की दो दिनों से बेठक हो रही थी, परन्तु किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद में मोरार जी देसाई के सचिव जगत मेहता के पास गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलें। मैंने कहा कि मेरा तो कोई एपाइन्टमेंट नहीं हैं। फिर जगत मेहता ने ही तुरन्त मेरी मुलाकात मोरारजी भाई से कराई। मैने उनसे कहा कि दो दिनों की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने तुरन्त जगत मेहता को बुलाया कहा कि जब नेपाल को देना है तो इसमें सोचना की क्या बता है। नेपाल जितने से खुश रहे उतना दे दो। उसके बाद दो अलग–अलग संधियां सम्पन्न हुई, अब स्थितियां बदल गयी हैं इस समय जो व्यपार संधि का नवीनीकरण हुआ है उसके पहले इतनी जद्दोजहद हुई उसका कारण नेपाल भारत से बहुत उम्मीद रखता है। परन्तु भारत में अब वे लोग नहीं रह तो फिर राजनियक तरोके से जो संभव है वहीं हुआ।

भारत नेपाल सबंध के बारे में पूछे जाने पर श्री वेदानन्द झा ने कहा कि देखिय दानों देशा के संबध में कुछ बुनियादी बात हैं–नेपाल को इंडिया से खतरा लगता है, इसके कारण भी हैं कुछ गलतियां भी हुई जसे दोनों बहुत करीबी हैं, यह सच है परन्तु दोनों देशों के बीच एक मर्यादा का भी पालन होना चाहिये। नेपाल में राष्टवाद की भावना बहुत है। इस्लामाबाद की घटना के बाद नेपाल की प्रजातंत्र की लड़ाई मे सहयोग करने के लिये भारत के सभी राजनीतिक दलों ने सक्रिय सहयोग देना शुरू कर दिया, जिसे नेपाल ने पसन्द नहीं किया, क्योंकि यह उचित नहीं था। आंदोलन के नेता बी.पी. कोईराला थे। उनके सबंध भारतीय नेताओं से थे। केवल इसी वजह से उनके आंदोलन को समर्थन देना भारत के लिये उचित नहीं था। यह मर्यादा के खिलाफ था। भारत राजनियक मामलों में बहुत अनुभवी देश है। अतः कूटनीतिक मर्यादाओं का पालन करने की जिम्मेदारी भारत की अधिक है।

नेपाल के लोगों में राजा के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है। वे राजा के खिलाफ सोच भी नहीं सकते।

नेपाल में भारत विराधी भड़कने के पीछे क्या कारण हैं? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नेपाल को लगता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और वह कभी भी नेपाल से राजतंत्र को उखाड़ फेंक सकता है। इस प्रकार की आशंका यहां के लोगों के मन में है।

परन्तु मैं आपको बता दूं कि मेरी तो भारत के सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई है। ज्योति बसु को छोड़कर सभी नेताओं के मन में नेपाल नरेश के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। केवल ज्योति बसु ने कहा कि हम राजा नहीं मानते हैं इसलिये तुम्हारे देश में नहीं जाएंगे जब तक वहां प्रजातंत्र नहीं होगा। वे बहुत शालीन आदमी है। मैं उनकी स्पष्टवादिता का सम्मान करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी नेपाल आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि नेपाल के लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं? मैंने उनसे भी यही कहा कि यहां के लोग सोचते हैं कि भारत एक सेक्यूलर स्टेट है। वहां प्रजातंत्र है वह कभी भी नेपाल के हिन्दू राजा के खिलाफ उलटफेर कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम सेक्यूलर है इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा हिन्दू राजा आबाद रहे। भारत में उनके खिलाफ कोई नहीं है। हमने यहां हिन्दू राजा नहीं बनाया ह। हम इसका विरोध क्यो करें? हां हम यह जरूर चाहते हैं कि दानों देश बिल्कुल नजदीक रहें।

यह पूछे जाने पर कि ऐसा लगता है कि नेपाल में भारत विरोधी भावना के पीछे राजतंत्र और उनसे जुड़े लोगों का हाथ है, इस सम्बन्ध में आपकी राय क्या है? श्री झा ने कहा कि क्या बतायें
केवल राजतंत्र और उनसे जुड़े नेता ही नहीं बल्कि काठमांडू में जनरल फीलिंग यही है। तराई में ऐसी फिलिंग नहीं है। तराई में कैसा होगा? इसके पोछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। बहुत हैं। वे भीतर से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। 1973 में मैं उत्तर कोरिया और चीन गया था, वहां जो मैने व्यवहार देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका उल्लेख मैने अपनी जीवनी में किया है। मैं जब मंत्री था तो लैंड लाक्ड देशों से संबंधित कन्वेशन के बारे में मैने काफी प्रयास किया। जेनेवा में भी मैंने यह बात उठाई और उसे स्वीकृत कराया। इस बात पर बहुत बहस हुई, अंततः मतदान हुआ। सावियत गुट के सभी देशों ने नेपाल के पक्ष में मतदान किया।

भारत से मेरा सम्बन्ध बहुत गहरा है। 1939 में मैं कलकत्ता गया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। श्रीकांत ठाकुर आर्यावर्त के सम्पादक मेरे फुफेर भाई थे। 1921 के सत्याग्रह में उन्हें दरभंगा जिला स्कूल से निकाल दिया गया था। वे जेल में भी रहे। फिर उन्होंने नेशनल कालेज पटना, सदाकत आश्रम से बी.ए. किया। उन्होंने कहा कि वेदानन्द तुम पत्रकारिता शुरू करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। श्रीकांत ठाकुर ने ही मेरा करियर बनाया। मैंने कलकत्ता के विश्वबंधु से शुरू किया। ठाकुर जी विश्वमित्र के सम्पादक थे। बाद में हम लोग बनारस आ गये। उस समय कमलापति त्रिपाठी ससांर अखबार में थे। प्रख्यात पत्रकार बाबू राव विष्णु राव पराड़कर भी बनारस में थे। बहुत आनन्द आया। राजा शिव प्रसाद गुप्त थे।

आपका राजदूत कैसे बनाया गया? उन्होंने कहा –भारत में नेपाल का राजदूत मुझ बनाना एक अघट घटना थी। मुझे तथा लोगों को विश्वास नहीं होता था ऐसा न पहले कभी हुआ और न भविष्य में होगा। मैं उस समय की राजसभा (राजपरिषद) का चेयरमैन था। महाराज ने ससंद नामजद की थी। मातृका प्रसाद पोइराला के कहने पर मुझे तथा शख लियाकत को तराई से उसमें नामजद किया। इस बीच तराई कांग्रेस का गठन हो गया। मेरे बड़े भाई कुलानन्द झा उसके अध्यक्ष थ। मैं राजसभा का सभापति था। मैंने उस समय राजा के पक्ष में

बहुत कछ किया। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ राजा को भड़काया, परन्तु राजा मेरा भाषण राजसभा में बराबर सुनते थ। उन्होंन लोगों के विरोध के बावजूद मुझे भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त कर दिया। मेरे लिये यह एक चुनौती भरा काम था। परन्तु भगवान की कृपा से सब ठीक–ठाक रहा। मैंने भारत–नेपाल सम्बन्ध खराब होने के बावजूद भारत से नेपाल के लिये बहुत कुछ हासिल किया। नेपाल के वर्तमान नताओं को भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत से सम्बन्ध अच्छा रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

श्री हिरण्य लाल श्रेष्ठ

नेपाल के प्रसिद्ध वामपंथी नेता श्री हिरण्य लाल श्रेष्ठ नेपाल की राजनीति के जाने माने व्यक्तित्व हैं। प्रखर प्रतिभा और स्पष्टवादिता के धनी हिरण्य लाल अक्सर भारत–नेपाल संबंधों पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। एशिया के देशों के परस्पर संबंधों की उनकी अपनी व्याख्या है। उनकी पार्टी –कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माले का पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–एमाले में विलय हो गया। पहले भी ये दोनों पाटियां एक थीं। परन्तु भारत–नेपाल के बीच महाकाली संधि हो जाने के माले के नेता संधि का विरोध करते हुये अलग हो गये। महाकाली संधि में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है परन्तु माले के नेता विरोध भुलाकर एक हो गये हैं। महाकाली संधि अब भी विवादास्पद बनी हुई है। नेपाली संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया है। परन्तु कुछ लोगों को अब भी लगता है कि यह संधि वास्तविक अर्थो में लागू नहीं होगी। अतः मैने अपनी बातचीत का प्रारम्भ यहीं से किया। श्री हिरण्य लाल श्रेष्ठ ने इस पर कहा कि– संसद ने इस संधि का अनुमोदन कर दिया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि इसे लागू करने में देरी क्यों? मुझे लगता है कि परियोजना के अंतर्गत बांध किस स्थल पर बनाया जाय इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। नेपाल चाहता है कि बांध रूपाली घाट पर बने जबकि भारत जोर दे रहा है कि इसका निर्माण पूर्णागिरि में होना चाहिये। मैने दोनों ही स्थानों का स्वयं निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि पूर्णागिरि पर बांध बनने से नेपाल का बहुत बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा। अतः भारत को इस पर सोचना चाहिये। जो गलती कोसी परियोजना के समय हो गयी उसे दोहराया नहीं जाना चाहिऐ। नेपाल के जल अधिकार की रक्षा होनी चाहिये। नेपाल की प्राथमिकता ऊर्जा उत्पादन है जबकि भारत की प्राथमिकता सिंचाई है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि नेपाल बिजली का उत्पादन करें और अतिरिक्त बिजली भारत तथा दूसरे पड़ोसी देशों को निर्यात कर सकें। नेपाल बांगलादेश को बिजली बेच सकता है, बदले में वहां से गैस ले सकता है। भारत से कोयला मंगा सकता है।

मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस क्षेत्र के देश यह महसूस करेंगे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग होना चाहिये। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव समाप्त नहीं हो जाता है मेरा सुझाव है कि तब तक भारत–नेपाल–बांग्लादेश–भूटान का उपक्षेत्रीय सहयोग हो सकता है।

इस क्षेत्र की नदियों के बारे में एक व्यापक सहमति की आवश्कयता है। इस क्षेत्र मं दो तरह की नदियां हैं–पहली प्रकार की वे नदिययां हैं जो दो देशों के बीच बहती हैं, जैसे महाकाली और मेची। दूसरे तरह की वे नदियां हैं जो कई देशों से होकर गुजरती हैं जैसे ब्रहापुत्र और गंगा। इसके संबंध में द्विपक्षीय और व्यापक सहमति बनायी जानी चाहिये।

मैं महाकाली संधि के खिलाफ नहीं हूँ। परन्तु इसके कुछ प्रावाधानों को स्पष्ट किया जाना चाहिये। ऊर्जा उत्पादन नेपाल द्वारा ही किया जाना चाहिए। विद्युत उत्पादन और विद्युत व्यापार को अलग–अलग करना चाहिये। विद्युत बेचने का अधिकार नेपाल को होना चाहिए। हमें सार्क क्षत्रीय ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने

की संभावना पर भी विचार करना चाहिये ताकि नेपाल की अतिरिक्त बिजली इस क्षेत्र के अन्य देशों को भी मिल सकें।

वर्ष 1950 की भारत–नेपाल संधि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर वामपंथी दल भारत की कड़ी आलोचना करते हैं। इस संधि के बारे में पूछे जाने पर श्री हिरण्य लाल श्रेष्ठ ने कहा – भारत और नेपाल के सम्बन्ध इसी संधि से परिचालित होते हैं। यह एक 'अम्ब्रेला–ट्रटी' है। राणा प्रधानमंत्रियों ने जब अपना शासन खतरे में महसूस किया तो उन्होंने भारत के साथ यह संधि की। उसके बाद बहुत परिवर्तन हो गया। है। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को भारत के सुरक्षा कवच के अंतर्गत रखने का जो प्रावधान है वह हमें पसन्द नहीं। दूसरी बात इसमें यह भी कहा गया है कि नेपाली और भारतीय नागरिकों के बार साथ दोनों देशों में समान व्यवहार होगा। हालांकि नेपाली नागरिकों के बारे में भी कहा गया है कि उन्हें भारत में वहां के नागरकों के समान व्यवहार मिलेगा, परन्तु नेपाल एक छोटा मुल्क है, गरीब है, अगर भारतीय नागरिक यहां आकर बसने लगे तो नेपाल का अस्तित्व खतरें में पड़ जायेगा। जबकि भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर समूचा नेपाल भारत में जाकर बस जाय तब भी भारत का कुछ नहीं होगा। वह समुद्र में एक पानी की बूंद के समान होगा। अतः दोनों देशों के बीच पंचशील के सिद्धांत पर आधारित शांति और सहयेाग की नयी संधि होनी चाहिये।

यह पूछे जाने पर कि अगर भारतीयों को नेपाल में आने से रांका जायेगा तो उन लाखों नेपालियों का क्या होगा जो भारत में रहकर काम कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ भावना नहीं भड़क सकती है। श्रीश्रेष्ट ने कहा कि भारतीयों का नेपाल में पर्यटक और तीर्थयात्री के रूप में बार–बार स्वागत है। परन्तु उन्हें यहां स्थायी रूप से बसने की इजाजत नहीं दी जा सकती और रही बात उन नेपालियों की जो वहां जाकर नौकरी करते हैं तो जब तक उनकी वहां जरूरत महसूस होगी वे वहां रहेंगे नहीं तो वापस आ जायेंगे।

इसी से जुड़ी एक अन्य बात है–नेपाली नागरिकता की। हम तराई में रहने वाले मधेशियों को कभी विदेशी नहीं मानते। हमं जनक और भगवान बुद्ध पर गर्व है। यह कहना गलत है कि नेपालियों को नागरिकता नहीं दी गयी है। सच्चाई यह है कि जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उन्होंने कभी इसके लिये प्रयास नहीं किया। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उनमें मधेशी है, पहाड़ी भी है तथा पहाड़ा पर रहने वाले बहुत सारे आदिवासी भी हैं। नेपाल की नागरिकता समस्या का भारत के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह नेपाल का आन्तरिक मामला है। मैं समझता हूँ कि भारत जैसा मित्र देश इससे अपने को दूर ही रखेगा। किसी भी नेपाली को नागरिकता प्रमाण पत्र देने से इंकार नहीं किया गया है। जिन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला है वे विदेशी नहीं है। इस समस्या का समाधान के लिये सरकार को एक नया विधेयक लाना चाहिये।

यह पूछे जाने पर कि नेपाल में कभी–कभी भारत विरोधी भावना क्यों भड़क उठती है? श्री श्रेष्ठ ने कहा कि यह तो भारत को सोचना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। कोई भी पसंद नहीं करेगा। भारत को बड़ी बहन की तरह व्यवहार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि कभी–कभी भारतीय व्यापारी नेपाल में अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इससे कठुता बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि कई बार भारत की राज्य सरकारें नेपाली

वस्तुओं पर स्थानीय कर लगा देती हैं जिससे नेपाल का व्यापार प्रभावित होता है। जैसा पश्चिमी बंगाल की सरकार ने नेपाली चाय के आयात पर लक्जरी टैक्स लगा दिया। गुजराल डाक्ट्रीन के द्वारा भारत नेअपने पड़ोसियों को जो कुछ दिया वह धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है।

नेपाल कभी भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है। परन्तु हम भारत के बिग ब्रदरली हेजीमोनिस्टिक और मोनोपालिस्टिक रवैया का बराबर विरोध करेंगे। हम भारत के साथ करेक्ट और कार्डियल संबंध चाहते हैं।

नेपाल अन्य सभी देशों के साथ भी द्विपक्षीय संबंध विकसित करना चाहता है। इसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। नेपाल इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि इसकी जमीन का इस्तेमाल इसके पड़ोसियों के खिफ नहीं होने दिया जायेगा।

खुली सीमा के बारे में उन्होंने कहा कि हम भारत–नेपाल सीमा की सील करने के पक्ष में नहीं हैं, परन्तु इसे ठीक से नियमित और नियंत्रित करने की जरूरत है। आरम्भ में दोनों देशों से आने–जाने वालो के लिये परिचय पत्र की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिये। बाद में पासपोर्ट भी लागू किया जा सकता है। नेपाल में माओवादी खुली सीमा का लाभ उठा रहे हैं। अतः सीमा पर गैर कानूनी गतिविधियों जैसे हथियारों तथा मादक पदार्थो की तस्करी, लड़कियों को फुसलाकर ले जाने जैसे कार्यो पर निगरानी रखी जानी चाहिये।

भरत–नेपाल का भविष्य उज्ज्वल है। मैं आशावादी हूँ। भारत का नेपाल को शांत क्षेत्र घाषित करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दे देनी चाहिये। एक बात और नेपाल में चाहे जैसी राजनीतिक व्यवस्था हो भारत के साथ उसके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चूंकि किसी देश को पोलिटिकल सिस्टम वहां का अंदरूनी मामला होता है।

श्री उद्धव दत्त भट्ट

श्री उद्धव दत्त भट्ट अपनी स्पष्टवादिता के लिये एक जाने–माने राजनयिक है। वयोवृद्ध राजनेता, विद्वान वक्ता और दूर–दृष्टि वाले श्री भट्ट भारत में उस समय राजनियक थे जब भारत–नेपाल संबंध नई करवटें ले रहा था। कई मुद्दों पर उनके दृढ़ विचार हैं जिनसे सहमत होना कोई जरूरी नहीं, किन्तु भारत–नेपाल संबंधों की व्याख्या करने में उनके विचारों का बड़ा महत्व है। उनकी भाषा शैली अनूठी है। उनका व्यवहार निराला है। मैंने जब उनसे इंटरव्यू का प्रस्ताव रखा तो उन्होंन फोन पर मुझसे कहा कि क्या किताब लिखनी है? भारत–नेपाल संबंध पर दर्जनों किताब लिखी जा चुकी हैं एक और किताब से क्या होगा? इसके बावजूद उन्होंने मुझे समय दिया। इत्मीनान से बात की। उनसे वार्ता करने के बाद ऐसा लगा कि दोनों देशों के संबधों के बारे में उन्होंने ऐसी बातें बताई जो किसी पुस्तक में कदाचित् नहीं मिलेगी। बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक ढंग से हुई। अतः ये सच्चाई के करीब प्रतीत होती है। प्रस्तुत है भारत–नेपाल संबंधों पर उनसे हुई बातचीत के अंश–

नेपाल और भारत दोनों देशो के नेता और बुद्धिजीवी कहते रहते हैं कि हमारा इतिहास चार हजार साल पुराना है। अगर इतना पुराना इतिहास है तो अभी समस्याएं क्यों हैं? मेरी नज़र में समस्यायें हैं, आप की नजर में भले ही न हों। अभी भी समस्याएं हैं। कालापानी की समस्या है, जल स्रोतों की समस्या है। उसके बारे में हमने कोई संतोषजनक हल निकाला है? मेरे ख्याल से तो कोई भी समाधान नहीं है। देखिये जिनते भी समझौते दोनों देशों के बीच हुये हैं, कोसी हो, गंडक हो, या महाकाली हो– सब विवादास्पद हैं, और सब बड़े आदमियों ने किया है। मेरा कहना है कि क्यों ऐसी चीजें की जायें जो बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिये समस्या रहे तथा ये चीजें विवादास्पद बनीं रहें। क्यों नहीं पहले से ही या सोचा जाय कि चलो भाई नेपाल को कुछ और देना है, और दे दिया जाय।

भारत ने नेपाल के लिये बहुत कुछ किया है। हर एक टाइम में मदद किया है। फिजिकल मदद किया है।

असल बात यह है कि दक्षिण एशिया उप–महाद्वोप में राजनीति की आधुनिक व्यवस्था वर्ष 1950 से शुरू हुई। दक्षिण एशिया से अंग्रेज जब गये तो उन्होंने एक नयी राज्य व्यवस्था खड़ी की। अभी तक नई परिस्थिति में इस क्षेत्र के देश इसमें अपने को एडजस्ट नहीं कर पाये हैं और मुझे आशा है कि यह कभी नहीं होगा।

नेपाल के डिप्लोमेट्स के बारे में क्या कहा जाय? कल एक जगह गया था। नेपाली लोग बड़ी जल्दी हर समस्या का समाधान बता देते हैं। कश्मीर के बारे में कह रहे थे कि इंडिया को अपने अधिकार वाला कश्मीर छोड़ देना चाहिये। वे यह भी नहीं मानते कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर रखा है। इस प्रकार की पूर्वाग्रह पूर्व धारणा से कहीं डिप्लोमेसी चलती है? हार्ड रियालिटी यह है कि जहां पर हैं, वहीं पर रहेंगें। यह मेरी अपनी दृष्टि है। अगर वह लाइन चेंज होगी तो कई तरह की समस्यायें खड़ी होगी।

तो मरा कहना है कि नेपाल और भारत का वर्तमान रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। सन पचास के बाद नेपाल ने दुनिया के अन्य देशों से जो संबंध बनाया उससे दोनों देशों को फायदा हुआ है। नेपाल के विदेशी सम्बन्धों का विस्तार नेपाल–भारत दोस्ती की कीमत पर नहीं हुआ है।

दोनों देशों के बीच जैसा कि आपने कहा 'अनक्वेल ट्रीटी' ;न्दम्नंस ज्तमंजलद्ध कैसे हो गयी? यह पूछे जाने पर श्री भट्ट ने कहा कि जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वे समझते हैं कि भारत ने ठग लिया है। मेरे ख्याल से इन संधियों में सुधार की ग्जाइश है। अगर भारत थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा दिखाये तो बात बन सकती है।

मैं आपको बताऊं जब नेपाल में नेपाली कांग्रेस द्वारा प्रजातंत्र के लिये आंदोलन चलाया जा रहा था तो वे लोग भारत में छिपे रहते थे। धीरे से वहां से आते थे और यहां बम फेंक कर चले जाते थ। मैं उन दिनों दिल्ली में ही था।

.....ठीक है। भारत में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। नेपाल के एक नेता थे, वे भारत में खुले आम हथियार के साथ ट्रेन में पकड़े गये। नेपाल ने जब उनके बारे में पूछा तो भारत ने कहा कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। हम कुछ नहीं कर सकते। नियमानुसार ही कार्रवाई हो सकती है। मैं कहता हूँ कि नेपाल और भारत क सम्बन्ध इस प्रकार के हैं कि दोनों देशों मे हो रही घटनाओं को आंतरिक मामला कह रक छुट्टी नहीं पाई जा सकती है। यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान दोनों देशों की जनता के बीच है।

माओवादी समस्या को ही लें। भारत जो कुछ कर रहा है, वह काफी नहीं हैं भारत को और कुछ करना चाहिये। हम बातें तो बड़ी मीठी–मीठी करते हैं परन्त, ठोस काम नहीं करते हैं। नेपाल में कुछ लोग शंका करते हैं कि माओवादियों ने भारत में शरण ले रखी है। एक तरफ तो भारत माओवादियों के खिलाफ नेपाद की मदद भी कर रहा है और दूसरी तरफ उनको भारत में ही शरण मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत–नेपाल सम्बन्धों में सुधार हो रहा है? श्री भट्ट ने कहा कि – देखिये भारत नेपाल के बीच थोड़े समय के लिये मनमुटाव हो सकता है, परन्तु दोनों फिर एक साथ रहने के लिये मजबूर हैं।

भारत और नेपाल के बीच अभी जो व्यापार संधि हुई है, उसमें भारत की संकीर्णता झलकती हैं..... यही संधि मोरार जी भाई के समय हुई थीं उस समय भी ब्यूरोकेट्स अपने ढंग से इसमें अड़ंगे लगा रहे थे, परन्तु मोरार जो भाई ने दृढ़ता से कहा कि इसमें सोचना की क्या बात है? जब नेपाल को देना है तो दे दो जितना वह मांगता है। इस प्रकार की उदारता अब भारत की आर नहीं दिखाई जाती।

श्रो भट्ट वर्ष 1950 की भारत–नेपाल संधि में संशाधन के वास्ते सुझाव देने के लिये गठित समिति के सदस्य भी हैं। इस संधि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि– भारत के तत्कालीन विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल आये थे। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से पूछा– क्या सन 1950 की संधि वैलिड है या समाप्त हो गयी है?..... बताइये हमारे मंत्री ने क्या कहा होगा.....। उसने कहा हां वैलिड ;टसपकद्ध है।

इस संधि से हम दोनों लाभ उठा रहे हैं। यहां तक कि माओवादी भी उसका लाभ ले रहे हैं। घायल होने पर वे भी बेधड़क भारत जाकर इलाज करवा लेते हैं।

दशों के बोच खुली सीमा होने के कारण कुछ समस्यायें अवश्य पैदा हो जाती है परन्तु कुल मिलाकर इससे दोनों देशों को सहूलियत है। एक बार नेपाल के कुछ राजनीतिज्ञों ने कहा कि सन पचास की संधि खत्म कर देनी चाहिये तो किसी ने तपाक से कहा कि अगर यह संधि खत्म हो जायेगी तो नेपाल के नेतागण भारत के खिलाफ कौन सा मुद्दा लेकर आंदोलन करेंगे। .....तो होना जाना कुछ नहीं है। संधि है और रहेगी।

खुलो सीमा को हम बंद नहीं करते। हां इसे अच्दी तरह मैनेज ;डंदंहमद्ध करने की जरूरत है। सीमा शुल्क केन्द्रों को बेहतर बनाकर अमेरिका और कनाडा की तर्ज पर हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पूरी सीमा पर पेट्रोलिग ;च्ंजतवससपदहद्ध चुस्त और दुस्त होनी चाहिये। स्थानीय स्तर की समस्याओं का तुरन्त वहीं समाधान हो जाना चाहिये।

नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने अभी हाल ही में वर्षो पुराने प्रस्ताव की चर्चा की है कि नेपाल को शाति का क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये। दुनिया के अनेक देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। सोवियत रूस और भारत ने इस पर अपनी असहमति जताई थी। उस समय ऐसा लगता था कि नेपाल ने यह प्रस्ताव अमेरिका के इशारे पर पेश किया है। इसके बारे में पूछे जाने पर श्री भट्ट ने कहा कि विचार कभी पुराने नहीं होते है। कभी लोगा को होश आयेगा–लोग समझेंगे यह प्रस्ताव ठीक है। भारत को इसका समर्थन करना चहिये। मै तो संसद में कहा था। .....मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि नेपाल के इस प्रस्ताव के पीछे चीन या अमेरिका का हाथ है। .....हां। अब नेपाल में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या कर लेगें आप? यह और बढ़ने वाला है। इससे नेपाल और चीन को नहीं भारत को ही नुकसान होगा। ऐसी स्थिति क्यों आये कि नेपाल का काई नुकसान हो। इसलिये तो मैं कहता हॅू कि भारत को नेपाल में माओवादी समस्या क समाधान के लिये और करना चहिये।

मैं इस पक्ष में नहीं नेपाल में कोई विदेशी सेना आये..... इसमें कोई बुराई नहीं कि हम स्वीकार करें कि भारत से हमारी दोस्ती है।

श्री भट्ट इस प्रश्न को टाल गये कि नेपाली नेता खुले आम यह बात कहने से हिचकिचाते ह कि भारत नेपाल का दोस्त है। आज भी भारत जो सैनिक सहायता दे रहा है, छुप–छुप कर ही दे रहा है।

यह पूछे जाने पर कि नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र है और भारत की अधिसंख्य जनता भी हिन्दू है। परन्तु दानों देशों के हिन्दुओं में कोई भवानात्मक एकता देखनें में क्यों नहीं मिलती है? इस पर श्री भट्ट ने कहा कि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये । हमारे यहां हिन्दू राज्य क्यों हुआ। कहीं हिन्दू राज्य नहीं लिखा है। हमारे राजा हिन्दू है। अतः नेपाल हिन्दू राज्य है। दोनो देशों के हिन्दुआ के बीच एकजुटता से क्या फायदा होगा।

श्री लीलामणि पोखरेल

श्री लीलामणि पोरखरेल जिनका जन्म प्यूठान जिले के एक सुदूरवर्ती गांव में हुआ, सिन्धुली जिला से चुनाव लड़ते हैं। उनकी पार्टी संयुक्त जनमोर्चा के सदस्यों की संख्या संसद में भले ही कम हो, परन्तु नेपाल की समस्याओं के बारे में उनकी पार्टी की नीतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्व0 श्री वामदेव उपाध्याय के पुत्र लीलामणि पोखरेल की धर्मपत्नी श्रीमती शशि श्रेष्ठ भी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। एम.ए., बी.एड. तक की उच्च शिक्षा प्राप्त कर राजनीति, पत्रकारिता और समाजसेवा से जुड़े लीलामणि, नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी तेज तर्रार व्यक्तित्व और उनकी प्रखर बुद्धि अक्सर उन्हें विवादास्पद बना देती है। वे निर्भीक और स्पष्टवादी विचारक हैं। इसी वजह से वे ऊपर से अत्यन्त कठोर और असहज दिखाई देते हैं। भारत सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करने के कारण उन्हें अक्सर गलत भी समझ लिया जाता है। परन्तु काठमांडू के कोटेश्वर स्थित उनके कार्यालय में उनसे बातचीत करने के बाद मुझे यह मानने में कोई हिचक नहीं होती कि लीलामणि जी भारतीय जनता के सच्चे हितषी हैं। दरअसल लीलामणि जी नेपाल के हितों के प्रबल समर्थक हैं। वे किसी भी कीमत पर नेपाली जनता के हितों के खिलाफ किसी से भी कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसी भावना की अभिव्यक्ति उन्हें कभी कभी भारत विरोधी नेता के रूप में उभार कर प्रस्तुत करती है जो कदाचित ठीक प्रतीत नहीं होता। भारत–नेपाल सम्बन्धों के बारे में पूछने पर वे कहते हैं कि दोनों देश एक साथ रहने के लिये मजबूर हं। क्योंकि मित्र बदले जा सकते हैं पड़ोसी नहीं। मुझको तकलीफ तब होती है जब भारत सरकार के अधिकारी नेपाल के साथ दादागिरी दिखते हैं। उनके अनुसार नेपाल एक छोटा देश है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि भारत उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। लीलामणि जो का यह भी ख्याल है कि भारत ने नेपाल के साथ जो संधियां की हैं उनमें नेपाल को छला गया है। कोसी और गंडक परियोजनाओं से सम्बन्धित द्विपक्षीय संधियों का उल्लेख करते हुये लीलामणि जी कहते हैं कि इन परियोजनाओं से भारत को तो बहुत लाभ हुआ है किन्तु नेपाल को उतना लाभ नहीं हुआ। उनका यह भी विचार है कि वर्ष 1950 की भारत–नेपाल संधि को रद्द कर देना चाहिये। क्योंकि इससे नेपाल की प्रभुसत्ता पर आंच आती है। लीलामणि जी की यह स्पष्ट धारणा है कि –माओवादियो से हर हालत में बातचीत होनी चाहिये। उनके खिलाफ दमन की सैनिक कार्यवाही उचित नहीं है। उनका यह भी सोचना है कि माओवदियों के खिलाफ भारत द्वारा सैनिक सहायता देना ठीक नहीं है। माओवाद नेपाल की आंतरिक समस्या है और इसे नेपाल स्वयं सुलझा लेगा इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं।

एक प्रश्न के उत्तर मं श्री पोखरेल ने कहा कि नेपाल में भारत विरोधी कार्रवाई कहीं नहीं है, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वे नेपाल को बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं नेपाल की घटनाओं के बारे में भारतीय मीडिया में जैसा चित्रण किया जाता है लीलामणि जी को उससे भी सख्त ऐतराज है। लगभग तीन घंटे की बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने देश

नेपाल के प्रबल समर्थक होने के साथ–साथ वे भारत के एक अच्छे मित्र और प्रशंसक ही है और कुछ नहीं।

श्री अरूण सुवेदी

नेपाल में भी एक शिव सेना है, किन्तु भारत की शिव सेना से इसका कोई मतलब नहीं। नेपाल की शिव सेना के अध्यक्ष श्री अरूण सुवेदी एक दमदार व्यक्ति हैं। वे एक प्रखर हिन्दूवादी नेता होने के साथ–साथ निर्भीक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अभी पिछले दिनों भारत के अमरनाथ मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गयी थी। भारत में इसके खिलाफ हिन्दूवादी संगठनों ने तो कुछ खास नहीं किया, परन्तु काठमांडू में नेपाल की शिवसेना ने पाकिस्तानी दूतावास के सामने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और मारे गये तीर्थयात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को। श्री अरूण सुवेदी का यह दुढ़ विश्वास है कि नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विचार है कि नेपाल में अधिक से अधिक पाकिस्तान का एक वाणिज्यिक दूतावास ही काफी होगा। सुवेदो जी ने कहा कि नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा भारत विरोधी कार्यो के लिये किया जाता है। अतः पाकिस्तानी दूतावास बंद कर देना चाहिये।

भारत–नेपाल संबंधों के बारे में पूछे जाने पर श्री सुवेदी ने कहा कि नेपाल में कोई विशेष भारत विरोधी भावना नहीं है। अलबत्ता काठमांडू में कुछ लोग पाकिस्तान के बहकावे पर भारत विरोधी कार्यवाही जरूर करते हैं। उन्होनें कहा कि– नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भारत के प्रबल समर्थक है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि यदि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नेपाल में भारत विरोधी तत्वों को इसी तरह काम करने की छूट मिलती रही तो धीरे–धीरे देहातों में भी लोग भारत के खिलाफ हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यही समय है कि जब भारतीय दूतावास को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये। उन्होंने कहा कि नेपाल के बुद्धिजीवी ही नहीं अपितु ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ही बराबर सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत नपाल सीमा पर बढ़ती हुयी मस्जिदों और मदरसों की संख्या नेपाल में मुसलमानों की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरियां भी इधर बहुत सक्रिय हो गयी हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि विश्व के एकमात्र हिन्दू देश नेपाल को गैर हिन्दू देश बनाने की साजिश के अंतर्गत यह सब किया जा रहा है। श्री अरूण सुवेदी ने कहा कि वसे भारत और नेपाल की जनता को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। परन्तु दोनों देशों के जिम्मेदार लोगों के बीच अगर समझदारी की भावना बनी रहे तो भारत–नेपाल सम्बन्ध दुनिया क लिये भी मिसाल हो सकत हैं। दोना देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के वास्ते उनके मन में कई योजनाये हैं जिन्हं वे मूर्तरूप देने के लिये अपने स्तर पर वे बराबर प्रयासरत हैं। हाल ही में उन्होंने काठमांडू घाटी से लगी एक पहाड़ी पर भगवान शिव का प्रतीक त्रिशूल सस्थापित किया जो दुनिया का सबसे ऊंचा त्रिशूल हो सकता है।

———————

भारत–नेपाल संबंधों के बारे में दिनांक 7 फरवरी, 2002 को काठमांडू में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किये गये। नेपाल फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडीज के कार्यवाही निदेशक श्री आनन्द श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल की विदेश नीति केवल भारत पर आश्रित नहीं रहनी चाहिये, दूसरे विकल्पों की भी तलाश की जानी चाहिये। इनमें चीन एक है। नेपाल को अपने दक्षिण के पड़ोसी देश भारत के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करना चहिये, किन्तु वही अंतिम लक्ष्य नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। भारत और नेपाल के संबंध केवल जुबानी नहीं होना चाहिये, बल्कि व्यवहारिक होना चाहिये। भारत और नेपाल को द्विपक्षीय मुद्दों विशेषकर जल संसाधन से संबंधित मुद्दों को संतोषजनक ढंग से हल करना चहिये। आनन्द श्रेष्ठ ने कहा कि अगर भारत चाहे तो भूटान शरणार्थी समस्या का समाधान करा सकता है जो दोनों देशों के संबंधों के बीच एक कटुता पैदा करने वाला मुद्दा है। कालापानी की समस्या और भारत में मनमाने ढंग से बनाये जा रहे बांधों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान तुरन्त होना चाहिये। उन्होंने कहा कि नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली के बाद नेपाली विदेश नीति का झुकाव भारत की आर ज्यादा हुआ है हालांकि शेर बहादुर देअवा की सरकार इस प्रवृत्ति को उलटने का प्रशसनीय कार्य किया। इसी अवसर पर भारत म नपेाल के पूर्व राजदूत डॉ. लोकराज बराल ने कहा कि यह सोचना गलत है कि नेपाल की विदेश नीति का झुकाव भारत की ओर है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में दोनों देशों के बोच खुलापन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों से संबंधित मद्दे कतई स्वाभाविक है। परन्तु उम्मीद है कि इनका समाधान निकल आयेगा। उन्होंने भी यह आशा व्यक्त की कि अगर भारत प्रयास करें तो भूटान शरणार्थी समस्या का हल जल्द निकल आयेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा से संबधित विवादों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिये, क्योंकि धीरे–धीरे इनका समाधान निकाल जायेगा। डॉक्टर बराल ने विश्वास व्यक्त किया कि चाहे जो भी समस्याएं है नपाल–भारत के रिश्तों में कभी खटास नहीं पैदा होगी।

भारत नेपाल के संबंध चाहे जितने प्राचीन और परम्परागत हो, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृटि से वे चाहे जितने निकट हो परन्तु वास्तविकता यह है कि वर्तमान में नेपाल एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व बिरादरी में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका है। नेपाल स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहता ह। जब तक हम इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे, भारत नेपाल संबंधों में यदा–कदा कडुवाहट पैदा होती रहेगी और कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों देशों के बीच दरार भी पड़ जाय। यदि दरार पड़ी तो कालान्तर में कदाचित इस दरार को पाटा जाना मुश्किल भी हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिन नेपाल की आर्थिक निभर्रता कम हो जायेगी उसी दिन से दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो जायेगा। नेपाल की उत्तरी सीमा शनैः शनैः खुल रही है। उस पार तिब्बत से चीन ने रेलवे लाइन का निमाण कर लिया है। इस परियोजना के पूरी तरह कार्यरूप लेने के बाद नेपाल में गंगा दक्षिण से उत्तर की चीन की ओर बहने लगी तो कोई आश्चर्य नहीं।

अध्याय–2
भारत–चीन के बीच

नेपाल तीन तरफ भारत से तथा उत्तर की ओर तिब्बत (चीन) स घिरा भूपरिवेष्टित (लैंड लाक्ड) देश है। उत्तरो सोमा दुर्गम पहाड़ों से घिरी होने के कारण नेपाल की निर्भरता भारत पर अधिक ह। वैसे भी नेपाल और भारत के संबंध सदियों से बहुत घनिष्ठ है। इस संबंध की तुलना चीन से नहीं की जा सकती है। परन्तु सन पचास के बाद नेपाल के नीति नियामकों का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वे दोनों देशों के साथ अपने सबंधों में संतुलन बनाये रखें। नेपल की उत्तरी सीमा भी धीरे–धीरे खुल रही है जबकि भारत–नेपाल सीमा पर जो अब तक खुली है नियंत्रण बढ़ रहा है। अगर भविष्य में यह सीमा बिल्कुल बंद हो जाय तो किसी को आश्चर्य नही होना चाहिये। यही प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि भविष्य में भारत–नेपाल के संबंध किस प्रकार के होंगे।

सन पचास के बाद नेपाल की यह कोशिश रही है कि भारत के साथ अपने व्यवहार में चीन की याद दिलाता रहे। हालांकि नेपाल में नेपालो कांग्रेस का बहुमत है परन्तु यदि सभी वामपंथी दलों का जनमत जोड़ दिया जाता है तो वह नेपाली कांग्रेस से कहीं अधिक है। नेपाल में राजशाही के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है। परन्तु साथ ही जनता का बहुमत वामपंथी दलों के साथ है।

नेपाल के वामपंथी दलों का भारत के वामपंथो दलों के साथ कोई खास भावनात्मक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि नेपाल का वामंपथी आंदोलन पूर्णतः नेपाली है। ज्यादा से ज्यादा वे चीन से प्रेरणा ले सकते हैं जबकि भारत का वामपंथी आंदोलन अंतरराष्टोय वामपंथी आंदोलन का एक हिस्सा है। इसलिय कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल के वामपंथी आंदोलन का स्रोत 'दरबार' अर्थात नेपाल नरेश है। माओवादियों को छोड़कर नेपाल के सभी वामपंथी दल नेपाल की एकता और उसके विकास के लिये राजशाही (किगशिप) का अनिवार्य मानते हैं। केवल माओवादी ही नेपाल में संवैधानिक मानकों को समाप्त कर पूर्ण गणतंत्र की स्थापना के लिये जनयुद्ध छेड़े हुये हैं।

हालांकि वे भो देउबा सरकार के साथ हुई वार्ताओं के दौरान इस मांग को छोड़ने के लिये तैयार हो गये थे।

एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा कि जैसे अगर किसी आदमो को बदनाम करना हो यह कहा जाता है कि उसे एडस की बीमारी हो गयी है। उसी तरह नेपाल में किसी को बदनाम करना हो तो यह कहना ही काफी कि वह भारत समर्थक या प्रो–इंडिया है। आज नेपाली कांग्रेस के सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला के संबंध में भी इसी तरह का प्रचार किया जा रहा है क्योंकि वे नेपाल में आपातकाल की घोषणा के बाद लगातार आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि नेपाल में प्रजातंत्र को खतरा है।

नेपाल के नीति नियामकों के मन में भारत के प्रति आशंका की भावना बराबर रहती है। इसमें काई संदेह नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत नेपाल को अपने में मिला लेगा और नेपाल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। संभवतः

इसलिये यदाकदा नेपाल में भारत विरोधी भावना भड़का दी जाती है ताकि लोग भ्ल न जाय। इसका लाभ पाकिस्तान हमेशा लेने का प्रयत्न करता है।

दिनांक 5 जून, 2000 को इंडिया टुडे में 'नेपाल गेम प्लान' नामक एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। पाकिस्तान नेपाल के भारत विरोधी संगठनों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों विशेषकर चरम वामपंथी और चरम दक्षिणपंथी दलों की मदद से भारत और नेपाल की जनता के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान नेपाली मीडिया के एक वर्ग के सहयोग से भारत विरोधी प्रचार भी कराता है। पाकिस्तान भारत–नेपाल सीमा पर मुस्लिम संगठनों की सहायता से भारत विरोधी कार्यवाही कराता है, इत्यादि। इस रिपोर्ट की नेपाल में भारत प्रतिक्रिया हुई। प्रेक्षकों का कहना है इस रिपोर्ट के प्रकाशन से नेपाल में जिनती भारती विरोधी भावना भड़की उतनी भारत विराधेी भावना पाकिस्तान के समूचे प्रयास से भी नहीं पैदा हुई होगी। रिपोर्ट में कई तथ्यों को मिलाकर घालमेल कर दिया गया है। इसमें काई संदेह नहीं कि पाकिस्तान अपने दूतावास के माध्यम से नेपाल की भूमि से भारत विरोधी कार्यवाही कराता है जिसके सबूत नेपाल सरकार के पास है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि नपेाल तस्करों का गढ़ है। परन्तु तस्करी और भारत विरोध मं अंतर है। तस्करी एक आर्थिक अपराध है जिससे इनडाइरेक्टली (प्रकारान्तर से) भारत की अर्थ–व्यवस्था को नुकसान होता है। परन्तु इसके पीछे भारत विरोधी भावना है, ऐसा कहना उचित नहीं। इंडिया गेम प्लान रिपोर्ट में ऐसे लोगों का नाम दिया गया जिनके बारे में ऐसा कहना कि वे पाकिस्तान के एजेंट हैं कतई उचित नहीं होगा। रिपोर्ट में नेपाल के कई प्रतिष्ठित लोगों का नाम था। इसका नेपाल के जमानस पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसका प्रभाव भारत–नेपाल सम्बन्धो पर भी पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री के सलाहकार ब्रजश मिश्र ने जो उन दिनों काठमांडू में थे, इस रिपोर्ट से अनभिज्ञता जताई और कहा कि इससे भारत सरकार का कोई लना–देना नहीं है। परन्तु भारत सरकार के खंडन मात्र से उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती जो इडिया टुडे की रिपोर्ट ने की थी। इंडिया टुडे की रिपोट में इस बात का भी उल्लेख है कि काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कमचाारी तथाकथित वृहत्तर नेपाल अभियान के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर रखा है। कि वर्ष 1816 की सुगौली संधि के अंतर्गत नेपाल ने अपने देश का जो भू–भाग भारत का दिया था उसे वापस किया जाना चाहिये। इस संबंध में बड़ी दिलचस्प मजाकिया घटना की याद आ रही है। एक स्थान पर पत्रकारों के साथ यूं ही गपशप हो रही थो,
किसो न सगौलो की संधि का जिक्र किया तो एक पत्रकार ने कहा कि अब उन इलाकों को भारत में ही रहने देना चहिये कि ये इलाके अगर फिर से नेपाल में आये तो नेपाल का प्रधानमंत्री कोइराला, देउबा और माधव नेपाल कभी नहीं हो सकगे, क्योंकि तब लालू यादव, राबड़ी देवी, मायावती और मुलायम सिंह यादव ही नेपाल के प्रधानमंत्री होगें, क्योंकि तब नेपाल में तब मधेशियों की संख्या पहाड़ियों के मुकाबले जो अभी आधी है, आठ गुनी हो जायेगी।

काठमांडू पोस्ट के दिनाक 06.09.2001 के अंक मे प्रत्यूष आंटा के लेख में कहा गया है कि भारत नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. का

जो मामला उठाता है, वह कश्मीर में उसकी हताशा का प्रतीक है। भारत सरकार पाकिस्तान से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने के बजाये आसानी से आरोप लगाती है कि नेपाल में आई.एस.आई. के लोग सक्रिय हैं। प्रत्यूष ओंटा ने यह भी कहा कि अगर नेपाल में आई.एस.आई. सक्रिय है तो क्या, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भी यहां वहीं काम नहीं कर रही है।

दुनिया भर में खुफिया एजेन्सीज काम करती है, इसमें काइ अनहोनी बात नहीं। पर अभी तक नेपाल में रा का कोई एजेंट आर.डी.एक्स. क साथ नहीं पकड़ा गया, जबकि नेपाल में नपोली पुलिस ने ही पाकिस्तानी दूतावास के कई जिम्मेदार अफसरों को आर.डी.एक्स. साथ गिरफ्तार किया है। आखिर नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी आर.डी.एक्स. क्यों रखते हं। अगर केवल पकड़े गये मामलों के तथ्यों और आंकड़ों पर जायें और किसी प्रकार का अनुमान न लगाये तो भी यह स्पष्ट है कि विभिन्न मौके पर नेपाली पुलिस ने काठमांडू में अब तक पाकिस्तानी नागरिकों से लगभग दो सौ किलोग्राम आर.डी.एक्स बरामद किया है जो काठमांडू घाटी जैस दस शहरों को बरबाद करने के लिये पर्याप्त हैं।

दिनांक 13 अप्रैल, 2001 को काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रथम सचिव मोहम्मद अरशद चीमा के निवास स्थान से सोलह किलोग्राम आर.डी.एक्स. बरामद किया गया। उसी आधार पर नेपाल सरकार ने उन्हें तुरन्त नेपाल छोड़ने का आदेश दिया। कुछ लोगा का ख्याल है कि आर.डी.एक्स. का यह जखीरा नेपाल के माओवादियों को दिया जाना वाला था। आश्चर्य इस बात पर है कि पाकिस्तानी दूतावास ने नेपाल पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी के निवास से आर.डी.एक्स. बरामद करके वियना कन्वेशन का उल्लंघन किया है।

दिनांक 01 जनवरी, 2002 को जब काठमांड में सार्क शिखर सम्मेलन हो रहा था ता पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी सिराज अहमद को नेपाल पुलिस ने भारो संख्या में जाली डालरों और जाली भारतीय रूपयों के साथ पकड़ा। इसके पहले कि उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नेपाल नरोश ज्ञानेन्द्र से बात की और कहा कि सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सिराज अहमद की गिफ्तारी से पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती होगी। बहरहाल उस समय सिराज को छोड़ दिया गया। किन्तु बाद में इस मामले की जांच की गयी और यह पाया गया कि सिराज अहमद दोषी था एवं उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिय। इसके पहले कि कार्रवाई प्रारम्भ हो नेपाली विदेश विभाग के अधिकारियों ने पाकिस्तानी राजदूत को सलाह दी कि सिराज को पाकिस्तान भेज दिया दिया और वह अततः दिनांक 08 फरवरी 2002 को पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस चला गया।

सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान जो कुछ हुआ वह सभी जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। सार्क शिखर सम्मेलन की यह परम्परा है और उसके नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सार्क के मंच से द्विपक्षीय मामले नहीं उठाये जाएंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत–पाकिस्तान का मामला उठाया और नाटकीय अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयो से जाकर हाथ मिलाया। इससे वाजपेयी जी को कितनी विचित्र स्थिति का सामना करना

पड़ा यह सभी जानते हैं। उस समय पत्रकार दीर्घा में उपस्थित कुछ लोगें ने जिस प्रकार तालियों की गड़गड़ाहट से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का हौसला बढ़ाया वह बड़ा अजीब लगा। उसी सम्मेलन में जब भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ के कथन का उत्तर दिया तो दो–एक पत्रकार को छोड़कर किसी ने कोई तवज्जों नहीं दी। होना तो यह चाहिये था कि सार्क के अध्यक्ष नेपला के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को जनरल मुशर्रफ के भाषण के बाद यह कहना चाहिये था कि जनरल मुशर्रफ ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जो कुछ कहा वह कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण ही उस दिन उजागर हुआ जब सम्मेलन के दो–चार दिन बाद उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित वार्ता में स्पष्ट तौर पर कहा कि सार्क सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी और पकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच मुलाकात करा देना नेपाल की उपलब्धि है। जबकि नेपाल को यह अच्छो तरह मालूम था कि भारत सार्क के दौरान भी जनरल मुशर्रफ से किसी प्रकार की भेंट या वार्ता से इंकार करता रहा था, अगर कुछ लोगों ने इस घटना से यह निष्कर्ष निकाला कि नेपाल भारत के मुकाबले पाकिस्तान को बेहतर दोस्त मानता है तो क्या आश्चर्य है? इसी संदर्भ में पसंगवश एक और छोटी सी घटना का उल्लेख करना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सिंह दरबार स्थित अपने कार्यालय में भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये बुलाया। हम लोग उनके कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि दो पाकिस्तानी पत्रकार एक नेपालो पत्रकार के साथ प्रधानमंत्री के कमरे से बहार निकल रहे थे। मरा भ्रम टूट गया।

दिनांक 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र पर हुये आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान तक ने अपने यहां चल रहे मदरसों को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया। नेपाल ने भी देर से ही सही एक आदेश जारी करके उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने का निर्णय लिया। परन्तु आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार के इस निर्णय की नेपाल–मुस्लिम इत्तिहाद संगठन ने जमकर आलोचना। यह वही संगठन है जो नेपाल में कश्मीरी आतंवकादियों को संरक्षण देता है। ऐसा जानकार सूत्रों का कहना है। अमेरिका के विश्वव्यापी आतंक विरोधी अभियान के बाद भारत और नेपाल के गृह सचिवों की बैठक में भी यह फैसला किया गया कि नेपाल अपने यहां मदरसों को गतिविधियों को नियमित करने के लिये कार्रवाई करेगा। काठमांडू स्थित हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता केशव प्रधान ने 01 फरवरी 2002 को लिखा कि नेपाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी अपनी सीमा पर तेजी से बढ़ रहे मदरसों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का फैसला किया है जिनके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से वे खतरनाक हैं। .. ..एक नेपाली अधिकारी ने कहा कि हमने सभो सदस्यों से कहा कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करायें और एक माह के भीतर अपना हिसाब किताब दें।.....

नेपाल में मदरसां की संख्या 500 से ज्यादा है जिनमें अधिकांशतः भारत से लगी तराई क्षेत्र में है। वर्ष 1990 में बहुदलीय प्रजातंत्र लागू होन के बाद नेपाल में गैर हिन्दू संगठनों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया। इसक बाद भारत–नेपाल सीमा के दोनों ओर काफी संख्या में नयी मस्जिदें बनीं है। इस समय नेपाल में

मुसलमानों की सख्या बीस लाख से जयादा है जो पिछले एक दशक में तीन गुनी हो गयी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि इतनी भारी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण के पीछे आई.एस.आई. और खाड़ी के कुछ देशों का हाथ है। एक फरवरी 2002 को काठमांड पोस्ट म कपिलवस्तु में छपी एक रिपोर्ट में मनोज पोडेल ने कहा कि कपिलवस्तु में इस समय चार बड़े रजिस्टर्ड मदरसे हैं और एक सौ से अधिक मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिये आवदन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मदरसों का सऊदी अरब, कतर तथा यू.ए.ई. से अर्थिक सहायता मिलती है। रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के हवाले से कहा गया है कि विदेश से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इन मदरसों मे अच्छे कार्यो के लिये उपयोग नहीं किया जाता है। नेपाल सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में भी मदरसों को संख्या कम नही। परन्तु वहां भी सरकार उनकी जांच पड़ताल नही कर पा रही है वोट की राजनीति के कारण। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भुट्टाचार्य ने कोलकाता में अमेरिकी कार्यालय के पास हुये विस्फोट के बारे में इन मदरसों के बारे में कुछ कहा –दूसरे दिन ही उन्हे माफी मांगनी पड़ो। इन सब बातों से इतना तो निश्चित है कि नेपाल तथा सीमा के उस पार हाल के वर्षो में मुस्लिम शिक्षा के नाम पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं।

दिनाक 13 जनवरी, 2002 को–एशियन ऐज में राहुल दास की एक रिपोट में कहा गया है कि –आई–.एस.आई. नेपाल में इस्लामिक उग्रवंथी संगठनों की मदद कर रहा है। सिलीगुड़ी से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद दिलशाद ने पूरा ब्यौरा दिया कि किस प्रकार आई.एस.आई क एजेंट नेपाल में भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई चलाते हैं।

चीन के प्रधानमंत्री जू रांगजी ने मई–2001 में अपनी काठमांडू यात्रा के दौरान 'स्याब्रूबेसी' और 'रसुआगढ़ी' के बीच सड़क निर्माण करने के समझौत पर हस्ताक्षर किये। इससे नेपाल का तिब्बत के 'केरूंग क्षेत्र' से सीधा संपर्क हो जायेगा। राइजिंग नेपाल (19.05.2001) में प्रकाशित एक लेख में चिरंजीवी पौडेल ने कहा कि नेपाल और चीन के संबंध प्राचीन सभ्यता, समान संस्कृति और धर्मिक परम्पराओं की ठोस नींव पर आधरति है और इनमें कभी उतार–चढ़ाव नहीं आया जो दोनों देशों के बीच सच्ची मैत्री का प्रतीक है।

उधर चीन ने ळवसउनक से ल्हासा तक ग्यारह सौ किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। इस संबंध में तत्कालीन नेपाल नरेश की यह कथन महत्वपूर्ण है कि तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर बनी यह रेल लाइन दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन है। चीन के उप रेल मंत्री सेन योंगफू ने कहा कि इस रेल लाइन का स्ट्रेटेजिक महत्व है, वैसे ल्हासा भले ही काठमांडू से दूर है परन्तु तिब्बत नेपाली की उत्तरी सीमा है। अतः तिब्बत म हा रह परिवर्तन का नेपाल पर असर पड़ना स्वाभविक है।

भारत और नेपाल

काठमांडू से प्रकाशित नेपाली पत्रिका 'राष्ट्रीय मंच' ने अपने जनवरी 2002 क अंक में लिखा है कि ''नेपाल में भारत विरोधी भावना कुछ वर्षो से है और इसके कई कारण हैं– पुरानी पंचायत व्यवसथा मूलतः भारत विरोधी भावना पर आधरित थो। राष्ट्रवाद पर आधरित थी। राष्टवाद के नाम पर इस व्यवस्था के लोग भारत का विरोध करते थे और प्रजातंत्र के नाम पर नेपाली कांग्रेस का। नेपाल में किसी संस्था या कार्य की राष्ट्रभक्ति का एक ही पैमाना है कि उसने कितनी बार भारतीय मूल्यों और सिद्धातों के खिलाफ आवाज उठाई है। परन्तु चिंता की बात यह नहीं। चिंता की बात यह है कि इस स्थिति का लाभ एक तीसरा देश पाकिस्तानी उठाता रहा है। उदाहरण के तौर पर ह्रतिक रोशन कांड के दौरान देश भर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन और घटनाएं हुई। बाद में नेपालियों को पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहरहाल इससे नेपाल को ही ज्यादा नुकसान हुआ। ह्रतिक रोशन कांड से नेपाल के मधेशियों और गैर मधेशियों के बीच कटुता बढ़ गयी तथा नेपाल का पर्यटन व्यवसाय संकट में पड़ गया। इसी प्रकार जब भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया था तो उस समय नेपाल के कुछ नेता जो अपने को राष्ट्रवादी कहते थे वास्तव में चीन की तरफ झुक गये और भारत विरोधी लहर को हवा दे रहे थे। परन्तु इस सारी स्थिति के लिये केवल नेपाल ही जिम्मेदार नहीं। भारत ने भी कई भूलें की हैं। नेपाल में इस बात को लेकर बहुत हो–हल्ला मचाया गया कि भारत द्वारा रसियवाल खुर्दलोटन बांध के निर्माण से लुंबिनी डूब जायेगी। भारत सरकार समय से नेपाल को नहीं समझा सकी कि ऐसी कोई बात नहीं। लुम्बिनी को कोई खतरा नहीं है।

नेपाल के लोग इस वजह से भी शंकालु हो जाते हैं कि भारतीय पुलिस यदाकदा नेपाल में बिना अनुमति के आ जाती है। वर्ष 1996 में भारत नेपाली के बीच महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये गये। पाकिस्तान इसका प्रारम्भ से ही विरोध करता रहा है। अतः उसने इस संधि के विरोधी नेपाली नेताओं को सह देना शरू कर दिया। उसका कारण था कि इस संधि से छमेलिया नदी पर पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित बिजली घर पानी में डूब जाता। अतः पाकिस्तान शुरू हो सही महाकाली संधि के खिलाफ था।

.....एक दशक पहले तक नेपाल में कोई भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थक अखबार नहीं था। परन्तु दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों नेपालो मीडिया को प्रभावित करने के लिये करोड़ों रूपया खर्च कर दिया है। नेपाल ने पाकिस्तान के साथ ''दौत्य सम्बन्ध'' इसलिये स्थापित किया कि वह तीन तरफ भारत से घिरे नेपाल की मद करेगा। परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक इस प्रकार की कोई सद्भावना नहीं दिखाई है।

इसी संदर्भ में पटना से प्रकाशित हिन्दुस्तान की एक खबर भी पढ़ने लायक है– अमेरिको संसद में रिपब्लिकन पार्टी की एक शोध समिति ने अपनी रिपोर्ट 'न्यू इस्लामिक इंटरनेशलन' में कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई. एस.आई. नेपाल तथा बांग्लादेश स्थित अपने गुप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से

भारत के विभिन्न भगों में आतंकवाद तथा विघनटनकारी गतिविधियों को फैलाने का प्रशिक्षण दे रही है। भारत–नेपाल खुली सीमा का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में उपद्रवकारी भारत में घुसने म सफल रहे हैं। हाल के दिनों में करीब दो दर्जन आतंकवादी पूर्वी चम्पारण तथ सीतामढ़ी जिलों में पकड़े गये हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अब उत्तरी भारत के काफी बड़े क्षेत्र में अपना जाल फैलाने लगी है। नेपाल से लगी भारतीय सीमा में आई.एस.आई. समाजिक एवं धार्मिक विद्वेष फैलाने के साथ इस्लामीकरण का आधार भी तैयार कर रही है। एक सुनियोजित योजना के तहत नेपाल के कृष्णा नगर, भालूगांव, नेपालगंज, जनकपुर और कल्या में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रही हैं। इन शिविरों का संबंध नेपाल के माओवादियों से भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं हिन्दुस्तान पटना 10 जुलाई, 2001)। इस तरह नेपाल की सीमा से दूर रहते हुये भी पाकिस्तान की गतिविधिया भारत–नेपाल संबंधों को प्रभावित करती हैं। भविष्य में इनका प्रभाव और बढ़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं।

अध्याय–3
माओवादी एजेंडा

नेपाल एक बार फिर माओवादी हिंसा से त्रस्त है। गृह युद्ध जसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, माओवादी समस्या नेपाल का आंतरिक मामला है। परन्तु सबसे नज़दीक और मित्र देश होने के कारण भारत का नेपाल की घटनाओं से चिन्तित होना स्वाभाविक है। विशेषकर तब जब माओवादियों की पांच प्रमुख मांगें भारत से ही सम्बन्धित ह। नेपाल के माओवादी आंदोलन को समझने के लिये सबसे पहले नेपाल के वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर सरसरी निगाह डालना होगा।

सबसे पहले वर्ष 1949 में पुष्पलाल प्रधान ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके सिद्धांत तत्कालीन सोवियत यूनियन के ज्यादा नजदीक समझे जाते थे। उस समय चीन का भो सोवियत यूनियन से कोइ सैद्धांतिक मतभेद नहीं था। वर्ष 1971 में मोहन विक्रम सिंह ने चीनी साम्यवाद के आधार पर एक संस्था का गठन किया। उन्होंने वर्ष 1974 में चौथा सम्मेलन आयोजित किया और पार्टी की विधिवित विभाजन हो गया। वर्ष 1983 में मोहन विक्रम सिंह मशाल गुट फिर विभाजित हा गया और कुछ वामपंथी निर्मल लामा के साथ हो लिये। गरम दल वालों में फिर विभाजन हो गया और मोहन वैध के नेतृत्व में माओवाद में विश्वास करने वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी–मशाल का गठन किया। वर्ष 1989 में पुष्प कमल दहाल उर्फ कामरेड प्रचंड मोहन वैद्य गुट के महासचिव बनाये गये। इस प्रकार वर्ष 1990 के पहले कुल मिलाकर अठ्ठारह वामपंथी दल गठित हो गये थे। वर्ष 1990 के बाद भी इनकी संख्या कम जरूर हुई परन्तु 11 वामपंथो दल थे, इस समय भी नेपाल में तेरह वामपंथी दल हैं। काठमांड् से प्रकाशित 'काठमाडू पोस्ट' (06.09.2001) के अंक में प्रत्यूष ओटा का एक विश्लेषण प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि यह सच है कि साठ के दशक में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी में हुये पहले विघटन के बाद दो दल बन गये–एक सोवियत रूस समर्थक और दूसरा चीन समर्थक। रूस समर्थक गुट ने राजा महेन्द्र से समझौता कर लिया और उन्हें पार्टी विहीन पंचायत व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। बाद में चीन समर्थक गुट में और अधिक विभाजन होते गये। चूंकि वर्तमान में माओवादियों की उत्पत्ति चीन समर्थक वामपंथी दल से हुई है, अतः कुछ राजनीतिक विश्लेषक उन्हे चीन समर्थक मानते हैं।

वर्ष 1991 के संविधान के आने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–मशाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथा महाधिवेशन निर्मल लामा, सर्वहारा श्रमिक संगठन (रूप लाल) का विलय होकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) की स्थापना हुई। कछ समय बाद आम चुनाव के बारे में मशाल पक्ष और चौथा महाधिवेशन के बीच विवाद शुरू हो गया। किन्तु संयुक्त मोर्चा नामक संस्था का गठन करके उन्होंने चुनाव में भाग लिया और कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र की टिकट पर वर्ष 1990 में माओवादी डॉ. बाबूराम भट्टराइ सहित नौ व्यक्तियों ने जीत हासिल की,

जो संसद में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी वर्ष आयोजित संयुक्त महाधिवेशन ने माओवादी नेता प्रचंड द्वारा प्रस्तुत 'जनयुद्ध' का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। वर्ष 1992 में एकता केन्द्र की स्थानीय निकाय चुनावों में करारी हार हुई। उसके बाद पार्टी का नाम बदलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी कर दिया गया। वर्ष 1994 के मध्यावधि चुनाव का माओवादियों ने बहिष्कार किया। दिनांक 13 फरवरी, 1996 को डॉ. बाबू राम भट्टराई के यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को अपनी चालीस मांगों की सूची दी, किन्तु मांग स्वीकार करने का समय सीमा समाप्त होने के पहले उन्होंने रूकुम, रोल्पा, गोरखा और सिधुली आदि जिलों में पुलिस थानों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। इस बीच दिनांक 23 जुलाई, 2001 को शेर बहादुर देउबा को पुनः प्रधानमंत्री बनने पर माओवादियों और सरकार के बीच बातचीन के लिये समझौता हुआ। उसी वष 30 अगस्त, 01 सितम्बर और 13 नवम्बर को सरकार तथा माओवादियों क बीच वार्ताओं का दौर होने के बाद अचानक माओवादियों ने पुनः हिंसक गतिविधियां शुरू कर दी।

दिनांक 25 सितम्बर, 2000 को माओवादियों ने दुनई में जिला मुख्यालय पर हमला करके 14 पुलिसकर्मियों को मार डाला। अप्रैल–20001 के प्रथम सप्ताह में रूकुम में अलग–अलग घटनाआ में माओवादियों ने 70 पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस प्रकार दिनांक 13 फरवरी, 1996 से प्रारम्भ कथित माओवादी जनयुद्ध के कारण 2500 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। नेपाल की अर्थ–व्यवस्था चौपट हो गयी है।

माओवादियों ने अपनी 40 मांगों की जो सूची सरकार को दी थी, उनमें भारत से संबंधित मांगे इस प्रकार हैं:–

1. 1. सन 1950 की भारत–नेपाल संधि तथा अन्य असमान संधि समझौते खारिज किये जाय।
2. 2. महाकाली संधि को तुरंत रद्द किया जाय।
3. 3. नेपाल भारत सीमा को तुरंत नियमित और व्यवस्थित किया जाय। नेपाल के अंदर भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के चलने पर तुरंत रोक लगाई जाय।
4. 4. गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द किया जाय और गोरखलियों के लिये देश में ही सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था की जाय।
5. नेपाल में काम कर रहे विदेशियों के लिये वर्क परमिट की व्यवस्था लागू की जाय।
6. हिन्दी सिनेमा, पत्र–पत्रिकाएं तथा वीडियो के प्रसारण तथा वितरण पर तत्काल रोक लगाई जाय।
7. नेपाल को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया जाय।

इसके अतिरिक्त माआवादियों की मांग यह भी है कि नेपाल में जन गणतंत्र की स्थापना के लिये नयी संविधान सभा गठित की जाय। राजा तथा राज–परिवार के सदस्यों के विशेष अधिकार समाप्त किये जाय।

यह महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल के लगभाग सभी राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी संविधन सभा के गठन और राजतंत्र की समाप्ति की मांग को छोड़कर

माओवादियों की अन्य सभो मांगों का समर्थन करते हैं। देउबा सरकार से चल रही वार्ताओं से अचानक अलग हो जाने के बाद माओवादियों ने और जोरदार ढंग से हिंसक गतिविधियां शुरू कर दीं। उन्होंने सेना के बैरक पर भी हमला शुरू कर दिया फलस्परूप माओवादियों से लड़ने के लिये शाही सेना लगा दी गयी। माओवादियों के ख्लिाफ अभियान में भारत ने नेपाल को सैनिक सामान आदि मुहैया कराया। अमेरिका ने भी आर्थिक सहायता देने की पेशकश की। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के दल ने भो माओवादी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पहली बार अमेरिका के विदेश कोलिन पावेल काडमांडू आय। जिस प्रकार अमेरिका नेपाल के मामलों मे दिलचस्पी ले रहा है, कुछ प्रेक्षकों का मानना है कि आतंकवाद के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय अभियान क नाम पर अगर अमेरिका नेपाल में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लें तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये। इससे भारत और चीन दानों पर निगाह रखने में अमेरिका को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। नेपाल के पूर्व विदेश सचिव उद्धव दत्त भट्ट ने मरे साथ बातचीत में यह स्वीकार किया कि अमेरका की दिलचस्पी नेपाल में और बढ़ेगी।

नेपाल संतव 25 वैशाख 2059 को नेकपा माओवादी अध्यक्ष द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गयी है कि चीन को घेरने तथा भारत को झुकाने के उद्देश्य से अमेरिका देउबा सरकार के समर्थन से नेपाल मं सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इससे पहले दिनांक 15 मार्च 2002 को पर्यटकों के नाम माओवादी नेता तथा यूनाइटेड रिवाल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल के संयाजक डॉ. बाबू भट्टराई ने एक खुला पत्र लिख। उन्होन भारतीय पर्यटकों के लिये जिस शब्दावली का उपयोग किया उससे लगता है कि भारत के प्रति माओवादियों के रूख में कुछ परिवर्तन आया है। अंग्रेजी में लिखे गये उनके पत्र के एक अंश का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैं– और पड़ोसी देश भारत के सम्मानित अतिथियों के लिय कुछ शब्द। हालांकि प्रतिक्रियावादी सरकारी मीडिया द्वारा हमारी तथाकथित भारत विरोधी नीतियों का ढ़िढोरा पीटा जा रहा है परन्तु आपको अनावश्यक रूप से घबड़ाने की जरूरत नहीं। दोनों देशों के सत्ताधारी वर्ग ने दोनों देशों की जनता के बीच दारर पैदा करने के लिये दुरभि संधि कर रखी है। परन्तु हमें इस बात का पूरा एहसास है कि दानों देशों की जनता का भाग्य एक–दूसरे से जुड़ा हुआ है। अतः भारतीय पर्यटकों का नेपाल में स्वागत है।

अब सवाल यह है कि नेपाल के माओवादियों की मदद कहां से मिल रही है। भारत ने नेपाल के माओवादियों को पहले से ही आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब भारत ने उनके खिलाफ सैनिक सहायता भी मुहैया कराया है। चीन के काठमांडू स्थित चीनी राजदूरत ने दिनांक 10 मई , 2002 को काठमांडू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि माओवादी चेयरमन माओ के नाम का दुरूपयोग कर रहे हैं। हम उन्हें माओवादी कभी नहीं मानते हैं। हम उन्हें सरकार विरोधी गिरोह मानते हैं। चीनी राजदूत ने यह तो कहा कि उनका देश आतंकादी गतिविधियों की निंदा करता हैं परन्तु उन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया कि नेपाल के माओवादी आतंकवादी है या नहीं। उनको उन्होंने केवल सरकार विरोधी गिरोह बताया। चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि उनका देश माओवादियों के खिलाफ अभियान

में नेपाल को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता दे रहा ह। परन्तु नेपाल के एक मंत्री ने मुझसे बातचीत में स्वीकार किया कि माओवादियों के खिलाफ नेपाल ने पहले चीन से ही सैनिक तथा आर्थिक सहायता मांगी थी, परन्तु चीन ने कोई सहायता देने से इनकार कर दिया। उसके बाद नेपाल ने भारत और अमेरिका की ओर मुंह मोड़ा।

कुछ लोगेां का ख्याल है कि नेपाल के माओवादी रिम अर्थात रिवाल्यूशनरी इंटरनेशनललिस्ट मूवमंट के निर्देशन और मार्गदर्शन में काम करते हैं। काठमांड् से प्रकाशित नपाली टाइम्स के दिनांक 30 नवम्बर, 2001 के अंक में माओवादियों के बार में कई दिलचस्प सूचनाएं दी गयी हैं जैसे माओवादियों ने जुलाई 2001 में कन्फेडरेशन ऑफ कम्युनिस्ट एंड माअइस्ट पार्टीज आफ साउथ एशिया ;ब्ब्।डच्ै।द्ध नामक क्षेत्रीय संगठन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने दिनांक 21 नवम्बर 2001 को डॉ. बाबू राम भट्टराई की अध्यक्षता में सैतीस सदस्यीय संयुक्त क्रांतिकारी जन परिषद का गठन किया। पत्र ने यह भी कहा है कि दिनांक 01 जून, 2001 को नेपाल नरेश वीरेन्द्र की हत्या के बाद माओवादी रिपब्लिक का जन्म हो गया हे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्वर्गीय नरेश वीरेन्द्र के साथ उनकी समझदारी विकसित हा गयी थी जिसे वे वर्किंग अंडरस्टैडिंग ;वतापदह न्दकमतेजंदकपदहद्ध कहते हैं इस वक्तव्य का कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि माओवादियों को दरबार का समर्थन प्राप्त था। परन्तु अखबार की खबरों के आधार पर ऐसा निर्णय करना उचित नहीं लगता।

लंदन के समाचार पत्र इन्डिपेंडेंट ने दिनांक 14 मई, 2002 को अपने वेबसाइट पर इस बात का खुलासा किया कि नेपाल के माओवादियों को अलकायदा से जुड़े संगठन हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके पहले ये अंतरराष्ट्रीय काला बाजार और भारत के विद्रोही संगठनों से हथियार प्राप्त कर रहे थे। द काठमांडू पोस्ट– 18.04.2001 में प्रकाशित हरि भूजेल के लेख मे बातया गया है कि माओवादी नेता पचंड और बाबू राम भट्टराई ने राज द्वारा नामित राष्ट्रीय सभा के सदस्य रमेश नाथ पाण्डेय से मुलाकात की थी। पाण्डेय ने भी मुलाकात की बात स्वीकार की परन्तु मुलाकात का ब्यौरा देने से इंकार कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि माओवादी नेता, रमेश नाथ पाण्डेय के माध्यम से दरबार में सम्पर्क बनाना चाहते हैं। जून 2001 में नेपाल नरेश वीरेन्द्र की हत्या हो गयी। इसके बाद माओवादियों का यह वक्तव्य आया कि स्वर्गीय महाराज से उनकी वर्किंग समझदारी बन गयी थी। दि. 27 जुलाई 2001 को नयी दिल्ली के एशियनएज में काठमांडू से डी.पी.ए. के संवाददाता के हवाले से एक खबर छपो जिसमें कहा गया कि नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल एमाले द्वारा गठित एक समिति ने रिपोर्ट दी है कि माओवादियां और दरबार के बीच गुप्त सम्बंध है। इस समिति के अध्यक्ष पार्टी के एक प्रमुख सांसद झालानाथ खनाल थे। यह खबर सबसे पहले काठमांडू के हिमालय टाइम्स मे छपी थी।

नेपाल के माओवादियों को कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइेशन, उल्फा, एम.सी.सी. तथा जी.डब्ल्यू.जी. जैसे भारत के उग्रवादी संगठनों से मदद मिल रही है। हिन्दुस्तान टाइम्स नयी दिल्ली दिनाक 07 अगस्त 2001 में भारत के जलपाईगुड़ी के पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर देते हुय कहा गया कि उल्फा म्यांमार से हथियार लकर के.एल.ओ. को देती है जो माओवादी को देते है।

बदले में नेपाल के माआवेादियों ने के.एल.ओ. को प्रशिक्षिण देने का वायदा किया है। इसी अखबार में दि. 19.02.2002 को छपी एक खबर में राहुल दास ने पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दी कि नेपाल के माओवादियां का भारत के एम.सी.सी. और पो.डब्ल्यू.जी. से पक्का संबंध है। लगता है कि इन खबरों के बाद भी भारत सरकार ने नेपाल से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ाने का निर्णय लिया और वहां विशेष सशस्त्र बल के जवाना को तैनात किया गया है।

नेपाल के माओवादियों ने दि. 13 दिसम्बर 2001 को भारत के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि वे ही नेपाल की जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं और वे नेपाल को पूर्ण रूप से गणतंत्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने भारत और चीन से विशेष रूप से आग्रह किया कि ये दोनों देश नेपाल के आंतरिक मामालों में दखल न दें। सरकार से दूसरे दौर की बातचीत के दार माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा ने एक पस कांफ्रेंस में कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख दी हैं, अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारी मांगें स्वीकार करें अन्यथा अगली वार्ता नहीं भी हो सकतो है। और ऐसा ही हुआ वे वार्ता के लिये नहीं आये तथा हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया।

ऐसा प्रतीत हाता है कि नेपाल के माओवादी आंदोलन के कीचड़ में न चाहते हुये भीा भारत का अपना एक पैर पड़ गया है। लोगा को यह भी आशंका है कि इस आंदोलन की परिणिति नेपाल में प्रजातंत्र की समाप्त में भी सकती है।

नेपाल के माओवादी आंदोलन के तार जहां भो जुड़े हों परन्तु भारत के लिये चिंता की बात है। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. की नेपाल में बढ़ती गतिविधियां तथा माओवादी हिंसा को अलग–अलग करके देखने से समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ऐसा कछ पर्यवेक्षकों का ख्याल है। बहरहाल माओवादी हिसा से निर्दोष नेपालियों का खून ही बह रहा है जिससे घाटी के लोग आक्रांत एवं भयभोत हैं। दिनांक 18 अप्रैल 2002 को काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित अपने लेख में प्रकाश ए. राज ने विचार व्यक्त किया कि नेपाल के तराई के चार जिलों कंचनपुर, कैलाली, बरदिा और बांके में माओवादियों का प्रभाव काफी है। ये जिले उत्तर प्रदेश के बहराइच से बनबसा से सटे हुये हैं जो दिल्ली के बहुत करीब है। इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। ....इसलिये न कवल नेपाल अपितु भारत और अमेरिका के हित में भी यही है कि नेपाल की माओवादी समस्या का समाधान वार्ता से न कि सैनिक कार्रवाई से तुरंत निकाला जाना चहिये।

अब तो माओवादी बिना किसी रोकटोक के पूरे तराई क्षेत्र में घूम रहे हैं और धमका कर वसूली कर रहे हैं। उधर मधेशी समुदाय के उग्रवादी भी उनसे बढ़चढ़ कर लोहा ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नेपाल में शांति स्थापना की उम्मीद धूमिल हो गयी है।

अध्याय–4
विवाद के बिन्दु
नदियां! वरदान या अभिशाप

नदियों के कारण दो देशों के बीच किस प्रकार के तनाव पैदा हो सकते हैं, यह हम सभी जानते हैं। लोगों के लिये पीने तथा औद्योगीकरण हेतु पानी की महती और अनिवार्य आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विश्व के बदलते हुये परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में दुनिया में अधिकांश संघर्ष नदियों आर पानी के कारण ही होंगे। ऐसा विशेषज्ञों का भी ख्याल है। स्मरणीय है कि नेपाल से प्रारम्भ होने वाली प्रायः सभी प्रमुख नदियां भारत से ही होकर गुजरती हैं। इसलियों दानों देशों के बीच संबंधों की दिशा भविष्य में ये नदियां ही तय करेगी, अनुचित नहीं होगा।

नेपाल और भारत के बीच संबंधों में नदियों का महत्व कम नहीं। मुख्य रूप से इनसे संबंधित मुद्दे तीन प्रकार के हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। भारत ने नेपाल से लगी अपनी सीमा के भू–भाग में गांवों को बाढ़ तथा जल भराव से बचाने के लिये कई स्थानों पर छोटे–छोटे बंधे बना रखे हैं जिन्हें नपेाली मीडिया में बराबर बांध ही कहा जाता है। इन बंधों से कई स्थानों पर नेपाली क्षेत्र के गांवों में भी पानी भर जाता होगा, ऐसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इस समस्या का नेपाली मीडिया में जिस ढंग से कवरेज होात है उससे नेपाल में भारत के प्रति काफी दुर्भावना बढ़ती है। इसी वजह से नेपाल के नेता सही आर यथोचित जल परियोजनाआ के बारे में भी भारत से समझौता करने में कतराते हैं। पिछले दो–तीन वर्षो में इस प्रकार के जो सबसे चर्चित बंधे थे, वे नपाल के बांके जिले के पास भारतीय भू–भाग में राप्ती नदी पर बना लक्ष्मणपुर बंधा और रूपनदेही जिले के पास भारत में निर्माणाधीन रसियावल खुर्दलोटन बंधा। इसके अलावा दोनों देशों की सीमा पर बने अन्य कई छोटे–छोटे बंधे भी हैं जिनका जिक्र प्रायः होता रहता है। निहित स्वार्थी तत्व भारत के खिलाफ अपना विष वमन करते हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिये दोनों देशों की संयुक्त तकनीकी समिति विधिवत गठित है। इसकी बैठकें भी होती रहती हैं। यह दोनों देशों के हित में है कि उन कारणों का पता लगाया जाय कि इस समिति के होते हुये भी इस प्रकार की समस्यायें क्यों पैदा होती है आर एक दूसरे के प्रति विपरती भावनायें क्यों पनपती हैं? जल संसाधनों से संबंधित दोनों देशों के बीच दूसरे प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिनका संबंध नदी जल समझौता से है। स्वतंत्र भारत में अब तक कोसी और गंडक नदियों से संबंधित दो समझौते दोनों देशों के बीच अनुबंधित हैं। तीसरा समझौता महाकाली नदी से सम्बन्धित है, जो लगभग 12 वर्षो बाद भी अभी केवल कागजों पर है। नेपाल में यह आम धारणा है कि कोसी तथा गंडक परियोजनाओं से लाभ भारत को ज्यादा होता है एवं इन समझौतों में भारत ने नेपाल को ठग लिया है। इस भावना के मूल में मीडिया द्वारा किया गया निराधार प्रचार है। यह सत्य है कि इन दोनों परियोजनाओं से नेपाल को जितना लाभ मिलने की उम्मीद थी

उतनी उसे नहीं मिल पाया, किन्तु इसके लिये नेपाल सरकार की उदासीनता भी एक बड़ा कारण है। केवल भारत को दोष देना उचित नहीं।

तीसरे प्रकार के वे मुद्दे हैं जिनका संबंध जल–विद्युत से है। नेपाल की जल विद्युत क्षमता 8300 मेगावाट है जिसका मात्र एक प्रतिशत से भी कम उत्पादन हो पा रहा है। यदि नेपाल की पूरी विद्युत क्षमता विकसत हो जाय तो नेपाल दुनिया के धनी देशों की श्रेणी में आ जायेगा। इतनी ही नहों भारत के सीमावर्ती राज्यों, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। नेपाल मे उत्पादन होने वाली विद्युत ऊर्जा का एकमात्र उपभोक्ता भारत होगा। भारत के साथ समझौत करना आसान नहीं क्योंकि दोनों देशों के बीच जो शंकाग्रस्त माहौल है वह दोनों दशों के बीच संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आड़े आता है। उदाहरण के तौर पर महाकाली परियोजना को ही लं। दोनों देशा के बीच इस समझौते पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर हुये। नेपाल की संसद में इसका अनुमादन भी किया। परन्तु अभी तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;क्मजंपसमक च्तवरमबज त्मचवतजद्ध ही तैयार नहीं हो पायी है। इस परियोजना का नेपाल में इतना विरोध हुआ कि मुख्य विपक्षी दल एमाले का विभाजन हो गया और वामदेव गौतम के नेतृत्व में क. पा. माले नामक एक अलग दल बन गया। यद्यपि अब दोनों दल फिर से एक हो गये हैं लेकिन महाकाली परियोजना का कार्यान्वयन जिस मंथर गति से हो रही है उसका पूरा होना आसान नहीं दिखता। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि नेपाली संसद ने इस परियोजना को जिन शतों के साथ मंजूरी दी है उन शतों का पूरा होना स्वयं में एक टेढ़ी खीर है।

अनुमानित है कि महाकाली नदी परियोजना से 60,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा तथा दोनों देशों में हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक महाकाली संधि के अंतर्गत पंचेश्वर परियोजना की विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट ;क्मजंपसमक च्तवरमबज त्मचवतजद्ध तैयार करने में देरी हो रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच पानी के उपभोग तथा जलाशय के स्थान के बारे में मतभेद है। 'डेमोक्रेटिक नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ नेपाल' ने डॉक्टर मंगल सिद्धि मानन्धर, वी.बी.थापा और डॉ. गोपी उप्रेती द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट प्रेस के लिये जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पंचेश्वर जलाशय पूर्णागिरि में बनाया जायेगा जैसा कि भारत का प्रस्ताव है तो उससे नेपाल की 25,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जायेगी, जबकि भारत में केवल लगभग 1500 हेक्टेअर जमीन डूबेगी जिसमें कोई आबादी भी नहीं है। इसके अलावा यहां जलाश्य बनाने से नेपाल के पर्यावरण पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की आशंकाओं के निराकरण के लिये जो पयास होने चाहिये उनका अभाव ही दिखता है। परिणामस्वरूप महाकाली परियोजना अभी अधर में लटकी हुई है।

आदित्य एम.श्रेष्ठ की एक पुस्तक 'ब्लीडिंग माउन्टेस ऑफ नेपाल' हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें उन्होंने एक बहुत ही रोचक काल्पनिक तथ्य प्रकाशित किया है जो भारत–नेपाल जल समझौतों के बारे में हैं। पृष्ठ–201 पर उन्होंने लिखा है कि पानी से संबंधित मुद्दों पर नेपाल के साथ जब भारत कुछ भी करता है उसका लाभ उसे ही मिलता है, अगर भारत निष्क्रिय बैठता है तब भी

उसे ही फायदा होता है। हर हालत में भारत नेपाल से आगे रहता है'' पृष्ठ–206 पर श्री श्रेष्ठ ने कहा है कि भारत ने अब तक नेपाल को पांच बिलियन रूपये की सहायता दी है जबकि नेपाल के साथ जल समझौतों के फलस्वरूप भारत को नेपाल के सहयोग से तीन हजार छः सौ बिलियन रूपये से अधिक का लाभ हुआ है। इस तरह नेपाल को दिये गये हर एक रूपये को सहायता के बदले भारत को सात सौ सैंतीस रूपये से अधिक का अदृश्य लाभ हुआ है। श्री श्रेष्ठ ने हिसाब लगाकर बताया है कि कोसी और गंडक परियोजनाओं से भारत के किसानों को औसतन प्रति वर्ष हेक्टेअर लगभग चाबोस हजार पांच सौ रूपये का लाभ हेता है। काश! श्री श्रष्ठ की कल्पना सही होती। वास्तविकता यह है कि कासी और गंडक परियोजना क्षेत्र में भारत के किसानों की आमदनी इसकी एक चौथाई भी नहीं है। वैसे श्री श्रेष्ठ की कल्पना को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि उनकी पुस्तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नेपाल में उन्हें छोड़कर अन्य सभी लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पड़े हैं।

गंडक समझौतों के बारे में नेपाल के स्वर्गीय प्रधानमंत्री बी.पी. कोइराला ने अपनी आत्मकथा में एक दिलचस्प बात का जिक्र किया है। जिससे पता चलता है कि भारत और नपाल के बीच राजनीति और कूटनीति किस तरह काम करती है। बी.पी. ने लिखा है कि उन्होंन अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में बहुत दिनों से लंबित गंडक समझौते पर दोनों देशों के हस्ताक्षर करवाये। उन्होने कहा कि नेपाल नरेश कभी–कभी अनावश्यक समस्या पदा कर देते थे। गंडक समझौते के बारे में भी उन्होंने ऐसा हो किया। समझौते से पहले उन्होंने कहा कि समझौते में नेपाल के मछली पकड़ने के अधिकार का उल्लेख होना चाहिये। चूंकि कोसी समझौत में यह बात रह गयी थी। मैन नरेश के इस निर्देश का उल्लेख जब भारत के राजदूत से किया तो उन्होनें कहा कि अब यह सम्भव नहीं हैं क्योंकि समझौते का मसौदा पहले नेपाल को भेजा गया था। नेपाल द्वारा संशोधित और स्वीकृत मसौदे को भारत की कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब उसमे फिर कुछ जोड़ना या घटाना आसान नहीं। इसके बाद राजदूत ने स्वयं नेपाल नरेश महेन्द्र से बात की और नरेश मान गये कि ठीक है, मछली पकड़ने के अधिकार का उल्लेख नहीं होगा। मैं इस सारे घटनाक्रम से खिन्न था– बहरहाल समझौते पर 1959 में नपाल के उपप्रधनमंत्री सुवर्ण शमसेर और भारतीय राजदूत के हस्ताक्षर हो गये। परन्तु नेपाल नरेश महेन्द्र ने भारत पर चीनी हमले के बाद अप्रैल 1964 में स्थिति का लाभ उठाते हुये गंडक समझौते में अपनी मर्जी के मुताबिक संशोधन करा लिया। ;त्पेपदह छमचंस 10 अप्रैल, 2000 एस.बी.पुन के लेख से साभार अनूदितद्ध।

भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कोसी और गंडक परियोजाओं से सम्बन्धित खबरें देखने लायक है। –भारत और नेपाल में समान धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। रीति व्यवहार की एकरूपता के कारण दोनों देशों में बेटी रोटी का भी संबंध है। लेकिन जब से दोनों देशों के बीच जलसंधि हुई है तब से तनाव की शुरूआत हो गयी है। नयी दिल्ली में आजकल नेपाल–भारत जल संसाधन मुद्दों पर जन मंच के तहत नेपाल के करीब दजन भर लोगों का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। इसी के साथ सीमा के पास के भारतीय क्षेत्र के निवासियों के पतिनधि भी आये हुये हैं इन प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार की उदासीनता का खमियाजा सीमा के दाना आर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

नेपाल में रहने वाले जहां जल संधि को पुराने मित्र राष्ट्र द्वारा किया जा रहा छल करार देते हैं वहीं भारतीय लोगों का कहना है कि नेपाल के कारण ही उन्हें हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। भारत–नेपाल के बीच पहली जल संधि कोसी परियोजना का निर्माण वर्ष 1954 में हुआ था। परियोजना के पूर्व अधिकारी गोपाल प्रसाद कोइराला ने कहा कि उस समय जो वादे किये गये थे वे सब दिवास्पप्न साबित हुये यहां तक 50 वष बीत जाने के बाद भी परियेाजना के लिये जिन किसानों की जमीन ली गयी उन्हें आज तक मुआवजा ;ब्वउचमदेंजपवदद्ध भी नहीं दिया गया। बिहार के मधेपुरा जिले के श्री देवनारायण यादव का कहना है कि कोसी परियोना से प्रारम्भ में हमें कुछ लाभ हुआ किन्तुअब हमारे खेतों में बालू भर गया है। कोसी के गाद को कभी निकाला नहीं गया, इस कारण कोसी नदी का जल स्तर ऊंचा हो गया है और हर साल हमें बाढ़ का संकट झेलना पड़ता है। नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली में प्रकाशित एक रिपोर्ट)।

नेपाल से दक्षिण की ओर जाने वाली नदियां अपने साथ दुःखद कहानियां लेकर जाती हैं। यह बात तो समझ में आती है कि चूंकि भारत ही इन नदियां पर बनने वाले बांधा के लिये सहायता देता है तो उसे अधिक बिजली और का उपयोग करने का हक है परन्तु यह उचित नहीं कि सहायता लेने वाले देश नेपाल के साथ बुरा बर्ताव किया जाय। भारत यह जानता है कि नेपाल की अर्थ–व्यवस्था अधिकांशतः भारत पर निर्भर है अतः वह हमेशा नेपाल के साथ दादागिरी करता है।। नेपाल अपन पड़ोसियों के साथ शांति और सद्भावना से रहना चाहता है। समझदारी इसी में है कि भारत को भी यह समझना चाहिये कि पड़ोसी के साथ मित्रता बहुत कीमती है'' यह विचार ओम मूर्ति वैद्य न दिनांक 19 अगस्त, 2001 को काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित अपने लेख में व्यक्त किये और कहा कि भारत को रसियावल खुर्दलोटन बांध का निर्माण बंद कर देना चाहिये। हालंकि वस्तुस्थिाति यह है कि भारत ने नेपाल के कहने पर तुरन्त निर्माण कार्य रूकवा दिया। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि इस निर्माण कार्य से लुम्बिनी को कोई खतरा नहीं क्योंकि लुम्बिनी की ऊंचाई प्रस्तावित बंधे से कहीं ऊंची है तथा बंधे और लुम्बिनी के बीच एक नदी भी बहती है परन्तु नेपाली मीडिया में इसका चित्रण इस तरह किया गया कि भारत द्वारा कथित बांध के निमार्ण से लुम्बिनी तक डूब जोयगी। कुछ पत्रों ने तो इसकी तुलना बामियान में बौद्ध मूर्तियों के तोड़ने की घटना से भी कर दिया। इसलिये भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसंवत सिंह को काठमांडू में कहना पड़ा कि लुम्बिनी भारत के लिये भी उतना ही महत्वपूर्ण और श्रद्धा का केन्दे है जिनता नेपाल के लिये।

हिन्दुस्तान टाइम्स नयी दिल्ली के दिनांक 14 अगस्त 2001 के अंक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार एक अगस्त को शाही नेपाली सेना के जवानों ने कोसी परियोजना के एक भारतीय कर्मचारी गोविन्द दास को पीटा। इसके पहले 17 जुलाई को नेपाल के नवलषरासी जिले के निवासियों ने गंडक नहर को काट दिया और जब इस कटान की मरम्मत के लिये भारतीय इंजीनियरों का दल वहां गया तो नेपाल के नागरिकों ने उन्हें मारा पीटा। नहर के कटान से पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था।

काठमाडू पोस्ट (21 जुलाई, 2000) में प्रकाशित एक लेख में मोहन कार्की ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारत ने गौर बाजार, नेपालगंज, कपिलतवस्तु, सपतरी, महोतरी जिलों के गांवों को प्रतिवर्ष भीषण जलभराव और बाढ़ से प्रभावित होन के लिये मजबूर कर दिया है क्योंकि इन जिलों के सीमावर्ती गांवा के पास भारतीय क्षेत्र में बंधों का निर्माण कराया गया है। इस वजह से नेपाल की तराई के बड़े क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अतः पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखकर नेपाल सरकार को भारत सरकार क साथ किसी भी सिंचाई परियोजना के बारे में निर्णय लेने के पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिये।

नदियों को लेकर भारत और नेपाल के बीच इस समय जो भी राजनीति हो रहो हो परन्तु ये नदियों ही दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों में उतार–चढ़ाव की साक्षी हैं। अब राजनीति बहुत हो चुकी है। अब समय आ गया है कि दोनों देश आपस मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर विश्वास की भावना के साथ केवल अपना ही नहीं बल्कि दोना देशों के लोगा के हित में वैज्ञानिक ढंग से नदियों का उपयोग करें। इन नदियों क समुचित उपयोग से ही नेपाल तथा उसकी सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है।

.....

भारत–नेपाल संधि 1950

वर्ष 1950 की 'भारत नेपाल मैत्री और शान्ति संधि' एक प्रमुख दस्तावेज है जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व्यवहार और संबंध निर्धारित होते है। नेपाल में आये दिन इस संधि का उल्लेख किया जाता है। लगभग सभी राजनीतिक दल यह कहते है कि इस संधि को खारिज कर देना चाहिए। इस संधि के अनौचित्य के बारे में विभिन्न तर्क दिये जाते है।

वर्ष 1950 की 'संधि' के बारे में काठमांडू से पकाशित 'नेपाल समाचार पत्र' के दि. 15 दिसम्बर 2000 के अंक में नेपाल एक वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव हरि अधिकारी का एक लेख छपा। लेख में कहा गया है कि 'यह संधि नेपालियों के लिये सदैव चुभने वाले कांटे की तरह है।

न केवल नेपाल बल्कि भारत के बुद्धिजीवी भी इस विचार से सहमत है कि इस संधि को खारिज कर देना चाहिए। आधी शताब्दी पुरानी संधि आज की परिस्थिति में सन्दर्भहीन हो गई है। संसद या विधिवत गठित सरकार द्वारा अनुमोदित दस्तावेज नहीं होन के कारण यह कानूनी रूप से ग्राह्य भी नहीं है। वर्षो से निष्क्रिय संधि को खारिज करना ही पडेगा । तो एक निष्क्रिय संधि खारिज करने के लिये नेपाल के राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी क्यों बैचेन रहते है। नेपाल को स्वतंत्र और सार्वभौमिक देश मानकर ही यह संधि की गई है। असमान संधि होने की धारणा कहा से आती है । इतिहासकारों की धारणा है कि इस संधि के कारण ही नेपाल को स्वतंत्र और सार्वभौमिक राष्ट्र की सदस्यता मिली। हां अब दुनिया के अनेक दशों ने नेपाल को सार्वभौम और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है–यह अलग बात है। इस संधि में स्पष्ट प्राविधान है कि दोनों देशों में से कोई भी देश वष की नोटिस देकर उस संधि को समाप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि नेपाल इसे नोटिस देकर खारिज क्यों नहीं कर देता है। इसके उत्तर में श्री अधिकारी ने कहा है कि ''नेपाल सोचता है कि ऐसा करने से भारत नाराज हो जायेगा। '' फिर उन्होंने स्वयं तर्क दिया है कि ''नेपाल के ऐसा करने से भारत नाराज नहीं होगा। अतः नेपाल को पहल करके संधि खारिज कर देना चाहिए ।'' लेख में कहा गया है कि ''आकार में नेपाल भारत से छोटा है फिर भी नेपाल का सहयोग मूल्य विहीन नहीं है..... नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत को प्राकृतिक सरक्षा दिये हुये है। यह सभी के सामने स्पष्ट है। भारत और चीन के बीच नेपाल के होने के कारण ही आकस्मिक मुठभेड़ और संघर्ष की सैकड़ों सम्भावनाएं टल जाती है। ऐसी सुरक्षा अरबों रूपये खर्च करके और सीमा सुरक्षा सेना रखकर भी पाना संभव नहीं है। यह ऐसा तथ्य है जिसके बदले में नेपाल में कुछ छात्रवृत्तियॉ बांटकर अथवा कुछ पुल बनाकर ही ऋण की अदायगी नहीं की जा सकती है।'' सुनने में यह तर्क तो बहुत अच्छा लग सकता है परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । दरअसल भारत को चीन से उतना खतरा नहीं है जितना अन्य पड़ोसी देशों स है । चीन अधिक से अधिक भारत के कुछ भूभाग पर अपना दावा रखता है। इसे हथियाने के लिये ही उसने वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण भी किया था। उसके बाद सभी जानते है कि भारत–चीन सीमा पर कोई असामान्य संघर्ष नहीं हुआ। चीन कुछ भी करें भारत

की आन्तरिक सुरक्षा में दखल नहीं देता है, यह बहुत बड़ी बात है। परन्तु नेपाल की भूमि का दुरूपयोग करके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आइ. तथा माफिया गिरोह तो भारत की सुरक्षा और उसकी अर्थ–व्यवस्था को चौपट करने के लिये पता नहीं क्या–क्या कर रहे है। सम्भवतः इसी वजह स भारत और नेपाल दोनों को अपनी सीमा पर सशस्त्र बल तैनात करना पड़ा है और भविष्य में और गंभीर उपाय भी करने पड़ सकते है। नेपाल को माओवादी आंदोलन भारत के पी.डब्ल्यू.जी. और एम.सी.सी. संगठनों से मिलकर क्या गुल खिला सकता है यह तो भविष्य ही बताएगा । तो भारत और नेपाल की सीमा सुरक्षित कहां हुई।

लगता है कि नेपाल में लोग सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता के बारे में अनावश्यक रूप से संवेदनशील है। इसके लिए एक उदाहरण ही काफी होगा। नेपाल में जब माओवादियों का कहर बरपा होने लगा। वे पुलिस और सेना के बैरकों पर हमला करके भारी संख्या में सुरक्षा बलों को हताहत करने लगे। ऐसे समय में नेपाल ने भारत से हथियारों आदि की सहायता मांगी । भारत ने हथियार भेजना शुरू किया । अब हथियार आयेंगे तो मार्ग में उनकी सुरक्षा के लिये सुरक्षा कर्मी भी होंगे–फिर क्या था..।

काठमांडू से प्रकाशित कई अखबारों ने एक स्वर से आलाप करना प्रारम्भ किया कि भारतीय सेना नेपाल में प्रवेश कर गई और भारत नेपाल के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वे यह भूल गये कि हथियार नेपाल के मांगने से ही आ रहे थे । इसी वजह से भारत के कुछ बुद्धिजीवी आज भी इस विचार के है कि भारत को माओवादी के खिलाफ नेपाल की मदद नहीं करनी चाहिए । शायद आकलन सही है कि भारत की सैनिक सहायता से माओवादी तो भारत के दुश्मन बन ही रहे है, जिनके लिए भारत सैनिक सहायता भेज रहा है वे शायद ही कभी भारत की प्रशंसा करेंगे ।

नेपाल की सार्वभौमिकता के संदर्भ में एक और दिलचस्प वाकया का उल्लेख करना अप्रासंगिक नही होगा।

दिसम्बर 1999 में काठमांडू से भारतीय विमान के अपहरण के बाद इंडियन एयर लाइन्स की उड़ानें स्थगित कर दी गयी थी । उन्हें फिर चालू करने के लिए दानों देशों के बीच वार्ता शुरू हुई। भारत ने प्रस्ताव रखा कि नेपाल उसे इस बात की इजाजत दे कि भारत के सुरक्षाकर्मी काठमांडू एयर पोर्ट पर विमान में प्रवेश होने के पहले यात्रियों की सुरक्षा जांच करें। ऐसा दुनिया के अनेक देशों में होता है। परन्तु नेपाल ने भारत के इस प्रस्ताव को यह कहते हुये नामंजूर कर दिया कि नेपाल की धरती पर भारतीय सुरक्षाकर्मियों को मौजूदगी से नेपाल की सार्वभौमिकता का उल्लघंन होगा।

उसके बाद जो समाधान निकाला गया वो इतना हास्यास्पद है कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं लगता ।

श्री ध्रुव अधिकारी का यह कहना बिल्कुल सच है कि पचास की संधि नेपालियों को कांटें की तरह चुभती है। भारत को चाहिए कि वह इस संधि को तुरन्त खारिज कर दे परन्तु इसके पहले लोगों को इसके परिणामों की जानकारी भी होनी चाहिए। इतिहास के चक्के को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता। नेपाल एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश है। अगर वह भारत के साथ कोई खास संधि नही रखना चाहता है। तो उसे समाप्त करने में भारत को कोई एतराज नहीं होना

चाहिए। श्री ध्रुव अधिकारी के लिए यह कहना बड़ा आसान है कि संधि खारिज होने के बाद अगर भारत मं काम कर रहे नेपाली वापस नेपाल आ जाते है तो इसमें क्या हर्ज है? क्या उन्होंने उन नेपालियों से भी पूछा जो अपना घर–द्वार छोड़कर भारत के शहरों में रोजी रोटी कमा रहे है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में इस समय लगभग अस्सी लाख नेपाली काम करते है जा नेपाल की कुल आबादी का एक तिहाई है।
वैसे विद्वान लेखक ने यह स्वीकार किया है कि पचास की संधि खारिज होने के बाद भी भारत में काम कर रहे नेपालियों को वापस नेपाल नहीं आना पड़ेगा क्योंकि वे वहां संधि के कारण नहों अपितु दोनों देशों में निकट का संबंध होने के कारण काम कर रहे है।

लगभग इसी प्रकार के तर्क नेपाल के नेता भी पचास की संधि के खिलाफ देते है। वास्तविकता यह है कि सन पचास की संधि अब केवल कागजों में ही है। नेपाल में ऐसे कई कानून है जिनसे इस संधि का उल्लघंन होता है। नेपाली लोगों का आरोप है कि भारत भी इस संधि का पालन नहीं करता है। उनका कहना है कि भारत किसी दूसरे देश के विरूद्ध सैनिक कार्रवाई करने के पहले नेपाल से विचार विमर्श नहीं करता है जो उसे करना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता है।

परन्तु दूसरी तरफ ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनसे यह पता लगता है कि नेपाल तो संधि की जरा भी परवाह नही करता है । एक ही उदाहरण काफी होगा। नेपाल ने कुछ वर्ष पहले अपने यहां शिक्षा के विस्तार के लिए भारत से कुछ शिक्षकों को अपने यहां स्कूलों में काम करने के लिए आमंत्रित किया। उनमें से कई लोग अब रिटायर होने के कगार पर है किन्तु उन्हें आज तक नियमित नही किया गया।

भारतीय शिक्षकों की भर्ती पर तो रोक बहुत पहले ही लगा दी गयी जो संधि के विपरीत है। परन्तु ठीक है नेपाल में भारतीयों की कथित बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल ने अपने यहां भारतीय शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी किन्तु जिन्हें बुलाकर भर्ती किया गया उन्हें नियमित न करना क्या कानून और परम्पराओं का उल्लघंन नहीं है? क्या मानवता के आधार पर भी, इन शिक्षकों की अवहेलना अनुचित नहीं ह? ऐसे शिक्षकों की संख्या 200 से भी कम होगी। इन्हें नियमित करने के बारे में नेपाल के तीन प्रधानमंत्रियों के.पी. भट्टराइ, गिरिजा प्रसाद कोइराला और शेरबहादुर देउबा ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखित आश्वासन दिया परन्तु आज तक कुछ नहीं किया गया और भविष्य में भी कुछ नहीं किया जायेगा क्योंकि इसके लिए नेपाल की शिक्षा नियमावली में परिवर्तन करना होगा जिसे करा पाना एक टेढ़ी खीर साबित होगा।

सैनिक साजों सामान की खरीद से संबंधित जिस प्रावधान के कारण ध्रुव अधिकारी ने अपने लेख में यहां तक कह दिया कि इस संधि के कारण नेपाल अभी भी 'अध औपनिवेशक' स्थिति में है उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या कोई भी स्वतंत्र और सार्वभौम देश अपने क्षेत्र से किसी दूसरे देश के लिए सैनिक सामान कभी जाने देगा? अगर यह संधि न भी हो तब भी नेपाल अपने

पड़ोसी देशों की सहमति के बिना कहीं से सैनिक सामान आयात नहीं कर पायेगा। वैसे खबर है कि माओवादियों से लड़ने के लिये अमरिका न नेपाल को कुछ हथियार दिये है।

वास्तविकता यह है कि नेपाल और भारत दोनों ही स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र है। परन्तु दोनों देशो का संबंध इससे कहीं अधिक है। फिलहाल तो कूटनीति और राजनीति के संकुचित दायरें में दोनों देशों के संबंधों को सीमित नहीं किया जा सकता ।

सन पचास की संधि को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने के वास्ते दोनों देशों में समितियों का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में इन समितियों को गतिविधियां धीमी हो सकती है। किन्तु वह समय भी आ सकता है जब इस निष्क्रिय संधि को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। इस संधि को पूरी तरह समाप्त कर देना ही भारतीयों के हित में है। मैत्री और शांन्ति की यह संधि कहीं शंका और हिंसा की दुरभि–संधि न बन जाये यह दोनों देशों के कर्णधारों को सोचना चाहिए।

1950 की संधि के अलावा एक और पुरानी संधि है– सुगौली की संधि जो तत्कालीन भरत की ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच हुई थी। माओवादी इस संधि को भी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। वैसे नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा भी इस संधि के बारे में विचाराधीन है।

मधेशी आंदोलन

'मधेशी ख' अर्थात मधेशी है । नेपाल की नेवारी भाषा की एक मजाकिया कहावत है– 'मनु म ख, मधेशी ख'। अच्छा है लोग इसे भूलते जा रहे है। परन्तु नेपाली समाज के विकास के इतिहास में इस कहावत का महत्व कम नहीं है । दो करोड़ तीस लाख से अधिक आबादी वाले नेपाल में लगभग चालीस लाख ऐसे नेपाली नागरिक है जिनके पास नागरिकता प्रमाण –पत्र नहीं है । 14 साल पहले गठित धनपति उपाध्याय आयोग ने नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकों की संख्या लगभग चौतीस लाख बताई थी जो अब बढ़ कर चालीस लाख हो गई होगी, ऐसा अनुमान है। इनमें से अधिकांश तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग है जिन्हें नेपाल में मधशी कहा जाता है। वैसे नागरिकता प्रमाण–पत्र विहीन नागरिाकों में पहाड़ों पर रहने वाली कुछ जनजातियां जैसे मगर, गुरूंग आदि भी शामिल है। नेपाल में नागरिकता प्रमाण पत्र के बिना न तो आप बैंक में खाता खोल सकते है। न स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते है। जमीन जायदाद तो खरीदने और बेचने का सवाल ही नहीं उठता ।

नेपाल की नागरिकता समस्या नेपाल का आन्तरिक मामला है। फिलहाल भारत नेपाल संबंधों पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। परन्तु मैने जितने लोगों से बात की उन सभी ने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उन सभी लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि अगर इस समस्या को हल करने में विलम्ब किया गया तो दोनों देशों के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये कुछ नहीं किया गया। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पहले धनपति उपध्याय आयोग, फिर महंत ठाकुर समिति और बाद में जितेन्द्र नारायण देव समिति का गठन किया गया। सन 2002 में गिरिजा प्रसाद कोइराला की सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पारित कराया। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की राय में वह विधेयक असंवैधानिक बताया गया है। यह विधेयक नेपाल नरेश के पास उनकी स्वीकृति के लिए लंबित है। राजशाही की समाप्ति के बाद इस विधेयक का क्या हुआ कुछ पता नहीं। तराई में रहने वाले मधेशी समुदाय के नेता भी इस विधेयक से संतुष्ट नहीं है। वे इस सरकार द्वारा मधेशियों के प्रति किये जा रहे कथित अन्याय का एक अंग मानते है। इधर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक फैसले के कारण तीस हजार और लोगों की नागरिकता समाप्त हो गयी है जो अब तक विधिवत नागरिक थे। इनमें अधिकांश मधेशी समुदाय के लोग है। न्यायालय के एक अन्य फैसले के अनुसार केवल माता की नागरिकता के आधार पर किसी को नेपाली
नागरिकता नहीं दी जा सकती। विशेषज्ञों के मुताबिक कोईराला सरकार द्वारा पारित विधेयक नेपाल के संविधान के खिलाफ है, नेपाल सदभावना पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह का कहना था कि ''इसके पहले भी ऐसे प्रयास किये गये और सर्वोच्च अदालत ने उसे विफल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में संविधान संशोधन ही एक मात्र रास्ता है और यह तभी संभव है जब सत्ता

और विपक्ष के सदस्य मिलकर समुचित संविधान संशोधन लाये जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है।''

नेपाल में पिछले लगभग चालीस वर्षो से रह रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री रामाशीष के अनुसार–''कुल मिलाकर मामला साफ है कि.

- सरकार भारतीय सीमा से लगे मधेशियों को नागरिकता प्रमाण–पत्र देने के रास्ते में अड़चन लगाये रखना चाहती है। उन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर आज नहीं तो कल संसद में मधेशियों की बहुतायत होगी।
- मजे की बात तो यह है कि अभी तक जितने भी चुनाव हुये सभी नागरिकों ने वोट डालें है। भले ही उनके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं रहे हो।
- विडम्बना यह है कि इस समय जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसमें वैसे वयस्क नागरिकों को मतदाता परिचय पत्र देने में आनाकानी बरती जा रही है। जिनके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है।
- ऐसे प्रावधान लाये जा रहे है कि अंगीकृत नागरिक, नागरिकता प्रमाण पत्र पाने के दस वर्षो तक किसी भी संविधानिक अग का सदस्य नहीं हो सकता और न ही वे चुनाव ही लड़ सकता है।

संसद या सरकार चाहे जितना प्रयास कर लें लेकिन देश भर के 75 जिलों में से 72 जिलों के सी.डी.आ. पहाड़ी जाति के ही है और वे अंतिम दम तक मधेशियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने में कोताही बरतेंगें। ''

नेपाल में तराईवासियों अर्थात मधेशियों के साथ भेदभाव के आरोप एकदम निराधार नहीं है। काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 'नेपाल एंड एशिया रिसर्च सेन्टर' ने तराई के नौ जिलों झापा, मोरंग, सुनसरी, सिरहा, सपतरी, महोतरी, धनुषा, रातहट और 12 जिलों में रहने वालें लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर दो वर्षो तक अनुसंधान करके एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'तराई के अधिकांश लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत हो रही है और इसका मुख्य कारण है राजनीतिक भष्टाचार। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मधेशियों पर तरह तरह के अत्याचार किये जाते है। काठमांडू से प्रकाशित 'जनादेश' के दिनांक 02 सितम्बर, 2001 के अंक में माओवादी नेता मातृका यादव का एक लख छपा जिसमें कहा गया है कि ''एक ओर अधिकांश गरीब तथा दलित समुदाय के मधेशियों को नागरिकता से वंचित कराया गया है तो नागरिकता प्राप्त मधेशियों को असली नेपाली के रूप में नहीं बल्कि दो नम्बर के नागरिक अर्थात नकली नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। ...भारत के साथ असमान संधि करने वाल राष्ट्रघाती तत्व नेपाली राष्ट्रीयता के प्रति गौरव करने वाले मधेशियों को भारतीय कहकर दुर्व्यवहार करते है। उनके साथ गाली गलौज करते है। ''

मधेशियों की समस्या नेपाल की आन्तरिक समस्या है। परन्तु नेपाल में ऐसे हजारों व्यक्ति है जिनके परिवारों के कुछ लोग नेपाली नागरिक है तो कुछ भारतीय नागरिक। दोनों साथ–साथ रहते है। मधेशियों का खान–पान, रहन सहन, उनकी संस्कृति बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जिलों में

रहने वालों से मिलती जुलती है। उनमें परस्पर वैवाहिक संबंध आदि भी है। अगर लम्बे समय तक मधेशियों को नागरिकता की समस्या से जूझना पड़ता रहा तो इसका प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसीलिए यह नेपाल और भारत के हित में है कि इस समस्या का समाधान अविलंब निकाला जाय।

नेपाल से बाहर रहने वाले पत्रकारों और अन्य विद्वानों के मन में यह धारणा घर कर गई है कि नेपाल की तराई में रहने वाले लोग भारतीय मूल के है। जबकि वास्तविकता यह नहीं है। नेपाल के तराईवासी मूलतः नेपाली है। हां! इतना अवश्य है कि वहॉ के निवासियों के जिन्हें मधेशी कहा जाता है, रहन–सहन, खान–पान, उनकी संस्कृति बिहार आर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के समान है। यही समानता दोनों देशों के बीच मैत्री की एक मजबूत कड़ी है, जिसे कमजोर बनाने की बजाय और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है।

नेपाल में राजशाही की समाप्ति के बाद मधेशी समुदाय के लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सशस्त्र आंदोलन छेड़ दिया। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अंततः फरवरी 2007 को एक राष्ट्रीय प्रसारण में मधेशियों की मांगों को स्वीकार करने आश्वासन दे दिया। उन्होंने कहा कि अब नेपाल के अंतरिम संविधान में संशोधन किया जायेगा, ताकि मधेशियों को उनके जायज हक दिये जा सके। उनकी घोषणा के मुताबिक नेपाल अब एक संघीय गणराज्य होगा। अर्थात केन्द्रीय सत्ता के अलावा स्वायतशासी राज्यों का गठन होगा जहां प्रांतीय सरकारें होगीं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संसदीय क्षत्रों का फिर से निर्धारण किया जायेगा। ताकि मधेशियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। कोइराला ने यह भी कहा कि अंतरिम संविधान में संशोधन करके संसद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।

नेपाल के मधेशी समुदाय के बारे में भारत में कई भ्रांतियां हैं। नेपाल के मधेशियों को भारत में अक्सर भारतीय मूल का नेपाली कहते हैं जो सर्वथा गलत है। वास्तव में नेपाल के मधेशी शत–प्रतिशत नेपाली हैं। उन्हें भारतीय मूल का कहना एक तरह से उनका अपमान करना है। मधेशी समुदाय के लोग पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं। नेपाल में उन्हें हमेशा उपेक्षा और यहां तक की घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। 1990 में नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के बाद भी ऐसा प्रयास किया कि मधेशी समुदाय के लोग नेपाल की सत्ता में हावी न हो सकें। वास्तविकता यह है कि दो करोड़ 40 लाख की आबादी वाले नेपाल में मधेशियों की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

नेपाल के मधेशियों ने प्रजातंत्र की स्थापना के लिये चलाये गये आंदोलन के पूरे दौर में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे गणेश मानसिंह के नेतृत्व में प्रजातंत्र की स्थापना के लिये चलाया गया आंदोलन हो या प्रचण्ड के नेतृत्व में आयेजित सशस्त्र संघर्ष हो, मधेशियों का इसमें पूरा योगदान रहा। परन्तु अब जब प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है तो मधेशियों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनका उचित हक नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ सच्चाई भी है। प्रशासन और सेना में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। नेपाल के 75 जिलों में से किसी भी जिले

में मधेशी समुदाय का जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक नहीं है। अंतरिम संविधान जिसे अभी लागू किया गया है इसमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मधेशी समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था नेपाल के अंतरिम संविधान में नहीं है इसलिये मधेशियों का आंदोलित होना सर्वथा उचित है। मधेशी जनाधिकार फोरम के नेता के रूप में उभरे उपेन्द्र यादव को अब दबाया नहीं जा सकता। उपेन्द्र यादव भारत के लालू प्रसाद याद और मुलायम सिंह यादव की तरह शक्ति के केन्द्र बन गये हैं।

प्रारम्भ में मधेशियों का आंदोलन सरकार के खिलाफ था। सरकार ने उनकी मांगे मान ली तो आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिये था। माओवादी आंदोलन के अंग रहे मधेशी नेताओं को जब यह लगा कि नेपाल के अंतरिम संविधान में मधोशियों की अनदेखी की गयी है तो उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया। वर्तमान में नेपाल के पूरे तराई क्षत्र में माओवादी और मधेशी आमने–सामने हैं। अगर संघर्ष इसी प्रकार जारी रहा तो नेपाल के हालात और खराब हो सकते है।

माओवादियों और मधेशियों के बीच बढ़ रहे संघर्ष के पीछे नेपाल की सामाजिक स्थाति है। नेपाली समाज में मुख्य रूप से तीन प्रकार के लाग है। एक वे जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है और दूसरे तराई में रहने वाले मधेशी। पहाड़ी समुदाय में जनजातीय समुदाय भी है जिनकी अपनी अलग संस्कृति है और वे अपनी पहचान बनाये रखने के लिये बराबर संघर्ष भी करते रहे हैं। पूर्वी नेपाल में कुछ जनजातियों का संगठन कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन वर्षो से अपने लिये एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है इन्हें विदेशी ताकतों से भी मदद मिलती है। मधेशी समुदाय में ज्यादातर लोग अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के हैं। इनकी संख्या नेपाल की आधी संख्या से अधिक है। परन्तु मुश्किल से नेपाल की दस प्रतिशत सम्पत्ति पर इनका कब्जा है। मधेशियों को पहाड़ी लोग हिकारत की नजर से देखते हैं। इसलिये उन्हे सदियों से दबाकर रखा गया। माओवादी आंदोलन क्योंकि मूलतः जनवादी आंदोलन है और राजशाही के खिलाफ है अतः यह उम्मीद की जा रही थी कि माओवादियों के प्रभाव वाली सरकार में मधेशियों को सम्मानजनक स्थान मिलेगा। परन्तु लगता है कि जनवादी आंदोलन की सफलता के बाद माओवादी नेता मधेशी लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भूल गये हैं।

कुछ लोगों का ख्याल है कि मधेशी आंदालन के पीछे राजा–समर्थक ताकतें काम कर रही हैं। परन्तु इसमें सच्चाई नहीं लगती है। राजशाही के समय में भी मधेशियों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता था। इसी वजह से उन्होंने राजशाही को समाप्त करने के आंदोलन में माओवादियों का साथ दिया था। इसलिये यह कहना कि मधेशियों को राजा समर्थक ताकतों का समर्थन प्राप्त है, सही नहीं होगा।

नेपाल सरकार ने भारतीय सीमा पर सुरक्षा चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। वैसे तो इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि ये पुलिस चौकियां नेपाल में अपराधियों की घुसपैठ रोकने और तस्करी पर नियत्रंण रखने के लिये बनायी जा रही है परन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य तराई क्षेत्र में बढ़ रहे

मधेशी आंदोलन को काबू में लाना है। जो भी हो मधेशियों और माओवादियों के बीच शुरू हुआ संघर्ष नेपाल को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकता है।

खुली सीमा
संकट या सहूलियत

भारत और नेपाल के बीच लगभग अठारह सौ किलोमीटर लंबी सीमा है जो बिल्कुल खुली है। कहीं कोई बाड़ या अवरोध नहीं लगाया गया है। सीमा को दर्शाने के लिए थोड़ी –थोड़ी दूर पर सीमेन्ट और कंक्रोट से बने खंभे गाड़ दिये गये है, जिनके दोनों तरफ की कुछ दूर की जमीन को 'नो मैन्स लैंड' या 'दस गजा' कहा जाता है। दस गजा भूमि के उस पार या इस पार जाने में दोनों देशों के नागरिकों के लिये कोई रोक–टोक नहीं है। यहां तक कि दोनों देशों के नम्बर प्लेट वाली गाड़ियॉ भी सीमा के पास स्थित शहरों और बाजारों में आती जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत नेपाल सीमा से होकर प्रतिदिन औसतन बीस लाख लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आते जाते है ये वे लोग है जो रोजमर्रा के सामानों की खरीद फरोख्त तथा अन्य कार्यो से आते जाते है।

भारत और नेपाल के बीच कोई गंभीर सीमा विवाद भी नहीं है। हां! कालापानी का मुद्दा अवश्य नेपाल में उठाया जाता है। यह स्थान तिब्बत से लगी नेपाल की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। नेपाल का दावा है कि कालापानी नेपाल का है और उसे मिलना चाहिए। सीमा स संबंधित कुछ अन्य छोटे–मोटे विवाद भी है जो एक दूसरे के क्षेत्रों में प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो जाते है दोनों देशों के संयुक्त समिति द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद उम्मीद है कि इन विवादों को भी सुलझा लिया जायेगा।

दोनों देशों के बीच सीमा का हाल यह है कि कई स्थानों पर लोगों ने दस गजा में भी मकान बना लिए है। यहा तक कि एक ही आदमी का आधा मकान नपाल में है तो आधा भारत में। जोगबनी में तो पता ही नहीं लगता है कि दस गजा कहां है? यही हाल और कई स्थानों पर भी है। दोनों देशों के नागरिकों को एक–दूसरे के यहां आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीसा की जरूरत भी नहीं है। अलबत्ता 1999 के दिसम्बर में काठमांडू एयर पोर्ट से भारतीय विमान के अपहरण के बाद दोनों देशों के बीच हुये समझौते के कारण विमान से यात्रा करने वाले दोनों देशों के नागरिकों के लिए अपना पास पोर्ट या मतदाता परिचय पत्र या नागरिकता प्रमाण–पत्र या राजदूतावास का पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क मार्ग से आने जाने वालों के लिए अब भी ऐसी कोई बंदिश नहीं है । नेपाल के एक राजनेता ने कहा कि भारतीय नागरिकों और पाकिस्तानी नागरिाकों में भेद कर पाना आसान नहीं । देखने में दोनों एक जैसे लगते है। इसका लाभ उठाकर कुछ अवांछनीय तत्व भी आ जाते है। परन्तु उनका पता लगाना इतना आसान है क्या?

भारत नेपाल के बीच खुली सीमा का लाभ सबसे अधिक तस्कर और अपराधी प्रवत्ति के लोग उठाते है। भारतीय व्यापारी और मीडिया के लोग अक्सर यह शिकायत करते है कि 'चीनी समान' तस्करी के जरिए नेपाल होकर भारत

भेजा जा रहा है इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है।

15 दिसम्बर 2000 को 'काठमांडू पोस्ट' में प्रकाशित एक खबर में एक आश्चर्यजनक तथ्य का उद्घाटन किया है। सुदीप श्रेष्ठ और गोपाल देव कोटा ने वीरगंज से एक 'फील्ड–स्टडी' का हवाला देते हुये लिखा है कि नेपाल और भारत के बीच व्यापार का लगभग एक तिहाई अनधिकृत तरीके से हो रहा है। 'फेडरेशन ऑफ नेपाली चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज' के उपाध्यक्ष रवी भक्त श्रेष्ठ के हवाले से उन्होंने लिखा कि लगभग 10 मिलियन रूपये मूल्य का सामान प्रतिवर्ष अनधिकृत तौर पर भारत से नेपाल आ रहा है। परिणामस्वरूप नेपाल की कई कपड़ा मिलें बंद हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कार्रवाई में नेपाल के भ्रष्ट अधिकारियों का भी हाथ है जो वीरगंज से लेकर काठमांडू के बीच 10 हजार से लेकर 30 हजार रूपये प्रति ट्रक घूस लेते है। नेपाल ने तस्करी की समस्या से निपटने के लिए भारत तथा चीन से लगी अपनी सीमा पर प्रमुख स्थानों पर शाही नेपाली सेना तैनात कर दिया है। इसका उददेश्य न केवल अवैध व्यापार रोकना है अपितु हथियारों और नशीले पदार्थो की तस्करी को भी रोकना है। दिनांक 18 मार्च, 2002 को गोरखा पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार केवल तीन सप्ताह के दौरान नेपाली पुलिस ने तिब्बत से लगी सीमा पर तातोपानी नाका पर चीन से नेपाल अवैध रूप से लाया जा रहा है अस्सी लाख रूपये का सामान जब्त किया । एक सूचना के अनुसार भारत–नेपाल सीमा पर अवैध व्यापार के कारण नेपाल को औसतन एक अरब रूपये के राजस्व की हानि होती है।

पूरी भारत–नेपाल सीमा पर सेना के जवान और अधिकारी, नेपाली कस्टम विभाग के कर्मचारियों की मदद कर रहे है। उधर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ''गत पांच वर्षो में भारत–नेपाल सीमा से होने वाली तस्करी का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। पहले तस्करों के कई गिरोह थे। उनमें ज्यादा भारतीय थे जो नेपाली नागरिकों की सहायता से तस्करी करते थे। उनका उद्देश्य किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाना था। परन्तु अब नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया ऐजेन्सी आई.एस.आई. के सक्रिय होने से पहले काम कर रहे तस्करों के दिन लद गये है। अब आइ.एस.आइ. सीमा के जरिए नशीले पर्दाथों और हथियारों की तस्करी करके आतंकवादियों की मदद कर रही है। नेपाल सरकार ने अपने यहां पांच सौ रूपये के भारतीय नोटो का प्रचलन बंद कर दिया है क्योंकि आई.एस.आइ. ने काफी संख्या में पांच सौ रूपये के जाली भारतोय नोट नेपाल में भेज रखा है। नेपाल से यह नोट भारत भेजे जाते है। नेपाल में जाली भारतीय नोटों का बरामद होना अब आम बात हो गयी है। जनवरी 2002 में सार्क सम्मेलन के अवसर पर काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास का एक अधिकारी जाली भारतीय नोटो और जाली डालरों के साथ पकड़ा गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया।

भारत–नेपाल, 'व्यापार–संधि, का नवीनीकरण हो गया है। परन्तु इसके पहले जो खीचतान दोना देशों के बीच हुई, उससे द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ा खटास जरूर आ गया था। इस संधि के अन्तर्गत भारत ने नेपाल को कुछ सहूलियतें दे रखीं है जैसे तीसरे देशों का माल नेपाली व्यापारी मगांकर उससे

अपने यहां समान तैयार करके भारत भेज सकते है और उस समान पर उन्हे कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसका उद्देश्य है कि इससे नेपाल में औद्योगीकरण को बढावा मिले और साथ ही नेपाली नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया हो । परन्तु पिछले कुछ वर्षो में देखा गया कि नेपाल के कुछ व्यापारियों द्वारा तीसरें देशों का माल मंगाकर उससे बिना कोई सामान बनाये केवल उसी सामान को फिर से पैक करके नेपाली उत्पाद के रूप मं भारत भेजा जा रहा था। इससे भारतीय व्यापारियों की पेरशानी बढ़ गयी थी । साथ ही नेपाल में औद्योगीकरण को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा था। न ही रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे थे। विशेषकर नेपाल के वनस्पति घी के मामले में यह हेराफेरी जोरों पर थी । भारत चाहता था कि इस पवत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसका बड़ा विरोध हुआ। बरहाल अब कुछ नई व्यवस्थाआं के साथ संधि फिर से ज्यों की त्यों लागू हो गयी है। साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वनस्पति घी के मामले में हो रही हेरा फेरी पर रोक लग सकें। किन्तु नेपाल अपने इस प्रयास में सफल रहा कि भारत–नेपाल, व्यापार –संधि, का नवीनीकरण ज्यों का त्यों हो जायें। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच व्यापार में और वृद्धि होगी तथा व्यापार संतुलन बनाने में मदद मिलेगी जो अभी भारत के पक्ष में अधिक है।

एड्स की बीमारी आजकल महामारी के रूप में फैल रही है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। विशेषज्ञों का ख्याल है कि दक्षिण एशिया के लोगों कि जीवन–शैली के कारण आने वाल वर्षो में इन देशों में एड्स से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी बढ़ सकती है। खुली सीमा होने के कारण भारत और नेपाल के लोगों के बीच सम्पर्क काफी घनिष्ठ है। अतः यह दोनों देशों का दायित्व है कि वे ऐसे उपाय करें कि दोनों देशों के लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकें।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइ ने दिनांक 11 जनवरी, 2002 को नई दिल्ली में अपने भाषण में कहा कि एड्स और एच.आई.वी. की महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। ''यूनीसेफ'' (न्दपजमक छंजपवदे प्दजमतदंजपवदंस बेपसकतमदश म्उमतहमदबल थ्नदक) की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग बारह हजार लड़के और लड़कियों को फुसलाकर प्रतिवर्ष भारत के वेश्यालयों मं बेचा जाता है जो अंत में एड्स का शिकार होकर नेपाल लौटते है या वहीं मर–खप जाते है। दिनांक 19.05.2002 को काठमांडू के राइजिंग नेपाल, नामक अखबार में बताया गया कि प्रतिवर्ष औसतन सात हजार नेपाली लड़कियों को विदेशों में वेश्यावृत्ति के लिये बेचा जाता है। 'काठमांडू को पोस्ट, में दिनांक 30.03.2002 को प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि अनुमानतः एक लाख नेपाली लड़कियां इस समय भारत के वेश्यालयों में काम कर रही है जहां उन्हें जबरदस्ती या धोखा देकर ले जाया गया है। दिनांक 21.03.2002 को 'राइजिंग नेपाल' में विराट नगर से प्रकाशित एक खबर में बताया गया है कि नेपाल में एच.आई.वी/ एड्स से प्रभावित लोगों को संख्या तेजी से बढ़ रही है । एड्स कन्ट्रोल समन्वय समिति' के हवाले से लिखा गया है कि अधिकांश लोग सीमा पर भारत के जोगबनी शहर में जाकर प्रतिदिन नशीली दवायें लेते है और वापस नेपाल आ जाते है। एक अनुमान के अनुसार करीब सात सौ नेपाली युवक प्रतिदिन जोगबनी

जाते है और नशीली दवाये लेते है। एक गर सरकारी संस्था द्वारा किये गये शोध के अनुसार केवल मोरंग जिले मे 70 मे से 27 युवक एच.आई.वी/एड्स से संक्रमित पाये गये है। उधर, वीरगंज की एक संस्था, जनरल वेलफेयर एकेडमी, द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक नेपाल से जिन लड़कियों को फुसलाकर वेश्यालयों में काम करने के लिये भारत ले जाया जाता है उनमें से एक तिहाई को उनके पुरूष मित्र (ब्वायफ्रेन्ड) ले जाते है, जबकि एक तिहाई को उनके पति, पिता या अन्य रिस्तेदार उन्हें वहां बेच देते है। केवल एक तिहाई लड़कियां बिचौलियों के माध्यम से जाती है। नेपाल से इतनी भारी संख्या में लड़कियों के वेश्यावृत्ति में जाने के कारण केवल गरीबी और अशिक्षा नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का बड़ा गिरोह भी काम करता है। जिनके तार अन्तर्राष्ट्रीय माफिया गिरोहा से जुड़े है। दिनांक 27 जनवरी 2002 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मे छपी रोमा नागराजन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वेश्यालयों में नेपाली लड़कियों की संख्या दो लाख से अधिक हो गयी है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के बाद महिलाओं की ट्रैफिकिंग ही सबसे अधिक फायदेमंद धंधा है, अपराधियों के लिए। इस धंधे में संगठित अपराधी गिरोहों ने करोड़ो रूपये लगा रखा है। सूत्रों के अनुसार भारत होकर य्नाइटेड अरब अमीरात (यू.ए.इ.) तथा अन्य यूरोपीय देशों को नेपाली लड़कियों को फुसलाकर ले जाया जाता है। नेपाल में यह आम धारणा है कि भारत महिलाओं की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। परन्तु देह–व्यापार को रोकने के लिए नेपाल की कुछ संस्थाओं खासकर ''मैत्री नेपाल का प्रयास निसंदेह तारीफ के काबिल है।

खुली सीमा के कारण उत्पन्न एक अन्य समस्या भी भारत–नेपाल संबंधों में खटास पैदा करती है। यह समस्या है– नेपाल में पिछले लगभग एक दशक से रह रहे भूटानी शरणार्थियों की समस्या ।

भूटानी शरणार्थियों की समस्या वैसे भारत–नेपाल संबंधों से जुड़ा मुद्दा नहीं है परन्तु इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। नेपाली अधिकारियों के अनुसार लगभग एक लाख भूटानी शरणार्थी पिछले एक दशक से पूर्वी नेपाल में शिविरों में रह रहें है। यह सभी नेपाली मूल के है और नेपाली भाषी है। इस समस्या के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रयास हो रहा है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ताये भी हुई है। भूटान ने इन शरणार्थियों की पहचान करके वास्तविक भूटानी नागरिकों को वापस लेना स्वीकार कर लिया है। शरणार्थियों की पहचान भी शुरू हो गयी है। परन्तु इसकी गति बहुत धीमी है।

नेपाल का मानना है कि अगर भारत चाहे तो यह शरणार्थी वापस भूटान जा सकते है। भारत को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि यह शरणार्थी भारत होकर ही नेपाल आये थे। भूटान के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। भारत का कहना है कि यह द्विपक्षीय मामला है। नेपाल और भूटान को स्वयं इसे सुलझाना चाहिए। वैस पच्चीस हजार से अधिक भूटानी शरणार्थी भारत में भी रह रहे है। एक सरकारी अधिकारी ने मुझे बताया कि नेपाल में वास्तविक शरणार्थियों की संख्या एक लाख नहीं है, क्योंकि उनमें से एक तिहाई से भी ज्यादा लोगों ने नेपाली नागरिकता हासिल कर ली ह और इतने ही लोग भारत चले गये है।

नेपाल में रहने वाले भूटानी शरणार्थियों की संख्या 25–30 हजार से ज्यादा नहीं होगी। जो भी हो यह खोज का विषय है। अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

भूटान से इन शरणार्थियों को नेपाल में आकर शरण लनी पड़ी, क्योंकि वे वहां मांग कर रहे थे कि उन्हें नेपाली भाषा बोलने एवं पढ़ने–लिखने तथा नेपाली संस्कृति के विकास की इजाजत दी जायें। भूटान के अनुसार अगर इस बात की इजाजत दी गयी तो भूटान जैसे छोटे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। जो लोग भूटान में है उन्हें वहां के संविधान और नियमों का पालन करना चाहिए। यह दिलचस्प बात है कि भूटानी शरणार्थियों की समस्या से जूझते रहने के बावजूद अपने यहां नागरिकता की समस्या की अनदेखी कर रहा है।

काठमांडू से प्रकाशित सरकारी अखबार 'तै्प्छळ छम्च|स' में 25 माच, 2002 को दमक (झापा) से रिपोर्ट करते हुये नवीन सिंह खड्का ने लिखा कि भूटानी शरणार्थियों की पहचान जिस गति से हो रही है उस हिसाब से पहचान का काम पूरा करने में ही पांच साल से अधिक समय लग जायेगा। 'पीपुल्स फोरम फार ह्यूमन राइटस इन भूटान' के महासचिव डो.पी. काफले ने काठमांडू में कहा कि शरणार्थियों की स्थिति बहुत दयनीय है।

'चौथा खम्भा अर्थात मीडिया का महत्व पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सच्चाई को उजागर करने, या सच्चाई को कुरूप करके प्रस्तुत करने या उसे छिपाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, नेपाल में प्रजातंत्र की पुनस्थापना के बाद मीडिया का भी विकास काफी तेज गति से हुआ है। नेपाल से इस समय साढ़े तीन सौ से अधिक दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकलते है। टेलीविजन के भी कई निजी चैनल सफलतापूर्वक चल रहे है। सरकारी रडियां और टेलीविजन तो है ही। निजी एफ.एम. चैनलों की संख्या भी एक दर्जन के करीब है। इसके बावजूद वहां भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकायं काफी संख्या में बिकती है। समाचार तथा मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों को देखने के लिए भारतीय टीवी चैनल भी काफी लोकप्रिय है। इसलिए भारतीय मीडिया की छोटी सी भूल पर भी नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया होती है। काठमांडू से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान (दिसम्बर–1999) अपहरण के समय एक भारतीय टीवी चैनल की लापरवाही से जिस प्रकार नेपाल को बदनाम करने वाली खबरों का प्रसारण किया गया, नपाली लोग उसे आज तक नहीं भुला पायें ह। एक राजनीतिक टीकाकार ने बताया कि उस टोवी चैनल के प्रसारण से भारत–नेपाल संबंधों को जितना नुकसान पहुंचा उतना नुकसान आज तक किसी भी अन्य वजह से नहीं हुआ। परन्तु रोचक बात यह है कि जिस संवाददाता ने उस टीवी चैनल पर यह खबर दी वहीं संवाददाता नेपाल में सबसे अधिक पहुंच वाला मीडिया मैन माना जाता है।

नेपाल की मीडिया भारत विरोधी स्वर की कमी नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पाकिस्तान और कुछ अन्य देश इस बात का प्रयास करते रहतें है कि नेपाल मीडिया को भारत विरोधी बना दिया जायें । ताकि उनका काम आसान हो जाये। ह्रितिक रोशन के बारे में निराधार खबरें फैलाने के पीछे आई.एस.आई. का हाथ बताया जाता है, जिसके फलस्वरूप भारत विरोधी घटनाएं हुई और यहां तक

की नेपाल के मधेशी और पहाड़ी समुदाय के बीच खाई पैदा हो गयी। अब नेपाली मीडिया के दिग्गज भी इस बात को समझने लगे है। नेपाल की मीडिया में यदा कदा भारत विरोधी खबरें छपती रहती है। उसका एक कारण यह भी है कि नेपाली जनता का देशाभिमान बहुत तीव और उग्र है उन्हें जब भी कहीं लगता है कि उनके देश की सार्वभौमिकता और स्वतंत्र सत्ता के खिलाफ कोई छोटी सी बात भी है तो वे उबल पड़ते है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है।

'राष्ट्रीय मंच' नेपाली मासिक के एक अंक में इंदर विशाल ने उन कारणों की व्याख्या की है कि जिनसे यदा कदा नेपाल मे भारत विरोधी भावना भड़क उठती है । उनके अनुसार ''नेपाल एक छोटा देश है। नेपालियों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। इस वजह से नेपालियों में भारत के प्रति नकारात्मक सोच पैदा होती है। नेपाल की पंचायती व्यवस्था का आधार ही भारत विरोधी नारे थे। ऐसा लगता है कि नेपाल का राष्ट्रवाद भारत विरोधी भावना पर ही फलता फूलता है यहा तक तो बात समझ में आती है। परन्तु परेशानी वहां खड़ी होती है जब इस स्थिति का लाभ एक तीसरा देश पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान द्वारा नेपालियों की नकारात्मक भावना का उपयोग रचनात्मक कार्यों में न करके षडयंत्रकारी कायो में किया जाता है। भारतीय फिल्म स्टार ह्रितिक रोशन के बारे में पाकिस्तान द्वारा फैलायी गयी अफवाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके कारण नेपाल के मधेशियों और गैर–मधेशियों के बीच दरार पड़ गयी ।''

''उस दौर में जब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं थे नेपाल के कुछ नेताओं को झुकाव चीन की तरफ था। परन्तु वे वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं थे बल्कि वे भारत विरोधी तेवर अपनाकर चीन की तरफदारी करने का प्रयास कर रहे थे।

'' एक दशक पहले तक नेपाल में एक भी पाकिस्तान समर्थक या भारत विरोधी अखबार नहीं था। परन्तु आज दाउद इब्राहिम जैसे पाकिस्तान समर्थक लोग नेपाली मीडिया में पानी की तरह पैसा बहा रहे है। पाकिस्तान ने आज तक नेपाल के प्रति कोई सदभावना नहीं दिखाई है।''

बी0पी0 कोइराला नेपाल की राजनीति के शिखर पुरूष थे। उन्हें नेपाल का महामानव कहा जाता है। उनकी डायरी आजकल ''द नेपाली टाइम्स'' अंग्रेजी पत्रिका में क्रमवार छप रही है। पत्र के अनुसार 30 दिसम्बर 1976 को जब वे काठमांडू के सुन्दरी जेल में नजरबंद थे, पहले ही दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा ''मै रिलैक्सड महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के झूठे वायदों और दाहरे व्यवहार से मुक्त हो गया हूं। वहां (भारत में) आजकल भ्रम का वातावरण है। ''

बी.पो. के उद्‌गार इस बात के प्रतीक है कि इस समय तक भारत नेपाल संबंधों पर अविश्वास की नींव पड़ चुकी थीं। जो भी हो बी.पी. की डायरो के इस समय प्रकाशन को क्या अर्थ है? ये इतिहास की बातें है। सच्चाई यह है कि भारत और नेपाल के मीडिया कर्मियों के बीच आज पहले के मुकाबलें सम्पर्क ज्यादा है। नेपाल में मीडिया का विकास भी तेजी से हुआ है। परन्तु ऐसा लगता है कि नेपाली मीडिया को भारत के बार में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके लिए गैर सरकारी तौर पर दोनों देशों के बीच और अधिक अनौपचारिक

संबंध बढ़ाने की जरूरत है। यही संबंध भविष्य में संयुक्त रूप से दोनों देशों की जनता की उन्नति और विकास में सहायक होगा, ऐसा लोगों का मानना है ।

अध्याय–7
दो देश एक लोग

भारत की सर्वोच्च सरकारी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों की भर्ती के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा का फार्म मेरे सामने है। इस परीक्षा में कौन लोग बैठ सकते है? इसके जवाब में जो लिखा गया है वह काफी दिलचस्प है। परीक्षार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा नेपाल की प्रजा भी इस परीक्षा में बैठ सकती है। शायद एक देश की सरकारी सेवा में दूसरे देश के नागरिकों की नियुक्ति को अवसर प्रदान करने को यह अनूठा उदाहरण है। पता नहीं नेपाल के पढ–लिखे लोगों को इस बात की जानकारी है या नहीं वैसे किसी भी नेपाली नागरिक न मुझसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया।

हां! भारत तथा बिट्रेन की सेवाओं में काम करने वाले गोरखा सैनिकों का जिक अक्सर होता रहता है। नेपाल मं कुछ लोग गोरखा सैनिका की भारतीय सेना में भर्ती के सख्त खिलाफ है। काठमांडू के एक बुद्धिजीवी मदन रेग्मी ने काठमांडू पोस्ट (13.12.2000) में एक लेख लिखकर कहा कि भारत तथा बिट्रेन की सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती तुरन्त रोक देनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ है । मदन रेग्मी ने तो यहां तक कह दिया कि ''राणा प्रधान मंत्री जंग बहादुर ने 1826 में गोरखा सैनिकों की भर्ती पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये थे। फिर भी ब्रिटिश सेना में इनकी अवैध भर्ती होती रही।'' लेख के अनुसार महाराज महेन्द्र ने दिनांक 17.04.1958 को पुनः गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए अनुमति दे दी। जो अभी तक जारी है।

लेखक के विचार चाहे जो हो पर जमीनी हालात यह है कि आज भो भारी संख्या में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अथक प्रयास करते है। पिछले दिनों धरान में भारतीय सेना में भर्ती के लिए एक शिविर लगाया गया था। उसमें इतनी भीड़ हो गयी कि शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

वर्तमान में लगभग पचास हजार नेपाली गोरखा भारतीय सेना में कार्य करते है। जिन्हें लगभग छः सौ करोड़ नेपाली रूपये के बराबर पतिमाह वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त एक लाख से अधिक गोरखा सैनिक सेवा निवृत्ति होकर नेपाल में रहते है जिन्हें लगभग पांच सौ करोड़ रूपयों के बराबर वार्षिक पेंशन मिलता है। भारतीय सेना में काम कर रहे नेपाली गोरखा सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। दोनों की सेवा शर्ते समान है। भारतीय सेना में प्रतिवर्ष डेढ़ हजार से लेकर दो हजार नये नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है जिसके लिए आम तौर पर बीस–पच्चीस हजार नेपाली युवक आवेदन करते है।

पहले नेपाली गोरखा सैनिकों को अपनी पेंशन लेने के लिए सीमावर्ती भारतीय शहरों जैसे गोरखपुर, बहराईच इत्यादि जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें दस पन्द्रह दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। परन्तु अब इनकी सुविधा के लिए धरान और पोखरा में पेंशन भुगतान केन्द्र स्थापित कर दिये गये है, जहां

न केवल भूतपूर्व गोरखा सैनिकों, बल्कि भारत में गैर सैनिक सेवाओं में काम करने वाले नेपाली नागरिकों को भी पेंशन दी जाती है। पेंशन देने के अलावा इन केन्द्रों द्वारा पेंशन भोगियों तथा उनके परिवार के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय आदि भी चलाये जा रहे है। पोखरा में मैने स्वयं देखा जब एक सौ पांच वर्षीया श्रीमती कैसू पुन अपने पुत्र की पीठ पर सवार होकर पेंशन लेने आयी थी। उसके दोनों पुत्र भी पेंशन भोगी है। श्रीमती कैसू पुन के पति धनराज पुन वर्ष 1921 में तत्कालीन ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना से रिटायर हुये थें। उन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लिया था। पोखरा के पास ही भूतपूर्व सैनिकों की कई बस्तियां है जहां वे शान्तिपूर्वक जीवन यापन कर रहे है। इसमें कोई शक नही कि नेपाल के गोरखा सैनिक भारत–नेपाली मैत्री की एक मजबूत कड़ी है।

इसके अलावा लगभग अस्सो लाख अन्य नेपाली नागरिक भारत में विभिन्न प्रकार के कार्य करते है। निजी क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के दरवाजे भी नेपाली नागरिकों के लिए खुले हुये है।

एक अध्ययन के मुताबिक भारत से नेपाली नागरिकों द्वारा लगभग चालीस अरब नेपाली रूपये की राशि भेजी जाती है जो नेपाल की सकल घरेलू आय का पांच प्रतिशत है। इसी तरह नेपाल आने वाले पयर्टकों में से हवाई जहाज से आने वाले पयर्टकों में लगभग चालीस प्रतिशत और सड़क मार्ग से आने वाले पयर्टकों में अस्सी प्रतिशत भारतीय नागरिक है। नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली के बाद खाड़ी देशों तथा अमरिका और यूरोप में काम करने वाले नेपालियों की संख्या भी काफी बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग दो लाख नेपाली विदेशों में काम कर रहे है। इसके बावजूद आम नेपाली अभी भी काम की तलाश में सबसे पहले भारत ही आता है। इस पर रोक लगाना क्या इतना आसान है, जैसा कि नेपाल के माओवादी तथा कुछ गिने–चुने तथा कथित राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी चाहते है।

अध्याय–7

पशुपति नाथ

भगवान पशुपति नाथ और काठमांडू एक दूसरे के पर्यायवाची है। सनातनो हिन्दू के मन में काठमांडू का ध्यान आते ही उसे भगवान प्शुपतिनाथ की याद बरबस आ जाती है। भारत के सनातनी हिन्दुओं के लिये तो पशुपतिनाथ द्वादश ज्योतिर्लिगों में से एक है। ऐसा विश्वास है कि काठमांडू के पशुपतिनाथ और भारतीय राज्य उत्तराखण्ड के भगवान केदारनाथ धरती के अन्दर ही अन्दर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार पाण्डवों को उनकी उत्तराखंड की यात्रा के दौरान भगवान शंकर ने एक पशु के रूप में दर्शन दिया। पाण्डवों ने उनका पीछा किय। ऐसी मान्यता है कि वह पशु वहीं तिरोहित हो गाय। पाण्डवों ने उसकी पूंछ पकड़ लो, जो केदारपाथ है और उसका अग्र भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ है। अतः श्रद्धालुओं की पशुपतिनाथ की यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाती, जब तक वे दोनों स्थानों का दर्शन नहीं कर लेते। भारत और नपाल के संबंधों की व्याख्या करने वालों के लिये यह एक चुनौती है। जब तक यह विश्वास बना हुआ है तब तक दोना देशों की जनता को कौन अलग कर सकता है। परन्तु यह भी तथ्य है कि वर्ष 2002 की महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत से काठमांडू आने वाले भक्तों की संख्या अन्य वर्षों तुलना में बहुत कम थी। कारण था नेपाल में माओवादी हिंसा से उत्पन्न असुरक्षा को भावना। दिनांक 12 मार्च 2002 को 'स्पेस टाइम' में मारवाड़ी समिति के सचिव विजय कुमार धरीवाल के हवाले से खबर छपी थी कि वर्ष 1999 में महाशिवरात्रि के अवसर पर दस हजार तीर्थयात्री भारत से काठमांडू आय थे, जबकि इस वर्ष उनकी संख्या बहुत कम थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करन द्वारिका से भगवान कृष्ण भी आये थे। उन्होंने ही इस मंदिर का जीणाद्धार कराया, हालांकि इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपल्ब्ध नहीं है।

मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के विग्रह के बारे में एक किंवदन्ती भारत में प्रचलित है कि वह पारस पत्थर का है और नेपाल नरेश वर्ष में एक बार वहां आते हैं और शिवलिंग में लोहा स्पर्श कराकर सोना बनाते है। परन्तु पशुपतिनाथ मंदिर के अर्चक एम. वालेश्वर भट्ट से जब मैंने इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंन कहा कि यह सत्य नहीं है। पशुपतिनाथ का वर्तमान विग्रह परास पत्थर का नहीं है। इसी प्रकार रुद्राक्ष का वह वृक्ष भी हमें नहीं दिखाई दिया, जिसमें केवल एकमुखी रुद्राक्ष फलता है। हां मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का एक पेड़ अवश्य है जो वहां हो रहे अत्यधिक पूदषण के कारण शायद ही फल देता हो। इन सबके बावजूद गजानन्द अग्रवाल जैसे हजारों वयोवृद्ध हैं जो प्रतिदिन पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। गजानन्द जी नेपाल की राज–परिषद के सम्मानित सदस्य हैं बहुत पहले उनक पूर्वज भारत से आकर काठमांडू में बस गये। वे पेशे से व्यापारी हैं परन्तु समाज सेवा और नेपाल की

राजनीति में गहरी रूचि लेते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है मधेशियों की समस्या के बारे में बेलाग भषण देते हैं।

वास्तव में काठमांड् घाटी मंदिरों का शहर है, पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही वाग्मती नदी के उस पार भगवती गुह्येश्वरी देवी का मंदिर है जो एक सिद्धपीठ है। इसक अलावा वहां अन्य कई देवी–देवाताओं की मूर्तियां हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ही उन्मत्त भैरव की विशाल प्रतिमा है जिनके दर्शन के बिना पशुपतिनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं उन्मत्ता भैरव की पूजा से कुमारी लड़कियों के मासिक धर्म सम्बन्धी विकार दूर हो जाते हैं। पशुपतिनााथ मंदिर के सामने नन्दी की विशाल स्वर्णिम प्रतिमा है जो संसार में अद्वितीय है। पशुपतिनाथ मंदिर में निवास कर रहे कई संतों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की विकास के नाम पर मंदिर के आसपास के जंगल को काटा जा रहा है। उनका विश्वास है कि पशुपति नाथ के कारण अनगिनत देवता, ऋषि , महाषि वक्षों के रूप में वहा निवास करते हैं। अतः इन वृक्षों को काटा नहीं जाना चाहिए।

काठमांडू के जनमानस में धार्मिक विश्वास कितनी गहराई से बठा है इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है। जुलाई 2001 के पथम सप्ताह में मकवानपुर जिले सम्पूर्ण श्रेष्ठ और दोलखा जिले के एक भूतपूर्व सौनिक झलक बहादुर थापा ने पशुपतिनाथ मंदिर से भीमसेन मंदिर तक 138 किलोमीटर की दूरी लगभग साढ़े पन्द्रह घंटों में एक बस और एक जीप को उल्टी दिश में (रिवर्स गेयर) चलाकर पूरी की जो कि अपने आपस में एक रिकार्ड है। उन्होंने वहां भोमसेन मंदिर में काठमांडू से लेकर बाग्मती नदी का जल चढ़ाया तथ नेपाल की जनता और राज परिवार के कल्याण के लिये प्रार्थना की। नेपाल में ऐसा धर्मिक विश्वास है कि अगर भीमसेना की मूर्ति की बांयी ओर पसीना आने लगे तो देश के लिय तथा अगर दायी ओर पसीना आये तो राज परिवार के लिये अशुभ संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति में जनवरी 2001 में ही दाहिनी ओर से पसीना आन लगा था और एक जून को नेपाल नरश वीरेन्द्र की हत्या कर दी गयी ''(काठमांड् पोस्ट'–12 ुलाई, 2001 , जितेन्द्र शाह की रिपोर्ट) भगवान भीमसेन काठमांडू के नेवार समुदाय के आराध्य देव हैं। भीमसेन पांचों पाण्डवों में से एक हैं। भीमसेन की मूर्ति देवता के रूप मं दुनिया में शायद केवल यहीं दोलखा जिले में है।

काठमांडू का स्वयंभू नाथ का मंदिर घाटी का दूसर अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि यह मंदिर उस समय भी था जब काठमांडू घटी नगर न होकर एक विशाल जलराशि वाली झील हुआ करती थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बौद्धों की देवी भगवती मंजूश्री एक बार आकाश माग से गुजर रही थीं तो उन्होंने देखा कि काठमांडू घाटी के झील में एक स्थान पर कमल खिला हुआ है और उससे ईश्वरीय प्रकाश फैल रहा है। उन्होंने ही घाटी के दाहिने किनारे पर एक जगह पहाड़ काटकर घटी से जल निकाला और स्वयंभूनाथ तक आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया। कालान्तर में घाटी आबाद होकर काठमांडू शहर में तब्दील हो गयी। लोगों का विश्वास है कि आज भाी पूर्णिमा की आधी रात को भगवती मंजूश्री भगवान स्वयंभूनाथ का दर्शन करने आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान स्वयभूनाथ का मंदिर बहुत प्राचीन है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह हिन्दू बौद्ध तथा अन्य कई सम्प्रदायों के लोगा के लिय समान रूप से पूजा का

केन्द्र है। भगवान स्व्यंभूनाथ की पहाड़ी तथा आस–पास के क्षेत्रों में तिब्बती शरणाथियों की बहुतायत है। वहां पर उन्होंने हजारों गुम्फ बना रखे हैं और इस पकार वह स्थान एक छोटा तिब्बत जैसा लगता है।

बूढ़ा नीलकंठ काठमांडू घाटी का एक अन्य महत्वपूण धार्मिक स्थान है। शिवपुरी हिल्स की तलहटी में स्थित काले पत्थरों से बनी भगवान विष्णु की यह प्रतिमा ऐसा लगता है कि सरोवर के जल में तैर रही है। इसे इस ढंग से स्थापित किया गया है कि इसके ऊपरी हिस्से की छाया तालाब में तैरती हुई नजर आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नेपाल नरेश बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिये अशुभ फल देने वाला माना जाता है। भगवान की यह प्रतिमा सनातनो हिन्दुओं के लिये श्रद्धा का केन्द्र है। परन्तु इसके बारे में भी तरह–तरह की किंवदन्तियां मशहूर है।

रातो मछिन्दर नाथ त्याहार काठमांडू घाटो में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस त्यौहार का प्रारम्भ नरेन्द्र देव ने नौंवी शताब्दी में किया था। ऐसी कथा है कि राजा ने अपने राज्य म व्याप्त सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये असम के कामरूप कामाख्या से लोकेश्वर अर्थात रातो मछिन्दरनाथ को बुलवाया था जो वहां के तत्कालीन राजा शशि महाराजा के पांच सौ पुत्रों में सबसे छोटे और चमत्कारी पुरूष थे। लोकश्वर के काठमांडू आते ही यहां अकाल समाप्त हो गया। उसी समय से मानसून के प्रारम्भ में रातो मछिन्दरनाथ को यात्रा प्रति वर्ष निकाली जाती है। रातो मछिन्दरनाथ की यात्रा का नाथ सम्पदाय से क्या संबंध है इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। परन्तु इतना सत्य है कि नेपाल में नाथ पंथ का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। जहां उनके अनेक मंदिर और देवालय है।

पितृपक्ष के दौरान काठमांडू में गाइजात्रा का आयोजन होता है। इस दिन हिन्दू धर्मावलम्बी अपन बच्चों को गाय की तरह सजाकर यात्रा में शामिल करते है। उनके गले में एक सफेद पट्टा पहना दिया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से उनके मृत पूवजां की आत्मा को शांति मिलती है। 4 अगस्त 2001 को काठमांड् में हनुमान ढोका महल से स्वगीय नरेश वीरेन्द्र तथा राज परिवार के अन्य दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये गाइजात्रा का का आयाजन किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगोंन स्वर्गीय नरेश वीरेन्द्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इतिहासकारों का कहना है कि गाइजात्रा का शुभारम्भ राजा प्रतापम मल्ल ने अपनी शोक संतप्ता रानी के चेहरे पर एक मुस्कान लान के लिये शुरू किया था। रानी के प्रिय पुत्र के अचानक निधन होने के बाद वह सतत शोक मग्न रहती थी। कालांतर में गाइजात्रा के आयोजन के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इस कार्यक्रम के साथ बाद में कई और बाते जुड़ गयी। पर आज भी इसका मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति दिलाना है।

काठमांडू का हनुमान ढोका चौक नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिये आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। इसके कई कारण है। एक तो जीवित कुमारी देवी का दर्शन। यहां कुमारी मंदिर में शाक्य परिवार की एक कन्या की, जिसमें शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण विद्यमान हो, दवी के रूप में पूजा की जाती है। जब वह रजस्वला हो जाती तो उसके स्थान पर दूसरी कन्या को पदस्थापित कर दिया जाता है। यह कन्या देवी का अवतार नहीं, स्वयं देवी मानी जाती है। नेपाल नरेश

भी वर्ष में एक बार यहां आते हैं और कुमारी की पूजा करते हैं तथा उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

जुलाई 2001 में प्रीति शाक्य नामक चार वर्ष की बच्ची का नयी कुमारी जीवित देवी के पद पर अधिष्ठित किया गया। पुरानी कुमारी को उसके घर भेज दिया गया। इस समय काठमांडू में आठ भूतपूर्व कुमारो देवियों हैं जिनमें से अधिकांश अविवाहित हैं क्योकि एक बार जीवित देवी रह चुकी कुमारी के साथ लोक घर बसाना ठीक नहीं समझते है। कुमारी प्रथा काठमांडू कें लिच्छवी काल में शरू की गयी होगी । प्रतिवर्ष दशहरे के समय इन्दर जात्रा के दौरान मनुष्यों द्वारा खीचें जाने वाले रथ में बैठाकर कुमारी की रथ यात्रा निकाली जाती है।

कुमारी मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर तैलजा भगवती का विशाल मंदिर है जो वर्ष भर में केवल एक बार दर्शनाथियों के लिये खुलता है जहां महाराष्ट्र की तुलजापुर की भगवती का भव्य विग्रह है जहां दशहरे के दौरान हजारों पशुओं की बलि आज भी दी जाती है।

वहीं चौक पर जगन्नाथ जी का मंदिर है जिसके मुंडरा पर तांत्रिक साधना से संबधित काठ की मूर्तियां हैं जिन्हें दखकर खजुराहा के मंदिरों की याद बरबस आ जाती है। इस तरह काठमांडू के इन मंदिरों में धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष का सुन्दर समन्वय मिलता है। जो हिन्दू दर्शन का अभीष्ट है।

नेपाल में किरात लोगों की संख्या दस लाख से अधिक है। भारत के सिक्किम तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी किरात लोग रहते हैं। पिछले कछ वर्षो से किरात लोग काठमाडु में नियमित रूप से दिसम्बर तथ मई के महीनों में पड़ने वाले पूर्णमासी के दिन उधौली त्यौहार मनाते है। इस दिन जब इस समुदाय के नर्तक गोलकार ढंग से नाचते गाते हैं और अपना विचित्र संगीत प्रस्तुत करते है तो देखते ही बनता है। नेपाल के पूर्वी जिलों में रहने वाले किरात समुदाय के लोग राइ, लिम्बु, यक्ख और सुनवार जातियेां में बंटे है। इधर इनमे राजनीतिक चेतना भी आ रही है। उन्होंने 2005 म सिक्किम में अपना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करने की घोषणा की है। किरात वैसे तो प्रकृति के पुजारी हैं, वे वृक्षों, लताओं, नदियों, आकाश, पूर्वजों और पत्थरा की पूजा करते हैं। परन्तु वे चाहते हैं कि उन्ह अलग धर्म मानने वालों के रूप में मान्यता मिले। किरातों का उल्लख महाभारत में मिलता है। पाण्डु पुत्र अज्न और किरात वेषधारी भगवान शंकर के युद्ध की कथा प्रसिद्ध है। । इस युद्ध क बाद ही भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशपत अस्त्र पदान किया था। पिछले दिनों नेापल में हुय किरात महाधिवेशन में उन्होंने नरद्वाज, लिगदेन, मुहीगम, आगयिांग, फल्गुनन्द को इक्कीसवीं सदी का महार्षि घोषित किया। (काठमांडू पोस्ट–12.12.2000)।

नेपाल के हिन्दुओं की यह उत्कट इच्छा होती है कि वे कम से एक बार वाराणसी, प्रयाग, रामेश्वरम, द्वारिका आदि तीर्थो की यात्रा करें। नपाल नरेश ज्ञानेन्द्र पिछले वर्ष अपनी भारत यात्रा के दौरान गोहाटी भी गये। उन्होंने भगवती कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कामाख्या मंदिर में प्रधान पुजारी नेपाल के ही होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पशुपतिनाथ के प्रधान पुजारी अनिवार्यतः भारत के होते है। यह कम लोगों को ज्ञात है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर तथा रामेश्वरम के मंदिर म गर्भ गृह में पुजारियों के अलावा जाने का अधिकर केवल नेपाल नरशे को ह अन्य किसी को नहीं ।

काठमांडू से थोड़ी दूर शंखू में शाली नदी के किनारे एक महीने तक चलन वाला स्वस्थानी समारोह नेपालियों की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा है। इसमें नेपाल के अलावा भूटान और भारत के दार्जिलिंग आदि से भी काफी संख्या में लोग जिनमें अधिकांश महिलायें होती है इस समारोह में भाग लेने आते है। जनवरी–फरवरो के महीने में प्रातःकाल शाली नदी में स्नान करना कितनी बड़ी तपस्या है। स्वस्थनी व्रत के दौरान श्रद्धापूर्वक स्वस्थनी का पाठ किया जाता है। जिसकी अधिकांश कथायें भगवान शिव से संबंधित है। कुछ विद्वानों का मत है कि स्वस्थनी परम्परा महाभारत और रामायण से भी अधिक प्राचीन है। इस व्रत के द्वारा श्रद्धालु त्रिदवों की पूजा
करते हैं और अपने परिवार के लिये मंगल कामना करते है। महिलाएं विशेषकर अपने पतियों की कल्याण कामना से यह व्रत करती है।

पशुपतिनाथ की चर्चा हो भगवान मुक्तिनाथ का उल्ल्ख न किया जाय यह कैसे संभव है। भगवान मुक्तिनाथ की यात्रा सुगम नहीं। भारत से वहां कम लोग ही जा पाते है। भारत के थल सनाध्यक्ष जनरल पद्मनाभन अपनी नेपाल यात्रा के दौरान वहां गये थे। यही इस बात का प्रतीक है कि भारत के हिन्दुओं में नेपाल क इस तीर्थ स्थान के प्रति कितनो गहन श्रद्धा है। भगवान मुक्तिनाथ से ही नाराणयी नदी निकलती है। जिसमें भगवान शालिग्राम मिलते है।

लुम्बिनी का उल्लेख किये बिना यह प्रकरण अधूरा ही रहेगा। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थान है। यह दुनिया भर के बौद्ध मतावलम्बियों के लिये अत्यन्त श्रद्धा का केन्द्र है। लुम्बिनी भारत–नेपाल सीमा(नागढ़) के बिल्कुल करीब है। इसके बावजूद भारत से सड़क मार्ग द्वारा वहां नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि सीमा के दोनों तरफ सड़क बंद है। पुराने लोग बताते है। कुछ वर्ष पहले लोग भारत से सड़क मार्ग द्वारा लुम्बिनी जा सकते थे किन्तु नेपाल की ओर सड़क बंद हो जाने के कारण अब यह सम्भव नहीं। महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य तीर्थ स्थान कुशीनगर जहां उनकी महापरिनिर्वाण हुआ था और बोध गया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, भारत में ही है। कुशीनगर लंम्बिनी से बहुत दूर नहीं है। नेपालियों की शिकायत है कि इतिहास की कुछ पुस्तकों मं भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का भारत में बताया गया है। परन्तु यह बोते जमाने की बात है जब बौद्ध धर्म से सम्बन्धित स्थानों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में ही है। यह अलग बात है कि लुम्बिनो में सम्राट अशोक का स्तम्भ आज भी विद्यमान है। इससे यह सिद्ध होता है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।
देशों की सीमायें चाहे जो हों, इससे श्रद्धा और पूजा के स्थलों के महत्व में कमी नहीं हानी चाहिये। आज भारत और नेपाल दो सार्वभौम और स्वतंत्र दश है। परन्तु भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म को विभाजित नहीं किया जा सकता। वह भारत में हो या नेपाल मे, जापान में हो या मंगोलिया में या किसी अन्य देश, वह एक ही है आर एक ही रहेगा। उम्मीद है लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के सदस्य मेरे मित्र नवोन चित्रकार, सचिव जनक लाल श्रष्ठ, धर्मोदय सभा के अयक्ष्य लोकदर्शन तथा सदस्य रत्न मान शाक्य मेरी राय से सहमत होंगे।

पख्यात बौद्ध विद्वान नार्गाजुन ने वषा घाटी की सीमा पर स्थित एक पर्वत शिखर पर तपस्या की थी जिसे आज नागार्जुन हिल्स के नाम से जाना जाता है।

कहते हैं कि नालन्दा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के प्रोफेसर नागार्जुन को अचानक एक दिन लगा कि उन्हें निर्वाण प्राप्त करना चाहिये, बुद्धत्व हासिल करना चाहिये। सचमुच एक दिन सब कुछ छोड़कर वे दक्षिण से उत्तर, पहाडों की ओर चल पड़े बुद्धत्व प्राप्त करने। लगभग तीस वर्षो की अनवरत साधना के बाद उन्हे उनका लक्ष्य मिल गया। इन्हीं नागार्जुन पहाड़ियों पर तपोवन भी है। जहां आज भी दुनिया भर से जिज्ञासु श्रद्धालु भक्त आकर साधना करते हे। स्मरण रहे कि भगवान बुद्ध ने नेपाल से दक्षिण दिशा मे भारत जाकर बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त किया था जबकि नागार्जुन ने उल्टी ज्ञान गंगा गंगा बहाकर भारत से नेपाल आकर निर्वाण प्राप्त किया। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वारा के पास दाहिनी ओर एक छोटी सी सीलन भरी कोठरी में भैरव वाहनों के साथ रहने वाले चुन चुन बाबाा को सब कुछ मालूम है। वे नेपाल और भारत का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते है। चुन चुन बाबा का असली नाम क्या है? वे कहां के रहने वाले हैं? काई नही जानता। वर्षो पहले वे पहली बार काठमांडू आये थे। पशुपतिनाथ के सानिध्य में वाग्मती के किनारे जंगलों में घोर तपस्या की। चुन चुन बाबा अघार सम्प्रदाय के पहुंचे हुये संत है। उस दिन अपनी कोठरी के सामने चबूतरे पर बैठकर गायों को दाना खिल रहे बाबा संयोगवश प्रसन्न मुद्रा में थ। उन्होंने देर तक मुझसे बात की। अपने असली नाम और जन्म स्थान के बारे कुछ नहीं बताया लेकिन जो ज्ञान मुझे उन्होंने दिया वह इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लगता है चुन चुन बाबा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर या वाराणसी जिले के रहन वाले हैं। परन्तु बवपन से ही तपस्या में लग गये। वाराणसी के प्रसिद्ध संत कीनाराम का उल्लेख करने पर उनका चेहरा कमल की तरह खिल गया। फिर बहुत देर तक मुझसे बात की। चुन चुन बाबा नेपाल नरेश वीरेन्द्र और शाही परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या की घटना से क्षुब्ध थ। उन्होंने कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ। बाबा ने संकेत दिया कि चारों तरफ पाप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर कर सका मानव मूल्यों की रक्षा के लिये संघर्ष करा। पशुपतिनाथ सभी का कल्याण करेग। चुन चुन बाबा ने अनेक संतों और महात्माओं को देखा है। न जाने किन–किन स्थानों की यात्रायें की हैं। उनकी आँखों की गहराई में काल–पुरूष की झलक दिखाई देती है जिसे वे अपनी उलझी हुयी लटों से छिपाये रहते है। संतों की वाणी और व्यवहार को समझना इतना आसान है क्या?

नेपाल में भुसुंडी सरोवर हैं जहां कागभुसंड जी ने पक्षिराज गरूण को रामकथा सुनाई थी। वहीं कहीं लोमश ऋशि का आश्रम भी है। नेपाल कह पहाड़ियों में आज भी अनेक स्थानों पर पहुंचे हुये महात्मा और सत साधनारत है।

जनकपुर का उल्लेख किये बिना यह अध्याय अधूरा ही रहेगा। भगवती सीता का पीहर, भगवान राम और उनके भाईयों की सुसराल। आज भी लाखों की संख्या में भक्त भारत से यहां आते हैं और जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करते है। यह स्थानों दोनों देशा के संबंधों का आध्यात्मिक प्रतिष्ठन है। इसे भुला पाना इतना आसान है क्या? और भी अनेक स्थान है नेपाल में, जो दोनों देशें की जनता के लिये समान रूप से श्रद्धा और विश्वास के केन्द्र है।

नेपाल में राजशाही की समाप्ति के साथ ही जीवित देवी कुमारी की परम्परा का भी अंत हो गया। नेपाल के लोग एक कन्या को देवी के रूप में मानकर

उसकी पूजा करते थे। यह अनोखी परम्परा थी। वर्ष में एक बार नेपाल नरेश भी आकर इस देवी का आशीर्वाद लेते थे।
अस्तु।

भारत नेपाल संबंध भविष्य की दशा–दिशा ?

सारांश

इस पुस्तक में कुल सात अध्याय है। प्रथम अध्याय यानी प्रस्तावना में दिसम्बर 1999 में काठमांडू में भारतीय विमान के अपहरण के बाद नेपाल में हुयी प्रमुख घटनाओं की संक्षिप्त विवेचना है। दूसरे अध्याय में नेपाल के कुछ वरिष्ठ लोगों के विचार दिये गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं– सूर्य बहादुर थापा–पूर्व प्रधानमंत्री, कृष्ण प्रसाद भट्टराई पूर्व प्रधानमंत्री, कीर्ति निधि बिष्ट–पूर्व प्रधानमंत्री, बनवारी लाल मित्तल,–उद्योगपति, रवीन्द्र नाथ शर्मा पूर्व मंत्री, वेदानन्द झा–पूर्व राजदूत, हिरण्य लाल श्रेष्ठ, वामपंथी नेता, उद्धव भट्ट राजनयिक लालमणि पोखरेल, राजनीतिज्ञ, अरूण सुवेदी–समाजसेवी।

तीसरे अध्याय में भारत–नेपाल संबंध के संदर्भ में चीन की भूमिका तथा चौथे अध्याय में माओवादी समस्या के बारे में प्रकाश डाला गया है। पांचवे अध्याय में नदियों , भारत–नेपाल संधि 1950 मधेशी आंदोलन और भारत नेपाल के बीच खुली सीमा की चचा की गयी है। छठे अध्याय में गोरखा सैनिका तथ्य उन बातों की चर्चा है जिनसें दोनों देशों की सद्भावना मजबूत होती है। सातवें अध्याय में पशुपति नाथ मंदिर तथा अन्य धार्मिक मुद्दों का उल्लेख है। जिससे दोनों देशों का जनजीवन समान रूप से प्रभावित होता है।